श्री हर्ष मल्होत्राः मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। यह जो process है, जो recovery mechanism है, वास्तव में यह recovery mechanism नहीं है, यह बेसिकली resolution mechanism और market-driven process है। यह जो प्रोसेस है, यह रिकवरी मैकेनिज़्म नहीं है, यह बेसिकली रिजॉल्यूशन मैकेनिज़्म है। यह मार्किट ड्रिवन प्रोसेस है। हमने जो उत्तर सदन को दिया है, वह 1,119 कंपनीज़ का है, जिनका रिजॉल्यूशन हुआ है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

1.00 P.M.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF EDUCATION

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we move on to the Discussion on the Working of the Ministry of Education. Shri Digvijaya Singh to raise the discussion on the Working of the Ministry of Education. माननीय दिग्विजय सिंह जी, अब आपको बोलना है। ...(**व्यवधान**)... No, I have not given floor to you. Shri Digvijaya Singh, please speak. *...(Interruptions)...* आप बोलें, नहीं तो मैं दूसरे सदस्य को बुलाऊंगा। ...(**व्यवधान**)... Shri Digvijaya Singh, please speak; otherwise, I will call the other speaker. *...(Interruptions)...* I will call the next one. *...(Interruptions)...* No, not allowed. आप ऑलरेडी एक बार वैल में आ चुके हैं। ...(**व्यवधान**)... I am warning you. *...(Interruptions)...* Mr. Tiruchi Siva, please go back to your seat. *...(Interruptions)...* Digvijaya Singh*ji*, please continue. *...(Interruptions)...* Digvijaya Singh*ji*, please speak; otherwise,e I will call the next speaker. *...(Interruptions)...*

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): How can I speak in such a situation? *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापतिः आप बोलिए। आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)... Please do not come in the Well. If you come in the Well, I will name you. I request you to go back to your seat. *...(Interruptions)...* माननीय दिग्विजय सिंह, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंहः सर, मैं क्या बोलूंगा? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, I will call the next speaker now. *...(Interruptions)...* यह आप सब लोगों ने तय किया था। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, you have to first bring the House in order. *...(Interruptions)...* How can I speak in such a situation? *...(Interruptions)...* Sir, I want to speak. Please bring the House in order. *...(Interruptions)...* If the House is in order, I am prepared to speak. If the House is not in order, how can I speak? *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापतिः माननीय दिग्विजय जी, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंहः सर, एलओपी कुछ कहना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मैं सुबह एलओपी साहब को बोलने का मौका दे चुका हूं। ...(**व्यवधान**)... माननीय एलओपी सुबह बोल चुके हैं। ...(**व्यवधान**)...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे)ः क्या आप मुझे एक मिनट का समय देंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मैंने ऑलरेडी सुबह आपको बोलने का वक्त दिया था।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सुबह एजुकेशन मिनिस्टर नहीं आए थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, विषय पर चर्चा करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अभी माननीय दिग्विजय जी को विषय पर बोलना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः उनको बोलना है और हमने बोलने की लिए तैयारी भी की है £...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप आपस में बहस करेंगे ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आप बातचीत में बड़े अनुभवी हैं और आपसे लोग सीखेंगे। ...(**व्यवधान**)... यह उचित नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः £ ...(**व्यवधान**)...

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

श्री उपसभापतिः प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः आप सुनिए ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not allowed. Please go back to your seats. ...*(Interruptions)*... प्लीज़, माननीय एलओपी ...(**व्यवधान**)... माननीय लीडर ऑफ दि हाउस। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः देखिए, यह क्या है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मैं इसके बाद आपको मौका देता हूं। ...(**व्यवधान**)... उन्हें बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... लीडर ऑफ दि हाउस, आप बोलिए।

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): सर, बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ दि अपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार हैं, जिन्होंने लंबे समय तक संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में, लोक सभा और राज्य सभा में नेतृत्व भी किया है और सदस्य के रूप में भी काम किया है। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने अभी जिस भाषा का उपयोग किया है और चेयर पर aspersion किया है, यह अति निंदनीय है। ...(**व्यवधान**)... This is condemnable. This has to be condemned by one and all, including the LoP. ...*(Interruptions)*... He should condemn and he should apologize. चेयर के प्रति जिस शब्द का उपयोग किया है, the word and the language used against the Chair are unpardonable. वह अस्वीकार्य है और माफी योग्य नहीं है, ...(**व्यवधान**)... फिर भी एलओपी को माफी माँगनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको expunge करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tiruchi Siva, please take your seat. मैं माननीय एलओपी को allow करूँगा, आप अपनी-अपनी सीटों पर जाएँ। प्लीज़ अपनी सीटों पर जाएँ। ..*(Interruptions)*... Please take your seats. ...*(Interruptions)*.. This is not your seat, Mr. Vaiko. Please go back to your seats. ...*(Interruptions)*.. माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने कभी आपके लिए नहीं बोला, हम सरकार की पॉलिसी को ठुकराएँगे, मैंने यह कहा। आप हमें माफ करना। अगर आपको मेरी बातों से ठेस लगी है, तो मैं आपसे माफी माँगता हूँ, मैं सरकार से माफी नहीं माँगता हूँ। ...(**व्यवधान**)... सुनिए, आप बार-बार क्यों ऐसा करते हैं? सर, मुझे यह कहना है कि अगर आप इस देश के एक भाग के और एक भाग की जनता के स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप यह कहेंगे कि uncultured, uncivilized और वे मानव नहीं है, अगर आप ऐसा कहते हैं, तो आप मंत्री पद से इस्तीफा दें। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats. ...*(Interruptions)...*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, देश को divide करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को divide करके ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats. ...*(Interruptions)..* Nothing is going on record now. ...*(Interruptions)...* No; I am not allowing. ...*(Interruptions)..* Nothing is going on record. ...*(Interruptions)...* माननीय लीडर ऑफ हाउस।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, अच्छा है, ...(**व्यवधान**)... अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता, सम्माननीय खरगे जी ने अपने वक्तव्य के लिए चेयर से माफी माँगी है। एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनका यह gesture सराहनीय है, लेकिन उन्होंने सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है, वह भी निंदनीय है और वह भी कार्यवाही से expunge होनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine it. ...*(Interruptions)..* Thank you. माननीय दिग्विजय सिंह जी, अब आप बोलें।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we stage a walk-out condemning it. ...(**व्यवधान**)...

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber.*)

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। 1947 में हमें आजादी मिली, तब साक्षरता कितनी थी और उच्च कोटि की शिक्षण संस्थाएँ कितनी थीं, यह सर्वविदित है। लेकिन पिछले 78 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे देश में साक्षरता बढ़ी है, शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ी है, वह अपने आप में ऐतिहासिक है।

[**उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी)** ***पीठासीन हुईं।***]

विज्ञान और प्रौद्योगिक तकनीक को महत्व दिया गया और Institutes of Excellence स्थापित हुए। मेरे मत से नीति में access, यानी पहुँच और excellence, यानी गुणवत्ता आवश्यक है। पहुँच geographically भी और financially भी गरीबों के लिए आवश्यक है। Excellence, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अब पिछले 11 वर्षों में क्या हुआ, उस पर हमें चर्चा करनी है। 2020 में New Education Policy आई। अब New Education Policy में जो Policy Statement है, उसको मैं quote करना चाहता हूँ। "It aims at producing

engaged, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged in the Constitution."

माननीया उपसभाध्यक्ष जी, क्या नयी एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन में इस पॉलिसी स्टेटमेंट का पालन हो रहा है, उसको हमें देखना पड़ेगा। कस्तूरीरंगन जी की जो रिपोर्ट थी, उसका ड्राफ्ट कुछ और था और सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी घोषित की, वह कुछ और थी। 1986 में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस समय मैं लोक सभा का सदस्य था। उस पर लोक सभा में चर्चा हुई थी, सदन में चर्चा हुई थी, लेकिन 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई चर्चा सदन में नहीं हुई। अब बात यही है कि क्या गरीबों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्सेस है, पहुंच है और हम लोग एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यह विषय है। बात यही है कि क्या नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा महंगी होगी या नहीं होगी, क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए उच्च कोटि के शिक्षकों का चयन होगा या नहीं होगा, क्या उनका उच्च कोटि का प्रशिक्षण होगा या नहीं होगा, क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए वाइस चांसलर्स व प्रोफेसर्स का चयन ठीक से होगा या नहीं होगा, इन सब बातों को लेकर हमें इस पर चर्चा करनी है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो यूनिवर्सल एक्सेस का उद्देश्य बताया गया है, मैं उससे सहमत हूं। इसीलिए आंगनवाड़ी, यानी कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए यूनिवर्सल एक्सेस को नई शिक्षा पॉलिसी में समावेश किया गया है, मैं उसका पक्षधर हूं, लेकिन Women and Child Development, महिला एवं बाल कल्याण व शिक्षा विभाग का जो convergence होना चाहिए, pre-primary literacy में और बाद में, उस पर आज भी कंफ्यूजन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 5 साल हो गए। मैं कहना चाहता हूं कि बाल वाटिका में बच्चों को मिड डे मील पीएम पोषण से दिलाया जाता है, जो एजुकेशन विभाग में है और आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी योजना से मिलता है, national guideline और funding में असमानता है, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी अलग है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी भी शिक्षा विभाग और महिला व बाल विकास विभाग में जो समन्वय करना चाहिए था, होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, मेरा यह सुझाव है कि इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी इसे एक मिशन मोड में डालें। उसे एक मिशन मोड में इसलिए डालें, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे, तो पाएँगे कि गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर होता जा रहा है तथा इस देश में 52 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं anaemic हैं और 39 प्रतिशत बच्चे आज कुपोषित हैं। इन सब पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

इसी प्रकार से Foundational Literacy और Numeracy की घोषणा की गई। हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपना जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम Reading Fluency को निरंतर रखेंगे, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने उसको छोड़ दिया। अब मैं आता हूं – access, यानी कि पहुंच पर। इसमें नए educational complex बनाने का प्रस्ताव है, यानी कि cluster of educational institutions को एक जगह पर डाला जाएगा। इसके कारण हमारे कई स्कूल्स बंद हो रहे हैं। Right to Education का जो provision है, जो कानून है कि प्राथमिक पाठशाला एक किलोमीटर से ज्यादा

दूर नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि जब हमने उनसे पूछा, तो पता चला कि स्कूल एजुकेशन के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि इस देश में 2014 से लेकर 2024 के बीच में 90,000 शासकीय स्कूल बंद कर दिए गए। अब जो स्कूल बंद किए गए हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI GHANSHYAM TIWARI: Madam, ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: I am not yielding.

SHRI GHANSHYAM TIWARI: Madam, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): कृपया आप बैठिए।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Madam, I am not yielding. Let me finish. माननीय तिवाड़ी जी हमारी समिति के सदस्य हैं, उसमें हम लोगों की इस पर चर्चा हुई है और उसमें उनकी सहमति थी। मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि आज GER बढ़ा है और dropout rate कम हुई है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब GER बढ़ा है और dropout rate कम हुई है, तो छात्रों की संख्या बढ़ी है। जब छात्रों की संख्या बढ़ी है, तो क्या शिक्षकों के पद बढ़े हैं? क्या उसके लिए 'समग्र शिक्षा अभियान' के अंतर्गत बजट बढ़ा है? बजट नहीं बढ़ पाया है।

महोदया, मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर 30,000 स्कूल बंद किए गए। अब आप बताइए कि जो गरीबों के बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, वे कहां जाएंगे? उन्हें निराश होकर निजी स्कूलों में जाना पड़ेगा। अब यह बताया जा रहा है कि 2014 के बाद लगभग 50,000 नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं, जो फीस लेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी जो यह शंका थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी गरीबों के लिए महंगी होगी और इसके साथ ही उच्च शिक्षा भी महंगी होगी वह सही है। मैं इसके कई कारण बताऊंगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल से 18 साल तक का संकेत दिया गया है और ड्रॉफ्ट पॉलिसी में भी ऐसा है, इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में भी बच्चों के लिए जो 6 साल से 14 साल तक का प्रावधान है, उसे बढ़ा कर 3 साल से 18 साल तक किया जाए। मेरा आपसे यह भी प्रार्थना है कि हमें आठवीं कक्षा के ऊपर के बच्चों का थोड़ा-सा सर्वेक्षण करना चाहिए। इसमें हमें काउंसलिंग करने की आवश्यकता है कि जिस बच्चे में जो हुनर है, उसे उसकी तरफ यानी उस स्किल को डेवलप करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए जितने भी मिशन के कार्यक्रम हैं, वे 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हैं, इसलिए उसमें भी परिवर्तन करके, उन्हें 14 साल के बाद ही स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

महोदया, मुझे इस बात पर आपत्ति है और दुख भी है कि जहाँ यह देश सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण है, अनेकता में एकता का एक उदाहरण है, वहाँ एनसीईआरटी की कुछ किताबों में सांप्रदायिकता के संकेत नजर आते हैं। यही नहीं है, बल्कि इतिहास को भी नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो हुआ, उसको सिलेबस से निकाल

दिया गया। इसी प्रकार हिंदू-मुस्लिम एकता के विषय को भी निकाल दिया गया। यहां तक कि एनसीईआरटी की किताबों में संविधान के Preamble की जो बाध्यता थी, उसके लिए मैं हमारे नेताजी को धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने इस बात को यहाँ पर बताया और उसकी वजह से आज मजबूरी में एनसीईआरटी ने यह स्वीकार किया है कि हम एनसीईआरटी की हर किताब में Preamble का समावेश करेंगे। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा।

महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के जो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय चलते हैं, हर जगह इसकी प्रशंसा है, क्योंकि इसमें कम फीस लगती है और उच्चतम शिक्षा दी जाती है। अब उसके अंदर 'पीएम-श्री स्कूल' की नई बात आ गई है। 'पीएम-श्री स्कूल' में उन्हें समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में 7,414 पद खाली हैं और 6,734 पद पर contract टीचर्स appoint हैं। नवोदय विद्यालयों में भी 4,022 पद खाली हैं और उनमें 3,237 पद कांट्रैक्ट पर हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में 70,000 पद खाली हैं। बात वही है। माननीय मंत्री जी, क्या कारण है, क्या नीति है, आप नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी निष्पक्ष तौर पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये उनकी विचारधारा से प्रभावित लोगों की नियुक्ति पिछले दरवाजे से कांट्रैक्ट रूप में करें। यह उनकी नीयत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नीति में प्रशिक्षण पर महत्व दिया गया है, लेकिन क्या कांट्रैक्ट टीचर्स को आप कोई ट्रेनिंग देंगे? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी, तो कितने दिनों की ट्रेनिंग आप देंगे और कब तक वे काम करेंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है।

माननीय, मैंने पीएम श्री स्कूल का उल्लेख किया। पीएम श्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिये गये थे और उन्हें राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसमें 661 में से 621 नवोदय विद्यालयों को शामिल कर लिया और 1,256 में से 869 केंद्रीय विद्यालयों को शामिल कर लिया। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इसका क्या औचित्य था? नवोदय विद्यालयों की मांग बढ़ रही है। अभी आपकी यह नीति थी कि नवोदय विद्यालय हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। पूरे देश में ऐसे भी जिले हैं, जहां एक असेंबली कांस्टीट्यूएंसी है और ऐसे भी जिले हैं जहां 10 असेंबली कांस्टीट्यूएंसीज़ हैं, इसलिए इसकी नीति आप जिले के आधार नहीं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर बनाएं। आज जो हालात हैं, उसमें लगभग 21 लाख की जनसंख्या पर एक नवोदय विद्यालय है। मेरा यह सुझाव है कि उसे 21 लाख से घटाकर 15 लाख की जनसंख्या के आधार पर स्थापित किया जाए और जियोग्रैफिकली देखकर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएं, क्योंकि नवोदय विद्यालयों की मांग है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा हमारे फेडरल कांस्टिट्यूशन का एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, लेकिन जिन प्रांतों ने पीएम श्री के स्कूल चालू करने पर समझौता नहीं किया, उनका समग्र शिक्षा अभियान का पैसा रोक दिया गया, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसमें पश्चिमी बंगाल के 1,000 करोड़ रुपये रोक दिए गए, केरल के 859 करोड़ रुपए रोक दिए गए और तमिलनाडु के 2,152 करोड़ रुपये रोक दिए गए। मंत्री जी, इसका क्या कारण है? राज्यों का संविधान के तहत जो कॉन्करेंट अधिकार है, उसका आप हनन कर रहे हैं, इसलिए आप तत्काल उनके पैसे रिलीज कीजिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, अब मैं हायर एजुकेशन पर आता हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी 5,410 पद खाली हैं। वहां भी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है। अब आप बताइए! ये

जाने-माने तरीके से अपने लोगों को बैक डोर से एंट्री कराने की कुटिल योजना है, प्रयास है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या इससे हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की नियुक्तियों का हनन नहीं हो रहा है? क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिए। आप उनकी नियुक्तियां तत्काल करें, ताकि हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, उनको उसमें मौका मिले। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आईआईटी फैकल्टी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जितना अधिकार है, उसका केवल एक प्रतिशत आदिवासी ही फैकल्टी में है। उसमें केवल 5% अनुसूचित जाति का है और केवल 10% ओबीसी का है, यानी हमारे कानून का भी उल्लंघन किया जा रहा है और जो संवैधानिक प्रावधान है, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है।

अब मैं वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। दिसंबर, 2024 तक 10 पूर्णकालिक वाइस चांसलर के पद रिक्त थे। माननीय मंत्री जी, उन्हें आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्त करना है, फिर ये 10 पद रिक्त क्यों रखे गए हैं? डायरेक्टर, एडवांस्ड स्टडीज़ का पद अगस्त, 2021 से रिक्त है। बीएचयू वाराणसी में है और माननीय प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र का BHU एक ऐतिहासिक इंस्टिट्यूशन है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कायम की थी। वहां के Executive Council defunct हैं, वे इसलिए defunct हैं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी को वहां के जिन सदस्यों का मनोनयन करना है, वह नहीं हो पा रहा है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप मनोनयन कीजिए, ताकि वहां का काम हो सके। ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है, ताकि वाइस चांसलर को इमरजेंसी पावर के अंतर्गत अधिकार दिए हैं, उसमें उनको जो करना है, वे करें, वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, यह भी एक बात है कि आज हम लोग Institutes of Excellence में भी समझौता कर रहे हैं। आज विश्व में और देश में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी social sciences, humanities and languages के लिए prime institution है। वहां भी कौन सा Vice-Chancellor नियुक्त होता है, जो IIT का प्रोफेसर है, वह टेक्निकल है, उसको वहां अप्वाइंट किया जाता है। क्या आपको social sciences, humanities and languages में कोई योग्य प्रोफेसर नहीं मिला, जो वहां नियुक्त किया जा सके। इतना ही नहीं, वहां पहुंचने के बाद Engineering की faculty चालू कर दी, जबकि JNU के बगल में IIT है। वहां management की faculty चालू कर दी। अब आप समझिए कि देश में और विश्व में जो social sciences, humanities and languages के लिए प्रतिष्ठित है, वहां आपने टेक्निकल और management studies चालू कर दीं।

अब मैं ज़िक्र करना चाहता हूं कि किस प्रकार से हायर एजुकेशन और एजुकेशन मिनिस्ट्री में भ्रष्टाचार पनप रहा है। NAAC का bribery scandal सर्वविदित है। जिस व्यक्ति को जेल हुई, जो ज़मानत पर है, उसकी नियुक्ति किसने की थी, उसकी नियुक्ति तत्कालीन Vice-Chancellor, JNU ने की थी, जिन्हें आपने अब प्रमोट करके University Grants Commission का चेयरमैन बना दिया। ...(**व्यवधान**)... उनकी नियुक्ति के बाद डायरेक्टर मैनेजमेंट स्टडीज की भी नियुक्ति की गई। फिर, जब वहां के वाइस चांसलर UGC के चेयरमैन बने, तो उन्होंने उन्हीं महाशय को NAAC में अप्वाइंटमेंट दे दिया, क्योंकि NAAC के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष यूजीसी के चेयरमैन होते हैं, इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ समझौता, समन्वय या साझेदारी उन दोनों में नज़र आती है।

दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय - वहाँ सुनील कुमार ने 19 करोड़, 48 लाख रुपये गवर्नमेंट अकाउंट से अपने प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और पकड़े गए।

उसी प्रकार से जीवाजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, डॉ. अविनाश तिवारी ने एक फेक कॉलेज को डिग्री प्रदान कर दी। जब यह मामला वहां के गवर्नर के संज्ञान में आया, तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ।

इसी प्रकार, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में है, जहाँ के चेयरमैन उपराष्ट्रपति जी हैं, वहाँ करप्शन और financial embezzlement के तहत 2 करोड़, 65 लाख रुपये के भ्रष्टाचार का तत्कालीन Vice Chancellor के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। इसके बाद वे वहां से भाग गए। उसके बाद उन्हें हरियाणा State Higher Education Council का चेयरमैन बना दिया गया।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटीज़ स्थापित किए थे, जिनके कारण आज भारत के इंजीनियर्स पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं। आईआईएम्स के माध्यम से भी भारत की ख्याति बढ़ी है, जिसको पंडित नेहरू ने कहा था, " These are the temples of modern India." अब वहाँ एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। नड्डा जी, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आईआईटी, मंडी का डायरेक्टर कहता है कि यहां पर जो भूमिस्खलन हो रहा है, इरोज़न हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है कि यहां के लोग मीट खाते हैं। आप बताइए की मीट खाने वाले व्यक्ति की वजह से हिमाचल प्रदेश में आपके प्रांत में land slide हो रहा है। अब आप समझ लीजिए। इसी के साथ-साथ और भी बातें थीं। दक्षिण भारत के एनआईटी के एक प्रोफेसर ने कह दिया कि नाथूराम गोडसे राष्ट्र भक्त थे। किस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित होकर New Education Policy लागू की जा रही है। हमें इस बात की आपत्ति है। मैं आपके सामने दो उदाहरण देना चाहता हूं। इस बार एनसीईआरटी में लगभग 20 प्रतिशत concession पर टैक्स्ट बुक्स बांटी गईं। इसका कारण यह है कि वहां पर उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि निष्पक्षता से कागज की खरीद होनी चाहिए। मैंने जब उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस भाव में कागज़ खरीदा गया। तब मैंने उनसे पूछा कि पिछले पांच सालों में किस रेट पर कागज खरीदा गया, लेकिन आज तक मुझे उसका उत्तर नहीं मिला है। मुझे इसकी जानकारी मिली है कि खरीद में भारी भ्रष्टाचार होता है। मैं इसी के साथ-साथ दो उदाहरण देना चाहता हूं। पहला, एक autonomous minority institution, जो देश में विख्यात है, वह St. Stephen's College है। St. Stephen's College के प्रिंसिपल वहां पांच साल से कार्यरत हैं। Delhi University पांच साल के बाद उनको नियुक्ति का अधिकार नहीं दे रही है। Vice-Chancellor उन्हें नियुक्ति के अधिकार नहीं दे रहे हैं। वहां promotion रोक दिए गए हैं। देश के सबसे सम्माननीय कॉलेज में लगभग 100 faculty members की posts vacant हैं। मैं हरदीप पुरी साहब से कहूंगा कि आप इसको देखिए कि St. Stephen's College के साथ क्या हो रहा है।

श्री जयराम रमेशः वे हिंदू कॉलेज के हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: वे हिंदू कॉलेज के हैं, लेकिन उनकी rivalry St. Stephen's College के साथ हो सकती है। मैं निवेदन करता हूं कि इसमें सौ पद खाली हैं। इसी प्रकार से जेएनयू, जो देश का एक प्रमाणित और विख्यात इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर भी 150 faculty members के promotion cases pending हैं। 30 faculty eligible Associate Professors अब भी Assistant Professor बने हुए हैं। Thirty faculty eligible for professorship के लोग अभी भी Assistant Professor हैं। Fifty faculty eligible for professorship अब भी Associate Professor बने हुए हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके छात्र उनके सीनियर हो गए हैं। यह हालत जेएनयू की है। जेएनयू एक ऐसी संस्था है, जो गरीब परिवार के बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा देती है, जिसके साथ यह समझौता किया गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि University Grants Commission पहले ग्रांट दिया करता था, लोन नहीं देता था। अब नीति परिवर्तित की गई है और Higher Education Financing Agency का गठन किया गया है। इसका मतलब यह है कि University Grants Commission अब कोई ग्रांट नहीं देगा। HEFA के माध्यम से आप लोन लीजिए और लोन लीजिए का मतलब है कि लोन पटाइए। अब लोन पटाने के लिए उनको फीस बढ़ानी पड़ेगी। जब फीस बढ़ेगी, तो private universities फीस बढ़ाएंगी और सरकारी universities को भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। University Grants Commission को ग्रांट देने का जो अधिकार था, उसको कायम रखना चाहिए। अब scholarships में Junior Research Fellowship payments मिलनी चाहिए, वह महीनों तक नहीं मिल पाती है। National level science talent search examination, जिसको बजट की कमी के कारण बंद कर दिया गया था। NSTSE, जो scholarship और grade IX के बच्चों को प्रोत्साहन देता था, उसको भी बंद कर दिया गया है। Maulana Azad National Scholarship for students of minority communities लॉन्च हुई थी, उसको भी 2020 से समाप्त कर दिया गया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, कभी भी कोई टैक्स सरकारी यूनिवर्सिटीज़ पर नहीं लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद सरकारी यूनिवर्सिटीज़ से भी जीएसटी लिया जा रहा है। यह टैक्स 18 परसेंट की दर से लिया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा महंगी होने की संभावना है।

महोदया, मैं इसी के साथ-साथ एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा यह सुझाव है कि टैक्स्ट बुक्स और रिसर्च के जो भी इक्विपमेंट्स और सामान हैं, उन पर एवं सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर जीएसटी और अन्य सारे टैक्सेस माफ होने चाहिए। हम लोग आपके माध्यम से इसकी डिमांड करते हैं।

महोदया, रिसर्च पर भी विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ज़माने में रिसर्च पर पहले जितना खर्च होता था, वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। 9 परसेंट शेयर, जो इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपेंडिचर था, उसमें भी कमी की गई है। नीति आयोग ने खुद यह रिपोर्ट दी है कि इन्नोवेशन और कमर्शियल रिसर्च पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हुआ है। महोदया, यह 2021-22 में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के 40 परसेंट पीएचडी स्टूडेंट्स को दिया जाता था, लेकिन अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि रिसर्च के क्षेत्र में हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट्स

हैं, जिन्हें पेटेंट की राशि मिलती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। As an incentive उन्हें अपने पेटेंट से रॉयल्टी मिलती है, इसलिए उन्हें इसको रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

माननीय महोदया, I will conclude. हालांकि मोदी जी कहते हैं, 'सबका साथ- सबका विश्वास- सबका प्रयास' महोदया, वे सबका साथ कहते हैं, लेकिन करते हैं कुछ लोगों का विकास। आप देखेंगे कि शिक्षा के अंदर भी सांप्रदायिक रंग दिए जाने के संकेत हैं, करिकुलम में भी सांप्रदायिकता के संकेत हैं, नियुक्ति में भी भेदभाव किया जा रहा है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक सुशिक्षित भारत नहीं बनाएंगे, तब तक विकसित भारत बनने वाला नहीं है। आज जो हालत है, मैं उसके लिए आपसे अनुरोध करता हूं।

महोदया, 1947 में दो देश आज़ाद हुए। एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। पाकिस्तान ने कौन-सा रास्ता चुना? उसने theocratic रास्ता चुना, यानी जो धर्म के आधार पर था। आज उसकी हालत क्या है? दूसरी तरफ भारत ने liberal, modern and secular democracy चुनी और आज हम लोग कहाँ पहुँचे हैं! माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया जी, मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई हमारी है और विचारधारा के आधार पर देश में आज वह संघर्ष चला हुआ है, जिस संघर्ष में हम पूरे तरीके से उन लोगों के साथ हैं, जो पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सभी लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। जब हम सभी को सुशिक्षित करेंगे, access देंगे, quality education देंगे, तभी हम विकास कर पाएंगे। महोदया, मैं आखिर में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे हरदीप सिंह पुरी जी इस बारे में जानते होंगे कि पाकिस्तान की एक मशहूर शायरा है, फहमीदा रियाज़। फ़हमीदा रियाज़ ने जब यहाँ की घटनाएं देखीं, तो उन्होंने एक नज़्म लिखी। मैं आपको उस नज़्म का कुछ पैरा पढ़कर बताता हूं। उन्होंने लिखाः

'तुम भी बिल्कुल हम जैसे निकले'

...यानी कि पाकिस्तान की शायरा कर रही है कि भारतीय, तुम भी हम जैसे निकले।

'अब तक कहाँ छिपे थे भाई?
वो मूरखता, वो घामड़-पन,
जिसमें हमने सदी गँवाई।'

..यानी कि पाकिस्तान ने एक सदी गँवा दी।

'आखिर पहुँची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई, बहुत बधाई।'

आज यह हालत आपकी विचारधारा, आपका 11 साल का शासन और आपकी 2020 की शिक्षा नीति करने जा रही है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक पाकिस्तानी शायर की शायरी से अपना बात समाप्त की। मैं भारत के राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की दो पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं:

'हां' और 'ना' भी अन्य जन करना न जब थे जानते,
थे ईश के आदेश तब हम वेदमंत्र बखानते।

मैं उस शिक्षा में, उस शिक्षा नीति के बारे में आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, पुस्तकों के बारे में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात कही। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आपकी बात तो ठीक है। हम तो कभी नाथूराम गोडसे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जेएनयू में आपके नेता खड़े थे और वहां नारे लग रहे थे, अफजल तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, हम अब भी शर्मिंदा हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: ऑथेंटिकेट कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Madam, please ask him to authenticate.

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैं ऑथेंटिकेट करूंगा और लिखकर दूंगा। ...(**व्यवधान**)... टुकड़े-टुकड़े गैंग के बारे में ...(**व्यवधान**)... Yes, I will authenticate. मैं निश्चित रूप से करूंगा, अभी करूंगा, लिखकर भेजता हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। उन्होंने प्रारंभ में चर्चा की कि कुछ किताबों में परिवर्तन कर दिया गया है। हां, कुछ किताबों में परिवर्तन हुआ है। जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की, वह किताबों में लिखा गया है। यह इतिहास है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवार पर चिनवा दिए गए, बंदा वीर बैरागी के बंद-बंद काटे गए, गुरु गोबिन्द सिंह जी के चारों शहजादों का बलिदान हुआ। उनका किताबों में उल्लेख करना कांग्रेस पार्टी को पाप लगता है, लेकिन हमारा यह राष्ट्र धर्म है और मैं माननीय प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म का इसमें निर्वाह किया है। इन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा में स्कूल बंद हो गए। समग्र शिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा में सुधार की बात माननीय प्रधान जी ने की है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 41,250 करोड़ रुपए का आवंटन समग्र शिक्षा अभियान में हुआ है। उस समग्र शिक्षा अभियान में बुनियादी ढांचा, स्मार्ट क्लासरूम, लैब, डिजिटल शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम हैं। ये प्रशिक्षण की बात कर रहे थे। समग्र शिक्षा में प्रशिक्षण है। यह समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान से आई, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर मुरली मनोहर जोशी जी ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। नई शिक्षा नीति में समग्र शिक्षा अभियान पर 41,250 करोड़ रुपया खर्च किया गया।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, ये कह रहे थे कि गरीब छात्रों का क्या होगा? ये कह रहे थे कि स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूलों में प्रवेश से लेकर, पुस्तक से लेकर, ड्रेस से लेकर, मिड डे मील से लेकर, दूध से लेकर, सारा काम अगर किसी ने किया है, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारी सरकार ने किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हम बच्चों को क्या नहीं दे रहे हैं - ड्रेस दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, टीचर दे रहे हैं और पीएम पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत 11.8 करोड़ बच्चों के लिए 12,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल के बजट में किया गया है। यह गरीब बच्चों की सेवा नहीं तो और क्या है? इस पर नजर नहीं डाली जाती। मैं इस साल का बजट बता रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः यह कब शुरू हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ीः अब यह शुरू कब हुआ - आप पुरानी बातों में क्यों जा रहे हैं? आप कितनी पुरानी बातों में जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है, यह कोई आपके लिए लागू नहीं है - गल आदमी करे पुरानी बात। इसलिए आप नई बात करिए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने पीएमश्री योजना प्रारंभ की है। देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों में आधुनिक स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ स्मार्ट क्लास, सौर ऊर्जा और आधुनिक सुविधाएँ होंगी। अब इस पीएमश्री योजना को अधिकांश राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। एक-दो राज्य इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन एक-दो राज्यों की बात माननीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ कह रहे हैं। आज 14,500 स्कूल सारे हिंदुस्तान में पीएमश्री के लिए चुने गए हैं। आज हर राज्य इसके लिए माँग करता है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी शासित हो, चाहे बीजेपी पार्टी शासित हो। पीएमश्री योजना, पीएमश्री क्लास आज एक अच्छा मॉडल बन गई है। मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ असम गया था। हमने असम में गुवाहाटी से दूर एक आदिवासी गाँव में जाकर देखा था कि पीएमश्री योजना वहाँ कैसे कार्यान्वित हो रही है। आपने वहाँ के बच्चों से प्रश्न भी पूछे थे कि यह फोटो किसकी है, तो उसने कहा कि शंकर देव की है; यह फोटो किसकी है, तो उसने कहा कि लाचित बरफुकन की है। ये सारे जवाब इनके सामने बताए। फिर इन्होंने कहा कि यह फोटो किसकी है, तो उसने कहा कि महात्मा गाँधी की है। ये दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के बच्चे थे, जिन्होंने यह सारी बात बताई। यह पढ़ाई, यह बातचीत नई शिक्षा नीति के कारण से शुरू हुई। लॉर्ड मैकाले, मैं उसको लॉर्ड नहीं कहता, मैं उसको मैकाले ही कहता हूँ, क्योंकि हमारे लॉर्ड तो भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, वे हमारे लॉर्ड थे। मैकाले की शिक्षा नीति ने जो शुरू किया था, उसका समापन इसी से हुआ है, यह मैं कहना चाहता हूँ। इस बार बच्चों के लिए -- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, यह आपने शुरू किया था, मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं -- इसकी संख्या बढ़ाई गई।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आप नवोदय विद्यालय देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज इसकी सबसे बड़ी माँग है। नवोदय विद्यालय का प्रारंभ किया गया और आज वे सबसे बढ़िया विद्यालय माने जाते हैं। उनमें कुछ vacancies की बात आई है, लेकिन उन vacancies को भरने का एक सिस्टम है और सिस्टम के आधार पर उनको राज्य सरकारों को भरना है। वे भरी जा रही

हैं, लेकिन इस देश में आज केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारा जो कुल बजट है, जब मोदी जी की सरकार आई थी, उस समय बजट था 68,728 करोड़ रुपए, जबकि आज यह बजट बढ़ कर 1,28,650.5 करोड़ रुपए हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इतना बड़ा बजट इसमें बढ़ गया है, यह शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं, तो और किसकी तरफ ध्यान है! यह जो बजट है, अभी यह राष्ट्रीय जीडीपी का 3 परसेंट है। समवर्ती सूची में राज्य सरकारें भी इस पर खर्च करती हैं। इसलिए यह 4.5 परसेंट के बराबर जा रहा है। अमेरिका जितना खर्च कर रहा है, जीडीपी का 4 परसेंट, उससे ऊपर खर्च हमारे यहाँ हो रहा है। मोदी जी के इस 5 साल के कार्यकाल में इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि जीडीपी का 6 परसेंट तक हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। इतना बड़ा काम हमारी शिक्षा नीति में हो रहा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, यहाँ उच्च शिक्षा के बारे में बात की गई। उच्च शिक्षा के बारे में जितना काम 10 वर्ष में हुआ है, उतना काम मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है कि 50 साल तक नहीं हुआ। इतना बड़ा काम हुआ! आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस की संख्या बढ़ाई गई। भारत में 23 विश्वविद्यालय ऐसे बनाए गए, जो eminence के संस्थान हैं। ऐसे 23 संस्थान बनाए गए। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज के युग के अनुरूप स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास का काम किया गया। यह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए किया गया। इंजीनियरिंग में देखें, तो 13 क्षेत्रीय भाषाओं में पहली बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई की शुरुआत हुई। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दो लाइनें क्वोट कर रहा हूं:

अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण,
पै निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन।

इसलिए इंजीनियरिंग के जो पाठ्यक्रम हैं, वे हमने 13 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रारंभ किए हैं। उनमें दक्षिण भारत की भाषाएँ भी हैं, उत्तर भारत की भाषाएँ भी हैं, पूर्व की भी हैं, पश्चिम की भी हैं और मध्य की भी हैं। हमने इसमें सभी भारतीय भाषाओं में काम चालू किया है। हमने एक राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन बनाया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नई शिक्षा के बारे में आप जो कह रहे थे कि उसमें किस प्रकार से अन्वेषण हो, शोध हो, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन (NRF) बनाकर उसमें 50,000 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। आज तक यह प्रावधान कभी नहीं किया गया।

इसी प्रकार एक 'दीक्षा पोर्टल' शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत डिजिटल माध्यम से शिक्षकों और बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनको ऑनलाइन अध्ययन कराया जाता है। इसमें बच्चे घर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। नई शिक्षा नीति में इसके माध्यम से यह काम शुरू किया गया है। एक 'स्वयं' और 'ई-पाठशाला' भी प्रारंभ की गई है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए विशेष प्लेटफॉर्म है, जिसमें लाखों छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें यह काम भी किया गया है। इसके साथ ही एक 'पीएम ई-विद्या योजना' भी है। 'One Class One Channel' नीति के अंतर्गत 12 नए टेलीविजन चैनल्स प्रारंभ किए गए हैं। यह आधुनिक शिक्षा का विस्तार और प्रसार नहीं तो और

क्या है? National Education Alliance for Technology (NEAT) में AI आधारित एडटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इंडस्ट्रीज़ में अप्रेंटिसशिप के अवसर बढ़ाए गए हैं। इस प्रकार स्टार्टअप और रिसर्च के लिए विशेष बजट दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, जिसके अंतर्गत 50 करोड़ का फंड दिया गया था, उसमें काम किए गए हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मेडिकल में स्टूडेंट्स के लिए सीट्स की संख्या 50,000 से बढ़ाकर एक लाख से ज्यादा कर दी गई है। IIM, AIIMS, जितने हायर एजुकेशन के संस्थान थे, उन सबको बढ़ावा दिया गया है। यह जो नयी शिक्षा नीति आई है, उसने भारत का कायाकल्प किया है। इसमें समग्र और बहुविषयी शिक्षा है। इसमें रटन्त करने वाली शिक्षा नहीं है। इसी प्रकार छात्रों को कोई भी विषय चुनने की आजादी है। छात्र एक साथ दो सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, वे साइंस भी पढ़ सकते हैं और आर्ट्स पढ़ सकते हैं। इसमें छात्र एक बार आ गया, लेकिन उसने 3 साल का कोर्स पूरा नहीं किया, बीच में ही चला गया, तो उतनी डिग्री उसको मिल सकती है। इसमें इस प्रकार के नए अनुसंधान किए गए हैं। पहले 10+2 का जो फार्मूला था, उसको चेंज करके 5+3+3+4 का नया फार्मूला लागू किया गया है। बच्चों को 3 साल से शिक्षा में ले जाकर, उसको और अधिक प्रशिक्षित करने का काम किया गया है तथा उच्च शिक्षा में सुधार किया गया है। अब उसका एक से ज्यादा बार प्रवेश हो जाएगा, तीन या चार साल के डिग्री कोर्स हो सकते हैं। यूजीसी, एआईसीटीई, सबको हटाकर - जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे, ये कह रहे थे कि वहां उनके लोगों को लगाना है या उनके लोगों को लगाना है। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि जितने पारदर्शी तरीके से विश्वविद्यालयों के कुलपति चुनने का काम और जितने पारदर्शी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर चुनने का काम अब तक हुआ है, जितने पद भरे गए हैं, आज तक इतिहास में उतना कभी नहीं हुआ। वहां पर पहले तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टेड लोगों के अड्डे बन गए थे। वे आज कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करना चाहते हैं, भारत में इस प्रकार की बातें सेट करना चाहते हैं! ये वामपंथ के जो अर्बन नक्सलाइट्स हैं, उनके लिए हम विश्वविद्यालयों में जगह नहीं छोड़ेंगे। यहाँ राष्ट्रभक्त लोगों के लिए राष्ट्र भक्त तैयार करने के लिए काम होगा - यह समझने जरूरत है। उनका जो समर्थन करेंगे, उनका भी समय लंबा नहीं है। मैं यह बता देना चाहता हूँ। उनको इस बात को समझ लेना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): तिवाड़ी जी, आप इसको authenticate कीजिए कि urban naxal कौन हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री घनश्याम तिवाड़ीः महोदया, मैं उनको बता रहा हूँ। मैं yield कर रहा हूँ। मुझे yield करने में कोई दिक्कत नहीं है। वे यह जानना चाह रहे हैं कि अर्बन नक्सलाइट कौन हैं? मैं कह रहा हूँ, 'प्रत्यक्ष सम किम प्रमाणं' - जो सामने प्रत्यक्ष है, वही प्रमाण है। यह विचारधारा से होता है। यह आदमी के व्यक्तित्व से नहीं होता है।

श्री जयराम रमेशः आपके गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि हमारे पास urban naxal की कोई परिभाषा नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैं उनको आग्रह करूँगा कि आपकी फोटो लगा दें, तो परिभाषा आ जाएगी।

मानीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र बारे में कह रहा था कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत माननीय प्रधान मंत्री जी ने... मैंने वेद के एक श्लोक से शुरू किया था :

'हाँ और ना' भी अन्य जन करना न जब थे जानते,
थे ईश के आदेश तब हम वेदमंत्र बखानते।'

उन वेदों पर खोज करने के लिए, हमारे प्राचीन ज्ञान को लाने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। उसमें भी 71.5 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। अब हम व्यवस्था की खोज कर रहे हैं। मैंने कल भी उदाहरण देकर कह था कि खगोल पूछ रहे हैं कि आप किसकी खोज कर रहे हैं? हमने आर्यभट्ट को पढ़ा दिया, तो क्या गलती कर दी? आर्यभट्ट को हमने नहीं पढ़ाया है। यह पुरानी खोज है। नासा ने आर्यभट्ट को पहला खगोलशास्त्री बताया और वहां पर उनकी फोटो लगायी। हमने वह लिस्ट भी साथ दी है कि आर्यभट्ट ने लिखा है कि मेरे पहले 122 खगोलशास्त्री और हुए थे। वे खगोलशास्त्री यह बताते हैं कि बृहस्पति यहाँ है, गुरु वहाँ है, तब जाकर महाकुंभ बनता है। उनको पढ़ाने का काम किया, तो वह ज्ञान का काम है। इन्होंने उस प्राचीन भारतीय ज्ञान को बताने का काम भी किया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मोदी जी के काल में शिक्षा में अभूतपूर्व और आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कल मैंने कहा था कि कई क्रांतियां हुई हैं। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत क्रांतियां हुईं। सबसे पहले आर्थिक क्रांति हुई। आज हमारी जीडीपी विश्व में सबसे ज्यादा है और हम 2026 में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। यह आर्थिक क्रांति है। कृषि क्रांति हुई, राजनीतिक क्रांति हुई, सांस्कृतिक क्रांति हुई और यह जो सातवीं क्रांति है, उस सप्त क्रांति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में शैक्षिक क्रांति हुई। ये सात क्रांतियां हैं और अंत्योदय है। हम सुनते थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय दिया। हम सुनते थे कि जयप्रकाश नारायण जी ने जेपी मूवमेंट में total revolution की बात की थी, संपूर्ण क्रांति की बात की थी। संपूर्ण क्रांति तब होती है, जब एक-एक चीज में क्रांति होती है। हमने आर्थिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति की। ये सब राजनीतिक क्रांति ही है कि असम से लेकर गुजरात, पुदुचेरी तक और ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है। क्या यह राजनीतिक क्रांति नहीं है? यह राजनीतिक क्रांति है। राम मंदिर का निर्माण होना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना और महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन होना - ये सब सांस्कृतिक क्रांतियाँ हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के द्वारा प्रतिभा सम्मान मिले हैं, बार-बार पुरस्कार मिले हैं।

2.00 P.M.

क्या यह हमारे भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने की क्रांति नहीं है? दिग्विजय सिंह जी क्रांति की बात कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सारी बातों के कारण हम एक क्रांति की ओर अग्रसर हैं। यह टोटल क्रांति है और संपूर्ण क्रांति है। ...(**समय की घंटी**)... मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि हमने यह जो नई शिक्षा नीति लागू की है, भारत

वैश्विक अनुसंधानकार शिक्षा का केंद्र बनेगा, जैसे नालंदा था, जैसे तक्षशिला था। ऐसे विश्वविद्यालय भारत में बनेंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भी हमने यहां पर खोल दिए हैं। यह मोदी जी के युग में शैक्षिक क्रांति है। यह क्रांति नहीं, संक्रांति है। क्रांति वह होती है, जिसमें केवल विद्रोह होता है, लेकिन संक्रांति वह होती है, जिसमें संस्कार की लिपि लिखी जाती है। यह नई शिक्षा नीति संस्कार की लिपि लिखी गई है और निश्चित रूप से संपूर्ण क्रांति होगी, शैक्षिक क्रांति होगी। मैं माननीय प्रधान जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को इस नई शिक्षा क्रांति के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): श्री रीताब्रता बनर्जी, आपका 12 मिनट का समय है।

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Madam, as I speak on behalf of my party, AITC, I want to mention that education is the basic building block of every society. It is the single best investment that countries can make to build prosperous, healthy and equitable societies. But, unfortunately, 'education for all' still remains a distant dream in our country. Since decades, discussions and demands for allocation of 6 per cent of GDP on education continue. Union expenditure on education in the Budget has been 0.37 per cent of the GDP, much below the set target of 6 per cent of the New Education Policy 2020. Ensuring equitable access to quality education is one of the greatest challenges facing the country. Eighty per cent of our youth are unemployed. One in every three youth is neither in education, nor in employment nor in training. Ninety-three per cent of the workforce contributing to more than 50 per cent of our GDP is employed in the unorganized sector, with no job security or social security and are being deprived of statutory benefits. Now, as we discuss education, -- hon. Minister is here -- I want to mention that without any consultations with the State Governments, the NEP has been forcibly thrust upon the States. Our State Government was forced to start the four-year graduation course with interdisciplinary and multidisciplinary framework so that students of the State don't lag behind or suffer as far as the all India perspectives are concerned. But the huge infrastructure and expenditure that the State Government is incurring is not borne by the Central Government. Leave aside the allocation for meeting such huge expenses, the Union Government is completely silent about the areas from where this huge expenditure will be met. The persistence of the Governor as Chancellor has caused numerous problems in the governance of State Universities. While State Governments fund these universities, Governors wield substantial power without corresponding accountability. This creates a dual authority system with conflicting demands. Disagreement between Governors and State Governments, particularly, in

Opposition-ruled States, lead to delays in appointing VCs causing administrative paralysis. These delays affect areas such as appointment of staff, implementation of projects and even awarding of degrees. Now, some Governors rely on political interference, often prioritizing the Centre's political agenda over the university's autonomy and interest. Allowing Governors appointed by Centre to control State institution compromises the principle of federalism. State Universities should be fully accountable to State Governments only elected by the people. The Search Committee headed by former Chief Justice of India, Shri U.U. Lalit, had made some recommendations.

In spite of those recommendations, the Governor of West Bengal has only appointed 14 permanent Vice-Chancellors out of the Government-run and 31 aided Universities. [&] "For a considerable period of time, attempts are being made to establish direct contacts with the Vice Chancellors of the State Government-aided universities bypassing the State Government. Those Vice Chancellors who are not maintaining direct contact are being unethically removed from their respective positions by the Chancellor. As a result, the higher education system in the State is on the verge of collapse." In the recently published UGC Draft Regulations, all powers for appointing Vice-Chancellors of State-run and affiliated universities have been vested in the hands of the Chancellors. The Governors, who are the Chancellors, are completely ignoring the elected State Governments. Literally, all powers are centralized in the hands of the Union Government, though education is not in the Union List. The Samagra Shiksha Abhiyan, a Centrally-sponsored Scheme with a fund-sharing ratio of 60:40, has seen the State of West Bengal achieve one of the best performances, yet it is being deprived of its share. The Minutes of the Programme Approval Board of Samagra Shiksha reveal that the Government of India has recommended a budgetary outlay of Rs 2,629 crore for 2023-24 for the State, out of which the Government of India's share was Rs 1,745.78 crore. Out of this amount, only Rs 311.29 crore has reached the State, with no other funds being released. Despite repeated communications from the State Government, the Government of India has not released any funds. The Government of India did not release its share of Rs 1,433.71 crore in 2023-24 and has made zero allocations for 2024-25 to date. It is worth mentioning that the Government of India has not released a cumulative amount of Rs 3,180.31 crore during 2023-24 and 2024-25 respectively to the State of West Bengal. The Government of West Bengal, under Madam Mamata Banerjee, is instead releasing State share of 40 per cent as well as additional allocations to the Samagra

[&] English translation of the original speech delivered in Bengali.

Shiksha Society to ensure timely payment of wages and salaries to Samagra Shiksha employees, composite grants to schools, and other student-centric incentives. The non-release of funds by the Government of India, despite clearance from the Ministry of Finance in favour of the State of West Bengal, is a clear sign of deprivation of our people and violation of their right to education, as enshrined in the Act framed by Parliament. We are now learning from the media that due to the non-signing of the MoU by the Government of West Bengal for the PM SHRI — PM School for Rising India Scheme -- which is a separate scheme with separate guidelines, budgets, and SNA accounts, the fund release under Samagra Shiksha has been stopped. The State has raised objections to this scheme, named PM SHRI, despite a fund-sharing ratio of 60:40. Furthermore, there is no mention in the Samagra Shiksha guidelines that signing the MoU for PM SHRI is a precondition for releasing funds under the Samagra Shiksha Scheme, which is designed under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. The new Centrally-Sponsored Scheme has been framed with a funding pattern of 60:40, creating pressure on States to accept the scheme's priorities, which may not align with State Government priorities. Now, the ideas of the ruling class, Madam, are the ruling ideas in every epoch. The class controlling the means of material production also controls the means of mental production. This is evident. When I heard Mr. Ghanashyam Tiwari speaking, I remembered these words, as the NEP 2020 emphasizes promoting critical thinking, scientific temper and constitutional values. We have cut down on several key topics in our curriculum. We have removed the periodic table, Darwin's Theory of Evolution, the theorem of Pythagoras, and Michael Faraday's contributions to our understanding of electricity and magnetism. Despite protests from thousands of scientists across the country, the NCERT has not taken heed. In 2018, the then Minister of State for Higher Education, Shri Satya Pal Singh, sparked controversy by demanding the removal of the Theory of Evolution from school curricula, citing that no one has seen an ape transform into a human being. Other political leaders from the ruling dispensation defended his statement on social media.

The National Council of Educational Research and Training has decided to omit the chapter of the Periodic Table saying that this is a rationalization exercise. I want to know from the hon. Minister: What does this rationalization exercise mean? Does it mean omitting the Periodic Table from the curriculum? The Council has also deleted chapters 'Democracy and Diversity, Popular Struggles and Movements, Political Parties, and Challenges to Democracy.'

Madam, I now come to a very important point, that is, of educational institutions run by the minorities. There are 54,000 educational institutions run by the

Christian community in our country. About seven crore of students go to these institutions every year. About 70 to 75 per cent of the students are not Christians. They are from different communities — Hindus, Muslims, Buddhists, Sikhs and even Atheists. Why does the Government want to interfere with the administration of these institutions and intimidate these institutions? There are many Ministers in Modiji's Cabinet. I can name many of them who have been to these institutions. It is a long list, but I will give only one name. The president of the Bharatiya Janata Party, the hon. Leader of the House, Shri J.P. Nadda, went to St. Michael's, Patna. He is the right person to share what a great education he had at this minority-run institution! *..(Interruptions)..* Let me finish.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: No; I studied from St. Xavier's High School, Patna.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Okay; sorry, I correct it. Now, how is India described? India was described by our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, in his Discovery of India. What does it say? It says, "Nehru invokes the very evocative idea of the palimpsest. In ancient times before the discovery or invention of paper, the palimpsest was either a tablet of stone or a wood on which every victor would erase the past history and write his own convenient version. But India is a typical palimpsest, an ancient palimpsest on which layer upon layer of thought and reverie had been inscribed and yet no succeeding layer had completely hidden or erased what had been written previously." This beauty of India will continue despite all attempts to erase away all our glories.

I have a minute left. So, lastly, I want to mention the Uttar Pradesh Government. The Uttar Pradesh Government has revised the syllabus and in the revision of the syllabus, the Uttar Pradesh Government has excluded Rabindranath Tagore. *...(Interruptions)...* Rabindranath Tagore has been excluded from the syllabus of the Uttar Pradesh Government. An elected State Government has every right of doing it. *...(Interruptions)...* It is their prerogative. They probably think that Rabindranath can be replaced by Ramdev. I have no problem. The UP Government thinks that Rabindranath can be replaced by Ramdev. *...(Interruptions)...* The true polymath, accomplished musician and artist, *...(Interruptions)...* Madam, I crave your indulgence; I will take a minute more. The true polymath, accomplished musician and artist, an electric philosopher and a passionate political activist, Rabindranath, advocated the integrity of education and culture. *...(Interruptions)...* The people who are dropping him from textbooks are the ones who are dictating that we cannot eat fish on particular days of the week. *...(Interruptions)...* Ancestors of Rabindranath and

of us have been eating fish for five thousand years. It is in our DNA. ...*(Interruptions)*... The problem is, Madam, some people do not understand the pulse of the *Maa, Mati or Manush. Maa, Mati, Manush* means mother, land and people. Alongwith Maa, Mati, Manush comes *Maa, Mati, Manush and Mach*, that means, *Maa, Mati, Manush* and Fish. I will just quote a line of Tagore. They have deleted Tagore. It was Tagore who said, ...(*Time-bell rings.*)... .

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है।

SHRI RITABRATA BANERJEE: &I am the poet of the world. Each and every sound that originates in any corner of the world will be reciprocated with the tune of my flute.

SHRI DEREK O'BRIEN: Madam, you need to protect the speaker? ...*(Interruptions)*... At least, you should allow the speaker to complete. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. INDU BALA GOSWAMI): Please sit down. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू। आपके पास 14 मिनट का समय है।

DR. KANIMOZHI NVM SOMU (TAMIL NADU): Hon. Vice-Chairman and esteemed Members of this august House, as of March, 2025, India had a total of 30 Cabinet-level Education Ministers. The Ministry of Education, formerly known as the Ministry of HRD, has seen various Cabinet Ministers since its inception, including prominent figures such as Maulana Abdul Kalam Azad, the first Education Minister post-independence, followed by leaders like Shri M.C. Chagla, Shri Fakhruddin Ali Ahmed, Shri V.K.R.V. Rao and many more. But after the reign of the BJP, led by Prime Minister, hon. Modiji, the challenges within the Education Ministry, particularly, with irrational policy decisions, emerged when Modi's Administration assumed office in 2014.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON) *in the Chair*.]

Under his leadership, there has been a discernible shift that has infringed upon the State's autonomy, deviating from established federal principles and undermining the intended framework of development and inclusive governance. During his reign from 2014 to 2016, centralization and curriculum changes had taken place; from 2016

& English translation of the original speech delivered in Bengali.

to 2019, he implemented NEET, undermining State autonomy; and from 2019 to 2021, there were controversial NEET-JEE Exams amid the COVID-19 pandemic; and, right now, hon. Dharmendra Pradhan from 2021 to present, implemented the NEP language policies, infringing on the State autonomy and cancelling the MP quota seats in the KV schools.

Sir, before the British rule, 'Education' in India was decentralized. The colonial system centralised 'Education', offering limited access, particularly, for rural poor and women, and aimed at creating an elite serving the Empire. Post-independence, India faced the dual challenge of unifying a diverse nation and addressing the deep educational disparities. The framers of the Indian Constitution recognised education as a vital tool for nation-building. As a result, Education was placed in the Concurrent List of the Constitution under Article 246, which made it a shared responsibility of both the Union and the State Governments. From this time itself, Tamil Nadu has been a forerunner in the educational reforms and achievements.

The State introduced free and compulsory education in 1947, well ahead of many other States in India. By 1960s, it implemented the Mid-Day Meal Scheme, which continues to be a model for the other States. This initiative not only improved enrolment but also reduced dropout rates, especially, among the underprivileged children. The State's emphasis on education has led to impressive literacy rate, with Tamil Nadu consistently ranking among the top States in literacy in India.

Sir, from the 60s, Tamil Nadu has been following the two-language policy and Tamil Nadu has been successful in achieving the good GER enrolment ratio. As per the 2011 Census, Tamil Nadu's literacy rate stood at 80.3 per cent, significantly higher than the national average. The State's focus on technical education has contributed to its status as a hub for industries like IT and engineering. Tamil Nadu also has a strong emphasis on inclusive education. Furthermore, the State's success in reducing educational inequalities through Schemes like free uniforms, bicycles and the digital learning platform continues to receive national recognition.

Sir, Tamil Nadu GER's growth is 51.4 per cent. In contrast, India's GER, during the same period, grew close to 6 percentage points from 21.5 to 27.1. Tamil Nadu has achieved a significant success in education, with the GER of 80 per cent in higher education, one of the highest in India. The State's progressive initiatives like the School Education Quality Index, the breakfast scheme, which is very close to the heart of the Chief Minister, the *Kaalai Unavu Sitrundi Thittam*, and our two-language policy have set benchmarks for the nation. The Breakfast Scheme, in particular, ensures that underprivileged students receive nutritious meal, improving their academic performances.

Sir, the GER of Tamil Nadu in Higher Education stands first in India as per the data of All India Survey of Higher Education. This is almost double the national average. Sir, the two language policy has promoted inclusivity by offering education in both Tamil and English.

Hon. Sir, Tamil Nadu was one of the first States to implement the Right to Education Act ensuring that children from all backgrounds have access to quality education. No matter what, when it comes to rational and logical initiatives, Tamil Nadu will adopt and implement the decisions as a State without any hesitation. This is how we have followed the family planning initiative and for that one reason, Tamil Nadu is getting penalized in the case of delimitation. At the same time, Sir, you can expect a denial if the policy decision is irrational, causing social injustice and is infringing upon the State's autonomy and the federal structure. Tamil Nadu is against the NEET, JEE and NEP as it is irrational, causing social injustice and is infringing upon the State's autonomy and the federal structure. Yet, Tamil Nadu is being forced to implement the BJP Government's flawed and irrational policies, causing social injustice and infringing upon the State's autonomy and the federal structure. The Minister and this Government should be regretful for pushing such policies to a State, which holds a long-standing legacy of social justice with a rational mindset, especially when it comes to education. The denial mindset of the hon. Minister, vendetta and diversion of funds allocated for development of educational infrastructure in Tamil Nadu to other States is disrupting key projects, including construction of classrooms, teachers' training and resource provision. These setbacks threaten the State's educational advancement, particularly in the rural areas.

Sir, I take this opportunity to clarify certain facts which have been going on for quite some time. Tamil Nadu has never accepted the NEP 2020 policy. I say it again, Tamil Nadu has never accepted the NEP 2020 policy. We had only promised to come back on this issue after scrutinizing the NEP policy with the Committee. In August 2024, the Government of Tamil Nadu, under the leadership of our Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, informed that we have scrutinized the NEP 2020 and found that since it was almost similar to the previous Navodaya School project, which was not implemented in Tamil Nadu, we were not keen on implementing the NEP 2020 policy in Tamil Nadu. Then, from where does the question that we had first accepted it and then declined it arise? I seriously do not understand this. This is ridiculous. The Tamil Nadu Government has been urging the Union Government not to withhold the release of funds under the ongoing *Samagra Siksha* scheme by linking it to the signing of MoU for the establishment of the PM-SHRI schools in Tamil Nadu as the State had some valid reservations to certain elements of the National Education Policy 2020. The

first clause of the proposal of the MoU for the PM-SHRI schools mandates that the States implement all provisions of the NEP. Many of the acceptable provisions of the NEP were being implemented in Tamil Nadu even before the launch of this NEP program and they were covered in the State's Education Policy. Linking the release of these funds to compliance with the PM-SHRI schemes undermines the State's autonomy, as granted by the Indian constitution, which places education in the Concurrent List. Furthermore, characterising the *Samagraha Siksha* as merely an extension of the NEP 2020 is misleading and fails to recognise the State's comprehensive educational framework and achievements. The release of funds for Tamil Nadu's education system is not just an administrative issue, but it is a matter of constitutional and federal importance. Under Article 21A, which was introduced by the 86th Amendment, the Indian Constitution guarantees right to education to all children between the ages of 6 and 14 as a fundamental right in such a manner as that the State may by law determine, I repeat, Sir, 'in such a manner as the State may by law determine'. This is a fundamental right of children as well as the State, and any actions that hinder the provision of the quality of education, infringe upon his right. In this context, withholding the funds allocated to Tamil Nadu for educational development is a direct infringement on the State's autonomy, sovereignty and the linguistic rights of Tamil Nadu. As a member of the Union of India, the State is entitled to equitable development and fair allocation of resources for the development of its educational infrastructure. By delaying the release of funds, the federal Government is not only undermining Tamil Nadu's educational progress, but also violating the principles of cooperative federalism that are meant to guide the relationship between the States and the Union. The delaying of funds affects the very essence of the federal structure of our country. The cooperative federalism framework, envisioned by the framers of our Constitution, was designed to ensure that all States have equal developmental opportunities, irrespective of geographic or political influence. When the funds meant for the State's development are delayed or withheld, it not only hampers the State's growth, but also destabilizes the balance of power that is an integral part of our federal system.

Sir, the Government of Tamil Nadu, under the leadership of our hon. Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, has reiterated that there would be no change in the two-language policy in Tamil Nadu, Tamil and English, which has been in force since 1968. Sir, I repeat, Tamil Nadu Government, under the leadership of Shri M.K. Stalin, has reiterated that there would be no change in its two-language policy of Tamil and English, which has been in force since 1968, from the times of our previous Chief

Minister, Annadurai. Tamil Nadu stands high and tall in educational achievement and it is mainly due to the strict adherence to the two-language policy only.

The people of Tamil Nadu have opposed the imposition of Hindi since 1930s, but the implementation of the two-language policy came into effect from 1968 when Perarignar Anna was the Chief Minister of Tamil Nadu. In the last 57 years, Tamil Nadu has achieved a remarkable success in education and is at par with many developed countries in the world. It will take two or three more decades for other populous States in the country to reach what Tamil Nadu has achieved right now. Though the NEP says that the third language could only be an Indian language, the State sees it as a ploy to impose Hindi through the back door. The three-language policy of NEP will be disadvantageous to the students from the poor and the marginalised population.

On 15th February, the Union Education Minister has told that the States like Tamil Nadu, which did not implement the NEP 2020, would not get funds under the Samagra Shiksha Abhiyan. This is not only ridiculous but it is unconstitutional too. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin, has asserted that Tamil Nadu would not succumb to the Centre's incessant pressure just to get the funds. Tamil Nadu has not opposed anyone learning Hindi, but we are only fighting against the imposition of that language. I repeat, Sir, Tamil Nadu has not opposed any one learning Hindi, but we are only fighting against the imposition of Hindi. All the major political parties in Tamil Nadu, except the BJP, support the continuation of the two-language policy. Therefore, I urge the Union Government not to be adamant on the three-language policy and refrain themselves from imposing Hindi and Sanskrit in Tamil Nadu.

Our great poet Thiruvalluvar had written a separate chapter Adhikaram, containing 10 couplets about the importance of good education 2,000 years ago. I am just quoting a couplet in Tamil by Thiruvalluvar, [&] "It means, "Learning is the true imperishable wealth. Other riches need not be considered as real wealth". Hence, the wealth which can never decline is not riches but it is learning. This has to be considered at this time. Education is the richness of the country and each child should get it. In Tamil Nadu, the two-language policy has been so well established and we have been competing with the developed countries, and our GER rate has been above the national average. So, we should consider the two-language policy which would take us globally to the next level.

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

I urge the hon. Education Minister to take immediate action to ensure that the funds allocated for Tamil Nadu's education system are released without any further delays. The disbursement of these funds is crucial for the completion of ongoing educational infrastructure projects and the successful implementation of educational reforms in the State. Moreover, the Union Government must re-affirm its commitment to co-operative federalism by ensuring that all the States, including Tamil Nadu, receive the financial resources they need to fulfill their educational mandates. This is not just a matter of financial aid, but it is about upholding the constitutional promise of the Right to Education to every child in India. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): The next speaker is Shri Sanjay Singh. You have 14 minutes.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया। सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं। आज जब हम लोग शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को याद करना बहुत आवश्यक है। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पीयेगा, उतना दहाड़ेगा। अगर भारत शिक्षित बनेगा, तभी विकसित बनेगा। शिक्षित भारत ही विकसित भारत बन सकता है। लेकिन वास्तव में इस शिक्षित भारत की सच्चाई क्या है? हो सकता है कि सरकार ने अपनी ओर से बड़े-बड़े दावे किए हों, बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की हों, लेकिन जमीन पर उसकी सच्चाई क्या है, यह आपके माध्यम से सरकार को और देश को जानना जरूरी है।

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके सामने पूरे देश में स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट का आंकड़ा रखना चाहता हूं। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में, 54 लाख, 77 हजार, 223 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। ये बच्चे कक्षा एक से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चे थे। अगर इसमें असम का आंकड़ा पढ़ें, तो 3 लाख, 58 हजार, 75 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है; गुजरात का अगर आंकड़ा पढ़ें, जिसके विकास के बारे में बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहाँ 1 लाख, 38 हजार, 813 बच्चों ने क्लास एक से क्लास आठवीं तक सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है; अगर आप मणिपुर की बात करें, तो वहाँ 17,991 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है; अगर आप मेघालय की बात करें, तो वहाँ 65,532 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है; अगर आप राजस्थान की बात करें, तो वहाँ 8 लाख, 99 हजार, 240 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ 7 लाख, 41 हजार, 626 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। ...**(व्यवधान)**... मैं जान रहा था कि हमारे भाई दिल्ली का आंकड़ा जरूर पूछेंगे, इसलिए दिल्ली का आंकड़ा बोलना जरूरी है। अगर आप दिल्ली का आंकड़ा देखें, तो दिल्ली में वर्ष 2022-23 और 2023-24 का मिलाकर इनका ही आंकड़ा है, सरकार का ही आंकड़ा है और मैं चाहता हूं कि हमारे साथी उसे पढ़ भी लेंगे, यहाँ 7,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। मान्यवर, ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, बहुत

परेशान करने वाले हैं और यह बताने वाले हैं कि सरकारी स्कूल से किस तरह से पूरे देश में शिक्षा छोड़-छोड़ कर बच्चे अपने घर पर बैठ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के बारे में जो मैंने आंकड़ा पढ़ा है, वह निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। इनको इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, दूसरा मामला पेपर लीक का आता है। पूरे देश में पेपर लीक की घटनाएं कितनी हुईं? पिछले सात वर्षों में 70 एग्जाम्स ऐसे हैं, 70 परीक्षाएं ऐसी हैं, जिनमें पेपर लीक हुए। मान्यवर, कितने परिश्रम के साथ एक बेरोजगार नौजवान एक कॉंस्टेबल की नौकरी की परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करता है। एक नौजवान अपने घर की जमीन बेच कर कितने परिश्रम से एक क्लर्क की नौकरी के लिए, एक पीसीएस-आईएएस की नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कहीं मेडिकल में दाखिला लेना हो, तो उसके एग्जाम में, नीट की परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, कहीं क्लर्क की, कॉंस्टेबल की नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहा है, तो उसका पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक की इन घटनाओं के लिए कोई राष्ट्रीय नीति या राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे पेपर लीक की घटना रोकी जा सके।

मैं अगर पेपर लीक से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या पढ़ूंगा, तो पूरे सदन को इसके बारे में अफसोस होना चाहिए। यह आपका आंकड़ा है कि 1 करोड़, 70 लाख हमारे बच्चे-बच्चियां, छात्र-छात्राएं, बेरोजगार नौजवान, इन पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। इसमें क्या घोटाला हुआ है? आप जिसको परीक्षा कराने का ठेका देते हैं - उत्तर प्रदेश में 69,000 कॉंस्टेबल्स की भर्ती के लिए आपने Edutest नाम की एक कंपनी को ठेका दिया। वह कंपनी विनीत आर्या नाम के व्यक्ति की है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गहरा रिश्ता है। इसमें यह पाया गया कि 69,000 कॉंस्टेबल्स की भर्ती में इस कंपनी ने पेपर लीक कराया, घोटाला किया, गड़बड़ी की, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया। जाँच एजेंसियों के सामने यह आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ और उसके बाद भी उसी कंपनी को बिहार में भी एग्ज़ाम कराने का ठेका दे दिया गया। यह आपका प्यार है! आपको छात्रों, नौजवानों के भविष्य से कोई लेना-देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों और अपने मित्रों को फायदा पहुँचाने का काम करना है। जो तीसरा आंकड़ा है, वह आपने अलग-अलग योजनाओं में जो खेल किया है, उससे संबंधित है। यह खेल समझना बहुत जरूरी है। आपने एससी-एसटी और ओबीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति देने, स्कॉलरशिप देने की एक स्कीम शुरू की। आपने उसका नाम 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम' रखा। इतना लंबा और भारी- भरकम नाम पढ़ कर आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है, जैसे प्रधान मंत्री जी एससी-एसटी और ओबीसी के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी कदम लेकर आए हैं। आपने इस योजना में क्या किया? इसमें हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और पीएचडी के जो एसटी-एससी और ओबीसी के छात्र हैं, उनको आप स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं। इसमें आपने 2023-24 में 98 करोड़ रुपया खर्च किया। आपने 2024-25 में इस स्कीम का बजट 1,558 करोड़ रुपए निर्धारित किया। यह बड़ी खुशी की बात है। 2023-24 में 98 करोड़ खर्च हुआ और आपने 2024-25 में इस स्कीम का बजट बढ़ा कर 1,558 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिया। फिर आप रिवाइज्ड बजट लेकर आते हैं। आपने संशोधित बजट में इस स्कीम के बजट को 1,558 करोड़ रुपए से घटा कर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया। आपने 2024-25 में ही इस स्कीम के बजट को घटा कर 1,000 करोड़

रुपए किया, यानी आपने इस स्कीम में एससी-एसटी और ओबीसी को मिलने वाली स्कॉलरशिप के पैसे को 35 परसेंट कम करने का काम किया।

आपकी दूसरी स्कीम, 'पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया', 'पीएम-श्री' स्कीम है। आप इसका भी बड़ा ढोल पीटते रहे। आपने 2023-24 में 'पीएम-श्री' स्कीम में 1,215 करोड़ रुपया खर्च किया। आपने 2024-25 में इस स्कीम के बजट के लिए 6,050 करोड़ रुपया निर्धारित कर दिया और जब आपने इसको बढ़ाया, तो यह प्रस्तुत किया कि हम 'पीएम-श्री' स्कीम में देश के स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, शानदार स्कूल बनाएंगे, इसलिए हमने इसका बजट बढ़ा कर 6,050 करोड़ रुपए कर दिया। फिर 2024-25 में ही आप इसके लिए रिवाइज्ड बजट लेकर आए और इसके बजट को 1,500 करोड़ रुपए घटा कर 4,500 करोड़ रुपए कर दिया, यानी आपने 'पीएम-श्री' स्कीम के बजट में करीब-करीब 25 परसेंट की कटौती कर दी। फिर 2025-26 में इसको 7,500 करोड़ रुपए कर दिया। आप एक और स्कीम, 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान' लेकर आए। आपने 2023-24 में इस स्कीम के तहत 186 करोड़ रुपया खर्च किया और 2024-25 में फिर इसको बढ़ा कर 815 करोड़ रुपए कर दिया, फिर इसी साल 2024-25 में आप रिवाइज्ड बजट लेकर आए, जिसमें आपने 920 करोड़ रुपए यानी करीब-करीब 50 परसेंट इस बजट का भी पैसा कम कर दिया। फिर इस स्कीम में 2025-26 के लिए 815 करोड़ रुपए, जो 2024-25 में किया था, वही कर दिया। आपने शिक्षा नीति के साथ, शिक्षा के लिए निर्धारित बजट के साथ कितना बढ़िया खेल किया! आप एक बार बजट निर्धारित करते हैं, फिर उसको संशोधित करते हैं और फिर वही बजट दोबारा अगले साल घोषित करते हैं। यह आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं? फिर आपका एक 'समग्र शिक्षा अभियान' है, जिसकी आजकल पूरे देश में बहुत चर्चा है। आपने 2023-24 में इस 'समग्र शिक्षा अभियान' के तहत 32,830 करोड़ रुपया खर्च किया और फिर 2024-25 में इसको बढ़ा कर 37,500 करोड़ रुपए कर दिया। आप फिर रिवाइज्ड बजट लेकर आए। आप हर बार रिवाइज्ड बजट लाते हैं और 2024-25 के लिए रिवाइज्ड बजट में आपने इस स्कीम का 490 करोड़ रुपया कम कर दिया, यानी आपने इसमें भी करीब 10 परसेंट पैसा कम कर दिया। अब आपने वर्ष 2025-26 में इसी स्कीम में 41,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।

सर, मिड डे मील की बहुत चर्चा होती है। "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण", इतना बड़ा-बड़ा और भारी-भारी नाम दिया जाता है कि आदमी को लगता है कि जैसे ही वह मिड डे मील स्कीम का नाम सुनेगा, तो प्रधान मंत्री का नाम सुनते ही उसके अंदर शक्ति आ जाएगी। सर, इस स्कीम की हकीकत सुनिए। इस स्कीम के अंदर आपने 8,458 करोड़ रुपया 2023-24 में खर्च किया, फिर 2024-25 में इसको बढ़ाकर 12,467 करोड़ रुपए किया, फिर इसी साल, 2024-25 में ही आप संशोधित बजट लेकर आए और इस स्कीम का पैसा 2,467 करोड़ रुपए घटा दिया। आप मिड डे मील का पैसा घटा रहे हैं! मिड डे मील के पैसे में आप कटौती कर रहे हैं! बच्चों के मिड डे मील का पैसा भी आप लोग पूरा नहीं देते और करीब 19 परसेंट पैसा आपने मिड डे मील का कम कर दिया। मेरा यह कहना है कि आज आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इतिहास के साथ भी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं।

सर, आजकल पूरे देश में औरंगजेब की बड़ी चर्चा चल रही है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी क्रूर मुगल शासक हैं, उनके बारे में इस देश के अंदर पढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ-साथ

अंग्रेजों ने जो 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना कर रखा, जो लोग जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार हैं, जो क्रूर अंग्रेज शासक शहीद-ए-आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद राजेंद्र लाहिड़ी, शहीद राम प्रसाद 'बिस्मिल', शहीद खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में भी, उनके शासनकाल के बारे में भी इतिहास के अंदर आप पढ़ाइए। लेकिन, जब आप उसको पढ़ाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन-सी वह संस्था थी, जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया। ...(**समय की घंटी**)... कौन-सी वह संस्था थी, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया? कौन-सी वह संस्था थी, जिसके नेता ने 1942 के आंदोलन में अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि वे कौन-से नेता थे, जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ तीन राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। यह सारा का सारा इतिहास हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए, जिससे हम मुगलों की क्रूरता के बारे में भी जान सकें और अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों का साथ देने वाले संगठन की सच्चाई भी इस देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI GOLLA BABURAO (Andhra Pradesh): Sir, at the outset, I thank our hon. former Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy, for giving me this opportunity to speak on the Discussion on the Working of the Ministry of Education. Every human being has two basic needs. One is primary healthcare and second is primary education. Let us discuss the education part. Not just in India but all over the world, the primary teacher to the child is the mother. Whatever a primary teacher teaches will have a lot of impact in the years to come. For example, Jijabai gave wonderful teachings to Chhatrapati Shivaji. Because of his mother, he became that much more powerful warrior in the Deccan field. In the same way, I want to impress upon the august House that primary education really does not have universalization. Now, the New Education Policy aims at universalization of education, cent percent literacy, new innovations, holistic development of students and teachers in India, etc. They may have achieved some good results, but there are so many changes that have to emerge in the New Education Policy, at least, in the future.

Now, I come to primary education which is most important. As far as my knowledge goes, unfortunately, privatization of primary education and secondary education is very high. Not only in Andhra Pradesh, but in entire India, it is so. How can you expect a poor man to send his children to private schools, spending thousands and lakhs of rupees? Is it possible in India? I want the hon. Education Minister to think of this most important problem. To send their children to schools, poor people are selling their lands; they are selling their ornaments; they are

borrowing thousands of rupees from their relatives and others. Ultimately, God knows if they come up in the life or not! But this is the pathetic situation going on in rural areas and urban areas. So, strengthening of primary education is most important. If the Government wants, it can strengthen Government schools, Zila Parishad high schools and elementary schools. Otherwise, we cannot achieve universalization of education. BJP Government wants Viksit Bharat by 2047. How can they achieve it? This type of plight is going on in India. What I want to impress upon the august House is, let us take stringent steps to curb privatization in secondary and primary levels.

Now, coming to secondary level, I will tell you my own example. Suppose I want to study in 7th, 8th, 9th or 10th class, do you know how far I have to go! It is, at least, ten miles in a State like Andhra Pradesh. How many people can go? There are no schools even today. Good teachers are not there. No teacher and student ratio is being followed. For that purpose only, our former Chief Minister of Andhra Pradesh took up a lot of wonderful and magnificent programmes like *Vidya Deevena, Vidya Kanuka, Vidya Vasathi*, etc. He spent Rs. 73,000 crore for secondary and primary education. You may not know, but 45,000 elementary and secondary schools were really developed like *Nandana Vanas*. Now, in many States, our Andhra Pradesh policy has been borrowed and they must have implemented it in other States also. What I want is that there should be an understanding of the education system.

Now, I come to collegiate education. Unfortunately, the so-called college managements have become only degree-issuing authorities. They are degree-issuing authorities; there are no standards, no teachers, no maintenance of curriculum, etc. This type of plight should be stopped. What I want is this. I want the hon. Education Minister to note these points. I am telling from my own side. In the entire rural India, so many lakhs and crores of poor people are suffering. What I want to impress upon now is that this collegiate education should be strengthened. If collegiate education is not strengthened, young students will become unemployed. They may become a waste material to the society, to the families also. So many people are becoming vagabonds. They are unable to achieve anything in their life. They cannot do anything in the rural areas or in the urban areas. That is why, even for university education, I want to really request the hon. Education Minister to give a direction to the University Grants Commission (UGC). What is it doing? What is the University Grants Commission doing so far? I want to question: how are they developing the collegiate education and the university education? Their role is not seen anywhere. I have seen in Andhra Pradesh. For my sake, I would like to tell you that I got only third class in B.Com. I did not get a seat in the entire Andhra Pradesh. I went to Jabalpur, Madhya Pradesh. I think, somebody may be from Jabalpur. I studied my post-graduation in

Jabalpur, Madhya Pradesh. After that, because of my strenuous efforts, my father's effort, my mother's effort, we could, at least, achieve the Group I services. Of course, I became an officer for 25 years. What I want is this. The basic need of the education system is to strengthen the entire Indian society, not only the society but mankind as a whole. Even from one side, I cannot blame the technical education side completely. There are so many improvements. IITs are there, NITs are there and IIMs are there. Their standards are very good. But I am very, very concerned about social sciences. Social sciences are completely neglected not just in Andhra Pradesh but in entire India. I can say that. What my wish is that a man who studied economics should become an economist. A man who studied history should become a historian. A man who studied commerce should become a CA. That type of serious education should be imparted especially in college education and at the PG level. At PG level, lecturers are there, readers are there and professors are there. Their salaries are more than Rs.3-4 lakh but they are teaching for only two to three hours in a week. That is the great contribution they are doing in Andhra Pradesh. I do not know about other States, but I know only about my State. That is why our former hon. Chief Minister took very stringent steps to develop medical education, engineering education, IIM and so many are there. He gave topmost priority for the education sector. ...(*Time-bell rings.*)... Sir, just one more minute and I would conclude. I want from the hon. Education Minister and the hon. Prime Minister — Rs.1,28,000 crores are allotted to education now — that equal riches and equality should be brought among all castes, all religions and all areas so that they can achieve *Viksit Bharat* by 2047. The opportunity given to me is very valuable and I thank you so much for this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): The next speaker is Shri Niranjan Bishi. You have ten minutes. Shri Niranjan Bishi, not present. The next speaker is Shri. Manoj Kumar Jha. You have seven minutes.

SHRI MANOJ KUMAR JHA (Bihar): *Vanakkam* hon. Vice-Chairman, Sir.

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो भूमिकाओं में खड़ा हूं - एक तो संसद में स्टेकहोल्डर की हैसियत से और दूसरी एक विश्वविद्यालय के शिक्षक की हैसियत से। मैं कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सरोकार बताऊँगा। महोदय, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मेरे ज़ेहन में अभी आया कि मैं ऐसी हिंदी कैसे बोलूं, जिसमें उर्दू न हो और ऐसी उर्दू कहाँ से लाऊँ, जिसमें हिंदी न हो। भाषाओं का जो मसला है, जो मानस में रचा बसा है, इन दिनों उसको लेकर कई चीज़ें चल रही हैं। हम तो संगम लिटरेचर पढ़कर बड़े हुए। हमने इतिहास में तमिल रिचनेस पढ़ी, संगम लिटरेचर पढ़ा।

सर, ओपनिंग रिमार्क दे रहा हूं कि हमने भाषा के विवाद में 1960 में बहुत कुछ गवाँ दिया। यह मुल्क साझा और बराबर की साइज की ईटों से बना है। किसी ईंट के साइज को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इमारत गिर जाएगी। यह इमारत बचाने का वक्त है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे संस्कृत हो, तमिल हो, बांगला हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो या हिंदी हो, भाषाएँ सरकार के प्रोत्साहन से नहीं बढ़ती हैं, भाषाएँ लोक माध्यम से बढ़ती हैं। अगर हिंदी भाषा बढ़ी है, तो लोक माध्यम से बढ़ी है, छोटे-छोटे गानों से बढ़ी है। यह हिंदी पखवाड़ा मनाने से नहीं बढ़ी है, फोर्टनाइट मनाने से नहीं बढ़ी है। सर, यह मेरी पहली बात थी, खैर, क्या कहूँ:

मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा,
उसको छुट्टी न मिली, जिसको सबक याद हुआ।

इन दिनों ये हालात कई सारी चीजों में हैं। मैं एक बात यह मानता हूं कि शायद हमारे दिग्विजय सिंह जी, हमारे सीनियर, एक लंबी लकीर खींच गए हैं, इसलिए, मैं चीज़ें दोहराऊंगा नहीं, महोदय, मैं सिर्फ चिंतित हूं। इससे पहले की एजुकेशन पॉलिसी का क्या हश्र था, मैं नहीं जानता, लेकिन इस सदन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर व्यापक चर्चा नहीं हुई है। सदन को इससे महरूम करना - क्या यह उचित है? मैं यह सवाल सदन के विवेक और सरकार के विवेक छोड़ता हूं।

सर, इस पूरे दस्तावेज में कई मिसमैच हैं। मैंने दस्तावेज की शक्ल और वैचारिक रुझान की पेडागोजी और टेक्नोलॉजी के मिसमैच की लैंग्वेज को लेकर एक बात कह दी है, उसी का थोड़ा खुलासा करता हूं। सर, मदर टंग वाली बात बहुत बेहतर है कि पांचवी पाँचवीं क्लास तक मदर टंग में शिक्षा दी जाए, लेकिन हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद करें, उनके वक्त में जो सच था, वह सच आज भी है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए अंग्रेज़ी एक भाषा है और हमें उसके प्रति भी दृष्टिकोण साफ करना होगा। सर, भाषाएँ किसी की बपौती नहीं होती हैं, भाषा लोक जीवन से उभरती है और लोक जीवन को समृद्ध करती हैं।

महोदय, अभी doubling the Gross Enrolment Ratio की बात हुई - 2035 तक संभवतः इस दस्तावेज में। मुझे उस पर ऐसा लगता है कि उस हिसाब से - अगर इसको अचीव करना है, तो प्रति सप्ताह 15 वर्ष तक नए विश्वविद्यालय खोलने होंगे।

सर, अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। मैं इस विषय पर संभवतः पचासों बार बोल चुका हूं। सर, एक चीज होती है - एनएफएस। यह एकलव्य ढूँढ़ने का नया तरीका हो गया है - 'none found suitable'. यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कमेटी कह रही है। The Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ने कहा है कि यह जो stereotypical response आता है कि सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले - यह बिल्कुल गलत है सर। कमेटी ने कहा कि यह एक्सेप्टेबल नहीं है। यही बात कमोबेश ओबीसी रिक्रूटमेंट में लागू होती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं, माननीय नेता सदन लगातार बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि यह महामारी सब कुछ लील जाएगी। यह मध्ययुगीन व्यवस्थाओं की महामारी है, जो आधुनिक चोला पहन चुकी है। इस चोले को उतरवा कर फिंकवा दीजिए, अन्यथा बहुत मुश्किल होगी।

महोदय, गुजरात बड़ा समृद्ध राज्य है। आज़ादी के बाद से ही हमेशा इस पर नज़र-ए-इनायत रही है, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे बिहार जैसा पिछड़ा राज्य भी गुजरात के साथ एक कैटेगरी में साथ-साथ है और वह कैटेगरी है Enrolment in Higher Education, जहाँ बिहार, असम, गुजरात भाई- भाई। बस यही एक चिंता का विषय था, मैंने कह दिया है और नीति आयोग की भी स्कूल एजुकेशन को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं।

महोदय, यदि मैं एकाध मिनट ले लूँ, तो आज माफ कर दीजिएगा। Please spare me one minute extra, if it is possible.

3.00 P.M.

सर, प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। आप एजुकेशन से क्या उम्मीद करते हैं? रीताब्रता जी ने जो palimpsest की बात कही थी, वह हमारा एक नजीर होना चाहिए। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैंने दसवीं कक्षा तक हिंदी मीडियम से पढ़ी। 11वीं में अंग्रेजी से पहली बार राब्ता हुआ और मुश्किल आई। Queen's language की अपनी दिक्कतें हैं। मैं अपने ही स्कूल को आज जब वापस जाकर देखता हूं, हमने क्या बनाकर रख दिया? मुझे निजी क्षेत्र के खिलाफ मत समझा जाए, लेकिन एक संतुलन होना चाहिए। दुनिया के तमाम उन देशों ने एजुकेशन और हेल्थ में सबसे अच्छा काम किया है, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ोतरी दी है, उसको प्रोटेक्ट किया है।

सर, मैं एनटीए के बारे में कई दफा बोल चुका हूं। ये कोचिंग इंस्टिट्यूट के दामाद - सर, दामाद शब्द असंसदीय तो नहीं है? मैं पहले ही पूछ लेता हूं, नहीं तो दूसरा शब्द प्रयोग करूंगा - हां, रिश्तेदार की तरह व्यवहार करना। कोचिंग इंस्टिट्यूट flourish कर रहे हैं। बार-बार परीक्षा पैटर्न, pedagogy, syllabus में बदलाव, हमने बच्चों को guinea pigs बना कर रख दिया है।

सर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं। नामांकन की पद्धति बदल गई है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब आठवीं, नौवीं क्लास से बच्चा स्कूल एजुकेशन को छोड़कर एनटीए की कोचिंग ले रहा है कि सीयूईटी क्वालिफाई करना है। यह स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ...(**समय की घंटी**)... सर, एक मिनट और दीजिए। शिक्षा के संस्थान वैचारिक युद्ध क्षेत्र हो गए हैं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। घनश्याम जी ने एक बात कही थी। सर, इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की कि वामपंथी रुझान - कांग्रेस के साथ पता नहीं क्या दिक्कत थी, उन्होंने वामपंथियों को तथाकथित - हालांकि उसमें मेरिट नहीं है। आज विश्वविद्यालय दक्षिण पंथी वैचारिकी का अड्डा बनते जा रहे हैं। आप कई चीजों को हटा रहे हैं। पीएचडी नहीं चाहिए, बिना पीएचडी के ले लो। ये एलिजिबिलिटी हटा दो। तब भी आपको उस रुझान के लोग नहीं मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षकों की स्वायत्तता में बहुत कमी हुई है। मैं प्रोन्नति के सवाल पर 100 चीजें कह सकता हूं। मैं अपॉइंटमेंट पर 100 चीजें कह सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि कैसे शिक्षक विक्टिमाइज हो रहे हैं। सर, एसईजेड की तर्ज पर नॉलेज पार्क बनाकर आपको यह सोचना होगा कि शिक्षा और इंडस्ट्री में थोड़ा फर्क है। इसको उद्योग और सिर्फ निवेश की नजर से मत देखिए, क्योंकि इसका पहले नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था। भले नाम बदल गया हो, लेकिन उस संकेत को याद रखा जाए। केन्द्रीयकरण आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब बड़ी सत्ता आती है, तो हर किसी को लगता है कि इसको भी

मुझको हथिया लेना चाहिए। NAAC के बारे में विस्तार से हमारे दिग्विजय सिंह जी बोल चुके हैं। ऐसे लोग आप बिठाते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। सर, NAAC में क्या होता है - मैंने भी अपने टाइम में अपने विश्वविद्यालय में एक NAAC देखा है। मैं बता नहीं सकता हूं कि एकदम जैसे शादी ब्याह में रिश्तेदारी में जाने पर वह जो गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, वे सारी चीजें होती हैं और कई विसंगतियों के बावजूद उस संस्थान को 'A+' या 'A' मिल जाता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि आप रिविजिट करिए। शिक्षा मंत्री और रेल मंत्री का काम इस देश में सबसे डिफिकल्ट है। आप एक महत्त्वपूर्ण पद पर हैं। मैं आपसे कहूंगा, आपकी सरकार नहीं होगी, लेकिन इस नीति का प्रभाव रहेगा। इसलिए हम सब कोशिश करें और ऐसी व्यवस्था विकसित करें जहां खुले मन से बोलने के लिए कोई बंद न कर दिया जाए। सर, डेमोक्रेसी की एक परिभाषा है। "True democracy is one where you are not closed for being open." ...(**समय की घंटी**)... सर, आखिरी 30 सेकंड और दीजिए।

सर, मैं एक और चीज कहूंगा। संजय जी कह कर चले गए। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। कभी मुगल सल्तनत और अन्य रूलर्स पर बहस होगी, तब मैं विस्तार से बोलूंगा, लेकिन आज एक टिप्पणी करना चाहता हूं। सर, इतिहास के बासी पन्नों में जाकर अगर हम आज की चुनौतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, उन बासी पन्नों के नायक और खलनायक आपकी चुनौतियों में आपकी मदद नहीं करेंगे। अद्भुत विसंगति है कि औरंगजेब पर टिप्पणी तो सदन से बाहर और महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन तो सदन के अंदर।

सर, आखिरी में मैं यही कहूँगा कि ...(**व्यवधान**)... सर, यह उनको समर्पित, जिन्होंने उर्दू पर ...(**व्यवधान**)... कुछ अल्फाज़ पेश किए थे। ...(**व्यवधान**)...

"सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं,
मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ।"

जय हिन्द, सर!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): The next speaker is Shri Javed Ali Khan. You have three minutes to speak.

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, समय बहुत कम है, इसलिए मैं भाषण की शक्ल में अपनी बात नहीं कहूँगा, न ही कोई गैर-जरूरी टिप्पणियाँ करूँगा। नई एजुकेशन पॉलिसी, 2020 जब से लागू हुई है, इस पॉलिसी के बारे में यह भी कहा गया कि इस पर जितने व्यापक विचार-विमर्श की अपेक्षा थी, वह नहीं हो पाई थी। जब करीब 500 पेज का इसका ड्राफ्ट बना था, तो उस पर तो लोगों की राय माँगी गई थी, लेकिन जब इसका 60-65 पेज का फाइनल ड्राफ्ट बना, उस वक्त किसी से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। राज्यों से भी विचार-विमर्श नहीं किया गया, शिक्षाविदों से भी विचार-विमर्श नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो एक बहुत पुरानी संस्था है, जो अंग्रेजों के जमाने की है - Central Advisory Board of Education, समय समय पर जिसकी बैठकें होती थीं, लेकिन New Education Policy बनने से पहले से उसकी कोई

बैठक नहीं हुई और बाद में भी कोई बैठक नहीं हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे confusions, -- भाषा के संबंध में, दाखिलों के संबंध में, नियुक्तियों की प्रक्रिया के संबंध में -- वे रह गए, जिनका कोई हल नहीं निकल पा रहा है और यूजीसी को higher education में New Education Policy बनने के बाद करीब तीन दर्जन regulations समय-समय पर एक-दूसरे को contradict करते हुए जारी करने पड़े हैं। सर, higher education की स्थिति यह है कि New Education Policy में एक कमीशन बनाने की बात कही गई थी कि सारी संस्थाओं को merge करके एक Higher Education Commission बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। कुछ साल पहले उसका एक ड्राफ्ट जरूर circulate हुआ था, लेकिन उसमें क्या प्रगति है, यह शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहिए, जब वे जवाब दें।

सर, पिछले कई बजटों में देश के साथ एक बहुत बड़ी commitment की गई है और आम तौर पर एक माँग रही है कि जीडीपी का 6 प्रतिशत हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे, लेकिन आज हम 2.7 प्रतिशत भी पूरे तरीके से खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए 6 प्रतिशत का जो संकल्प पिछले बजटों में कहा गया था, उस दिशा में क्या स्थिति है, यह बात भी शिक्षा मंत्री जी को बतानी चाहिए।

सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थाएँ हैं, उनमें बहुत बुरी स्थिति है। अध्यापन कार्य में या नियुक्तियों में हम पूरी नियुक्तियाँ नहीं कर पा रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केंद्र सरकार की दूसरी संस्थाओं में करीब 33 प्रतिशत vacancies हैं। उसका सीधा असर आरक्षण पर पड़ रहा है। SC/ST/OBC का आरक्षण भी हम पूरे तरीके से नहीं भर पा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 9 परसेंट SCs, 3 परसेंट STs और 14 परसेंट OBCs हैं। जो बहुत ही favourite category ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं एक मिनट और लूँगा। हमारी सरकार की जो बहुत ही favourite category थी - Economically Weaker Section, उसका quota भी हम पूरे तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

सर, मैं दो बातें सिर्फ school education के बारे में कहना चाहूँगा। Primary education की स्थिति तो यह है कि सरकारी स्कूलों से जो drop outs होते हैं, वे घर ही नहीं बैठते, बल्कि बहुत से लोग सरकारी स्कूल छोड़ कर निजी स्कूलों में जाते हैं। आज हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल तो बंद होने के कगार पर हैं और निजी स्कूल गली-मोहल्लों में खुलते चले जा रहे हैं। उसके अंदर छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सर, इसका कारण क्या है? मैं एक कारण बताना चाहता हूं कि क्यों लोग प्राइमरी सरकारी स्कूलों से विमुख हो रहे हैं और निजी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। चूंकि प्राइमरी सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाई के अलावा करीब-करीब 32 ऐसे कार्य करने होते हैं, जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। वे BLO की ड्यूटी करेंगे; चुनाव की ड्यूटी करेंगे; कहीं राशन बट रहा है या नहीं बट रहा है, इस बात का सुपरवीजन करेंगे; पल्स पोलियो का काम करेंगे; बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी देंगे; प्रतियोगी परीक्षाओं में ड्यूटी देंगे। वे राशन कार्डों का सत्यापन भी करते हैं; मिड डे मील का सुपरवीजन भी करते हैं; जनगणना भी वही करते हैं; पशु गणना भी वही करते हैं; बाल गणना भी वही करते हैं और वृक्षारोपण भी वही करते हैं। इस प्रकार के 32 प्रकार के काम हैं। जब ये सारे काम सरकारी स्कूलों के अध्यापक करेंगे, तो वे किस वक्त पढ़ाएंगे? इसीलिए लोग प्राइमरी सरकारी स्कूलों को छोड़ कर के निजी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं।

मैं आखिरी बात पीएम पोषण शक्ति निर्माण पर कहना चाहता हूं। पहले जिसे हम मिड डे मील कहते थे, ...(**समय की घंटी**)... आज की तारीख में उस पर हम 6 रुपये 19 पैसे प्रति छात्र खर्च करते हैं। दिसंबर तक यह खर्च 4 रुपये 97 पैसे था। इससे भी बुरी हालत यह है कि जो रसोइया भोजन बनाते हैं, जो महिलाएं रसोइये का काम करती हैं, उन्हें हम मात्र 2,000 का वेतन देते हैं, मानदेय देते हैं।

†**جناب جاوید علی خان) اترپردیش** :(اُپ سبھادھیکش جی، وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بھاشن کی شکل میں اپنی بات نہیں کہوں گا، نہ ہی کوئی غیر ضروری ٹِپّنیا کرونگا۔ نئی ایجوکیشن پالیسی، 2020 جب سے لاگو ہوئی ہے، اس پالیسی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس پر جتنے ویاپت وچار وِمرش کی اپیکشا تھی، وہ نہیں ہوپائی تھی۔ جب قریب پانچ سو صفحات کا اس کا ڈرافٹ بنا تھا، تو اس پر تو لوگوں کی رائے مانگی گئی تھی، لیکن جب اس کا 60-65پیج کا فائنل ڈرافٹ بنا، اس وقت کسی سے کوئی وِچار وِمرش نہیں کیا گیا۔ راجیوں سے بھی وچار ومرش نہیں کیا گیا، شکشاودوں سے بھی وچار ومرش نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ جو ایک بہت پرانی سنستھا ہے، جو انگریزوں کے زمانے کی ہے، Central Advisory Board of Education وقت وقت پر جس کی بیٹھکیں ہوتی تھیں، لیکن نئی ایجوکیشن پالیسی بننے سے پہلے سے اس کی کوئی بیٹھیک نہیں ہوئی اور بعد میں بھی کوئی بیٹھک نہیں ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے کنفیوژنس، بھاشا کے سمبندھ میں، داخلوں کے سمبندھ میں، نیوکتیوں کی پرکریا کے سمبندھ میں وہ رہ گئے، جن کا کوئی حال نہیں نکل پارہا ہے اور یوجی سی ہائر ایجوکیشن میں نئی ایجوکیشن پالیسی بننے کے بعد قریب تین درجن ریگولیشن وقت وقت پر ایک دوسرے کو contradict کرتے ہوئے جاری کرنے پڑے ہیں۔ سر، ہائر ایجوکیشن کی حالت یہ ہے کہ نئی ایجوکیشن پالیسی میں ایک کمیشن بنانے کی بات کہی گئی تھی کہ ساری سنستھاؤں کو مرج کرکے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کی دشا میں کوئی خاص پرگتی نہیں ہوئی ہے۔ کچھ سال پہلے اس کا ایک ڈرافٹ ضرور سرکولیٹ ہوا تھا، لیکن اس میں کیا پرگتی ہے، یہ شکشا منتری جی کو بتانا چاہیے، جب وہ جواب دیں۔

سر، پچھلے کئی بجٹوں میں دیش کے ساتھ ایک بہت بڑی کمٹمینٹ کی گئی ہے اور عام طور پر ایک مانگ رہی ہے کہ جی ڈی پی کا چھ فیصد ہم شکشا کے شیتر میں خرچ کریں گے، لیکن آج ہم 2.7 فیصد بھی پوری طریقے سے خرچ نہیں کرپاتے ہیں۔ اس لیے چھ فیصد کا جو سنکلپ پچھلے بجٹوں میں کیا گیا تھا، اس دِشا میں کیا استھتی ہے، یہ بات بھی شکشا منتری جی کو بتانی چاہیئے۔

سر، سینٹرل یونیورسٹی اور سینٹر گورنمنٹ کی جو سنستھائیں ہیں، ان میں بہت بری حالت ہے۔ ادھیاپت کارئیے میں یا تقرریوں میں ہم پوری تقرریاں نہیں کرپارہے ہیں۔ سینٹرل یونیورسٹی اور مرکزی سرکار کی دوسری سنستھاؤں میں قریب 33 فیصد ویکنسیز ہیں۔ اس کا سیدھا اثر آرکشن پر پڑرہا ہے۔ ایس ٹی، ایس سی، اوبی سی کا آرکشن بھی ہم پورے طریقے سے نہیں کرپارہے ہیں۔ سینٹرل یونیورسٹیوں میں نو فیصد ایس سی، تین فیصد ایس ٹی اور چودہ فیصد او بی سی ہیں۔ جو بہت ہی favourite category (--- **وقت کی گھنٹی**---) سر، میں ایک منٹ اور لونگا۔ ہماری سرکار کی جو بہت ہی favourite category تھی Economically Weaker Section اس کا کوٹہ بھی ہم پورے طریقے سے پورا نہیں کارپا رہے ہیں۔

سر، میں دو باتیں صرف اسکول ایجوکیشن کے بارے میں کہنا چاہونگا۔ پرائمری ایجوکیشن کی حالت تو یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں سے جو ڈراپ آوٹ ہوتے ہیں، وہ گھر ہی نہیں بیٹھتے، بلکہ بہت سے لوگ سرکای اسکول چھوڑ کر پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکول تو بند ہونے کے کگار پر ہیں اور پرائیویٹ اسکول گلی محلوں میں کھلتے جارہے ہیں۔ اس کے اندر چھاتروں کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔

سر، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں لوگ پرائمری سرکاری اسکولوں سے وِموکھ ہورہے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کی طرف جارہے ہیں۔ چونکہ پرائمری سرکاری اسکولوں میں جو ٹیچر پڑھاتے ہیں، انہیں پڑھائی کے علاوہ قریب قریب 32 ایسے کام کرنے ہوتے ہیں، جن کا تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وہ بی ایل او کی ڈیوٹی کریں گے، چناؤ کی ڈیوٹی کریں گے، کہیں راشن بٹ رہا ہے یا نہیں بٹ رہا ہے، اس بات کا سپرویزن کریں گے، اور پولیو کا کام کریں گے، بورڈ کے امتحان میں ڈیوٹی دیں گے، پرتی یوگی امتحانات میں ڈیوٹی دیں گے۔ وہ راشن کارڈوں کا ستیاپن بھی کرتے ہیں۔ مڈ ڈے میل کا سپرویژن بھی کرتے ہیں۔

† Transliteration in Urdu script.

مردم شماری بھی وہی کرتے ہیں، پشوگننا بھی وہی کرتے ہیں بال گننا بھی وہی کرتے ہیں، اور ورکش روپن بھی وہی کرتے ہیں۔ اس طرح 32 طرح کے کام ہیں۔ جب یہ سارے کام سرکاری اسکولوں کے ادھیاپک کریں گے، تو وہ کس وقت پڑھائیں گے؟ اس لیے لوگ پرائمری سرکاری اسکولوں کو چھوڑ کر کے پرائیویٹ اسکولوں کی طرف جارہے ہیں۔

میں آخری بات میں پی ایم پوشن شکتی نرمان پر کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے جسے ہم مِڈ ڈے میل کہتے تھے، **---)وقت کی گھنٹی(---** آج کی تاریخ میں اس پر ہم چھ روپے انیس پیسے فی طالب علم خرچ کرتے ہیں۔ دسمبر تک یہ خرچ چار روپے ستانوے پیسے تھا۔ اس سے بھی بری حالت یہ ہے کہ جو رسوئیا بھوجن بناتے ہیں، جو مہیلائیں رسوئیے کا کام کرتی ہیں، انہیں ہم صرف دو ہزار کا ویتن دیتے ہیں، مان دیتے ہیں۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्री जावेद अली खान: सर, मानदेय, वेतन नहीं देने का बहाना है। ये 'मानदेय' नाम जो गढ़ा गया है। उसे वेतन नहीं देना पड़े, इसलिए उसको 'मानदेय' कहते हैं। पूरे दिन एक रसोइया स्कूल में काम करता है, 50 बच्चों का खाना बनाता है और किसी सरकारी स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता, तो उसके अंदर सफाई भी उससे करवाते हैं और उसे सिर्फ 2,000 रुपये देते हैं।

†**جناب جاوید علی خان** : سر، مان دئے، ویتن نہیں دینے کا بہانہ ہے۔ یہ مان دئے، نام جو گڑھا گیا ہے۔ اسے ویتن نہیں دینا پڑے، اس لیے اس کو مان دئے کہتے ہیں۔ پورے دن ایک رسوئیا اسکول میں کام کرتا ہے، پچاس بچوں کا کھانا بناتا ہے اور کسی سرکاری اسکول میں کوئی صفائی کرمچاری نہیں ہوتا، تو اس کے اندر صفائی بھی اس سے کرواتے ہیں اور اسے صرف دو ہزار روپے دیتے ہیں۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्री जावेद अली खान: सर, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि स्कूलों में जो महिलाएं मिड डे मील बनाती हैं, जो रसोइये हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और उन्हें 2,000 रुपये की बजाय उन्हें कम से कम 10,000 रुपये दिए जाएँ।

सर, मैं आखिरी बात पीएम श्री विद्यालय पर कह देता हूँ। बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि पीएम श्री विद्यालय होगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। ...(**समय की घंटी**)...

†**جناب جاوید علی خان** : سر، میں شکشا منتری جی سے یہ مانگ کرنا چاہونگا کہ اسکولوں میں جو مہیلائیں مِڈ ڈے میل بناتی ہیں، جو رسوئیے ہیں، ان کی تنخواہ بڑھائی جائے اور انہیں دو ہزار روپے کی بجائے انہیں کم سے کم دس ہزار روپے دئیے جائیں۔

سر، میں آخری بات پی ایم شری ودیالیہ پر کہہ دیتا ہوں۔ بہت ڈھنڈورا پیٹا جارہا ہے کہ پی ایم شری ودیالیہ ہوگا۔ میں اپنا تجربہ بتارہا ہوں۔ **---)وقت کی گھنٹی(---**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्री जावेद अली खान: सर, आखिरी 30 सेकंड। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरे जिले के बड़े अधिकारियों ने मुझसे कहा कि पीएम श्री के अंदर कुछ सोलराइजेशन का काम करना है, तो आप

† Transliteration in Urdu script.

अपनी निधि से वहाँ सोलर लाइटें दे दीजिए, वहाँ वाटर कूलर्स और आरओ के प्लांट्स लगने हैं, वे दे दीजिए। MLAs से मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब यह एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, प्रधान मंत्री के नाम पर है, तो इसमें सांसदों से और विधायकों से किसलिए निधि मांगी जा रही है। इसे तो सरकार को priority पर करना चाहिए था। इस प्रकार, आज ऐसी स्थिति है कि पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, वह अधर में लटकी हुई है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी कृपा होगी कि शिक्षा को गंभीरता से लीजिए और शिक्षा नीति को सही तरीके से अमल में लाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

†**جناب جاوید علی خان :** سر، آخری تیس سیکنڈ۔ مانیئے شکشا منتری جی، میرے ضلع کے بڑے ادھیکاریوں نے مجھ سے کہا کہ پی ایم شری کے اندر کچھ سولرائیزیشن کا کام کرنا ہے، تو آپ اپنی ندھی سے وہاں سولر لائٹیں دے دیجیئے، وہاں واٹر کولرس اور آر او کے پلانٹس لگنے ہیں، وہ دے دیجیئے۔ ایم ایل ایز سے مانگ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب یہ ایک مہتوکانشی پروگرام ہے، پردھان منتری کے نام پر ہے، تو اس میں سانسدوں سے اور ودھایکوں سے کس لیے نِدھی مانگی جارہی ہے۔ اسے تو سرکار کو priority پر کرنا چاہیئے تھا۔ اس طرح، آج ایسی حالت ہے کہ پوری کی پوری جو شکشا ویوستھا ہے، وہ ادھر میں لٹکی ہوئی ہے۔

میں مانیئے شکشا منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ شکشا کو گمبھیرتا سے لیجیئے اور شکشا نیتی کو سہی طریقے سے عمل میں لائیے۔ بہت بہت شکریہ۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Now, Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara. The hon. Member will speak in Gujarati.

SHRIMATI RAMILABEN BECHARBHAI BARA (Gujarat): &"Thank you, Vice Chairman Sir. Hon. Finance Minister of India, Smt. Nirmala Sitharaman, has presented the Union Budget for the financial year 2025-2026. Indeed she is the pride of the women of India. Various provisions pertaining to the field of education have been made in the Union Budget. I would like to present my views pertaining to these provisions and I also congratulate the hon. Prime Minister of India Shri Narendrabhai Modi and the hon.Finance Minister of India, Smt. Nirmala Sitharaman for presenting a revolutionary budget.

Hon'ble Vice Chairman Sir, Comprehensive Educational reforms have been envisaged in the present Budget and appropriate provisions have also been made in this regard. Requisite provisions have been made in the Union Budget so as to strengthen the foundations of education in our country. The Modi Government came to power in 2014 and since then we are witnessing reforms in various sectors. We are also witnessing enhanced allocation of funds under various heads year after year. And due to this, the most deprived persons of our country are being benefited. Every child who deserves to be educated is being educated. Sir, all of us know, "विद्याविहीनः

---

† Transliteration in Urdu script.

& English translation of the original speech delivered in Gujarati.

पशुः", a person without education is like an animal. Life without education is useless. After our country gained independence, the framer of the Constitution of India, Dr. Babasaheb Ambedkar said, 'every individual of this country should receive education'. All eminent educationists had also said that everyone should have an access to education. But after India became independent, the country was led by the persons who focused only on vote bank politics. They kept the people from the SC, ST and Backward communities deprived of education. Sir, I belong to the tribal community and I know it well. But it is the good fortune of our country and its people that in 2014 Narendrabhai came to power and he gave the slogan of "Beti Padhao - Educate the girl child". He was really concerned about the education of girl children. When he was the Chief Minister of Gujarat, he approached the people of Gujarat with the Kanya Kelavani Rath (Girl Child Education Chariot) and asked for alms. He told the people of Gujarat, "I want alms. And what do I want as alms! I don't want money. I want your girl child to be educated. This is what I want as alms." The people of Gujarat accepted his request.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.*]

The BJP is in power in Gujarat since last 30 years. And none of the children, boy or girl, born during the reign of the BJP is illiterate.

While initiating the Discussion on the Working of the Ministry of Education, Shri Digvijaya Singh raised the issue of dropout ratio. He was quoting the figures of illiteracy in our country. Sir, if we should consider the literacy rate in the tribal areas of our country for the past years, during the past years, Children did not go to schools. When such was the situation, what is there to talk about the dropout ratio? During the Congress regime, the schools weere in dilapidated condition. Even if the schools were there, there were no children to take education. And even if there were children who wished to pursue education, there were no teachers. Just now my colleagues from the opposition were criticizing the process of recruitment of teachers for school education. I would humbly request and ask them to re-visit the past. What was the condition of the schools in the past? What was the condition of the students seeking education in the past? What was the condition of classrooms in the past? Under the leadership of hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, provisions pertaining to the implementation of the New Education policy 2020 have been made in the Union Budget for the year 2025- 26. Separate allocations have been made in this regard. Special provisions have been made to strengthen the basic infrastructure in the field of education, implementation of the New Education policy and Skill

Development of the youth of India. Considering the requirements of the contemporary times, requisite provisions have been made in the union budget. The Digital Young India program has also been launched. Today there is a demand for skill education and development. And henceforth, a provision for imparting training for the skill development of 2 crore youth has been made in the Union budget for the financial year 2025-26. This would ensure that, we have skilled youth who can cater to the needs of jobs of contemporary times. The opposition does not have any right to talk about jobs and unemployment because they have never been concerned about the youth of this country and the tribal population of this country. Today, we see a huge gap in the quality of education imparted in the schools of rural India, Government schools and the private schools of urban India. The hon. Prime Minister of India and the hon. Minister of Education are putting in sincere efforts to reduce this gap and eliminate this gap. Henceforth, the classrooms of the schools of rural India are being transformed to smart classes. In the Union budget for the financial year 2025-26, a provision has been made to convert 10,000 classrooms of the schools of rural India to smart classrooms. With an aim to foster scientific temperament amongst the school children of India, there is a proposal to established Atal Tinkering laboratories.

Sir, I belong to Gujarat. The entire stretch between Ambaji and Umbergaon has a dense tribal population. Nearly 1 crore tribal people reside in this area. In the past, during the regime of the Congress, what was the condition of education of the tribal population residing in this area? Thereafter, Narendrabhai Modi became the Chief Minister of Gujarat and Gujarat had a double engine Government. Today, we can see radical changes in Gujarat. During the rule of the Congress, there were only 13 Universities. Today, during the BJP regime, this number has gone up to 105. With a great pride, I am saying this. Tribal universities have been established in the tribal areas of Gujarat. Science colleges have been established in the tribal areas. Medical colleges have established in the tribal areas. How many seats for medical education were there in the past? In the past, there were only 550 medical seats. As a resultm students had to go to other States to acquire medical education. Students had to go abroad to get medical education. There was a huge revenue loss because when the students went abroad to acquire medical education, they had to pay fees to the colleges of foreign countries. Parents were worried about their children. Today, there are 6500 seats in the field of medical education. Not only this, requisite provisions have been made in the Budget so as to establish a medical college in every district of the country. There is a target to have 75,000 seats for medical education in the country. Sir, if the target of 75000 medical seats is achieved, no student of India will have to go abroad to acquire medical education. Because of this provision, the

country is going to be benefited a lot in the future. In addition to this, 500 new ITIs will be established so as to enhance the skills of the youth of this country. Just now, we were talking about IITs. The Bhartiya Janata Party is in power since 2014. Hon. Narendrabhai Modi is leading the country since 2014. And during the regime of Shri Narendrabhai Modi, 8 IITs have been established. No doubt, two IITs have been upgraded and 6 new IITs have been established, that makes it a total of 8 IITs. This has benefited the youth of this country. Sir, today Gujarat has become the hub of education in India. There is a double engine government in Gujarat. Young men and women from all over the world come to Gujarat to acquire education. Today, Kamdhenu University, Sanskrit University, Children's Research University, Forensic laboratory University, Gati Shakti University etc. are functioning in Gujarat. Yesterday, hon. Minister of Railways was saying that that there is a requirement for Technical Universities to impart technical education. A Railway University has also been established in Gujarat. Today, we are talking about leadership skills amongst youth, we are talking about cultural values amongst youth. Hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, has taken an initiative to establish a School of Ultimate Leadership. The objective behind this is to enhance leadership skills amongst the youth of the country and develop cultural values. This has started in Gujarat. In addition to this, many new Universities and educational institutions are coming up in Gujarat.

Sir, I come from a tribal area. I wish to throw some light on the initiatives taken in the field of Education in Gujarat. The area between Amirgarh and Umargaon, predominantly, has a tribal population. During the past years, nobody sent girl children to schools. Due to the efforts made by the hon. Prime Minister of India, every girl child in this area is acquiring education and, due to the efforts of the BJP Government, girls of tribal areas are working in various sectors. Girls are not only serving in the civil sector but are also working in defence sector. Many girls have become pilots. Sir, I would like to narrate an incident which depicts how much affection the hon. Prime Minister of India Shri Narendrabhai, has for the people of the SC, ST and backward communities. Whenever Narendrabhai Modi used to fly in a helicopter in rural areas and whenever the helicopter flew and landed in rural areas, people used to gather to see the helicopter. During one such incident, the hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi had said, "I want to see this youth of my country flying helicopter. I want to see my tribal sons and daughters flying helicopters." And, henceforth, he started a scheme so as to encourage the youth from Dalit, Tribal and backward communities to become pilots. And because of his farsightedness, youth from SC, ST and backward communities of Gujarat have today

become pilots and are flying in the skies. Also, due to the efforts of the BJP Government and the double engine Governments, today, 105 Eklavya model schools, Girls Literacy Residential Schools and Eklavya Model Residential Schools are functioning. In this way, 35,763 young boys and girls are acquiring education in these residential institutions. Good quality boarding and lodging facilities are being provided in these institutions. 50% of the students acquiring education in these institutions are girl children. Sir, I would like to draw your kind attention towards the fact that the last year pass outs from these institutions have secured admission in respectable institutions of higher education. Out of these students, 26 students have secured admission in the MBBS course, 32 students have secured admission in BHMS course, three students have secured admission in BAMS course, three students have secured admission in BDS course, 32 students have secured admission in pharmaceutical courses, 94 students have secured admission in BE courses and 244 students have secured admission in nursing courses. This comprehensive development is being witnessed amongst the tribal students because of the educational reforms of this Government. In addition to this, SAMRAS Hostels have been established in Gujarat. The objective behind establishing these hostels is to build a harmonious environment wherein the students from different communities come together, study together, and exchange ideas. The Government is working for the development of the youth. Mr. Vice Chairman Sir, the future of a nation depends on its Education Policy. The hon. Prime Minister of India understands this very well. The New Education Policy is really a praiseworthy initiative. Henceforth, emphasis has been laid on Education through Mother Tongue. Today, if we analyse the results of the UPSC examinations, the results of the Competitive Examinations of various States, it becomes clear that the aspirants have developed a sense of self-confidence because of the liberty of the usage of Mother Tongue in these examinations. This has contributed to better results and is definitely a praiseworthy step. Sir, the aspects of Skill Development, Strengthening of Infrastructure in the field of Education and enhancing the capabilities of the youth, as envisaged in the New Education Policy, are really commendable and good work is being done in the field of education in Gujarat.

At last, I would like to mention that we should rise above our differences and should respect the sentiments of our hon. Prime Minister, who is marching towards the goal of a Developed India 2047, and walk with him hand-in-hand. Let us work together with an objective to make every child of this country educated. It is said, “It cannot be stolen by thieves, nor can it be taken away by kings.” It cannot be divided among brothers and It does not cause a load on your shoulders. If spent, it indeed

always keeps growing. The wealth of knowledge is the most superior wealth of all.Thus, let us all work together to educated the children who are deprived of educations, who are poor and who belong to backward areas. Hon. Prime Minister and Hon. Education Minister are working hard in this regard. Let us all consider this our responsibility and appreciate this New Education Policy and co-operate in its implementation. And let us ensure that every child of this country goes to school and studies well. Thank you very much.

Jay Jay Garvi Gujarat, Jay Jay Garvi Gujarat
Victory to proud Gujarat, Victory to proud Gujarat!

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (महाराष्ट्र)ः उपसभाध्यक्ष महोदयः

'भूख के एहसास को शेरो- सुख़न तक ले चलो,
या अदब को मुफ़लिसों की अंजुमन तक ले चलो,
मुझको नज़्मों- ज़ब्त की तालीम देना बाद में,
पहले अपनी रहबरी को आचरन तक ले चलो।'

सर, मैं New Education Policy पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं। New Education Policy कहती है कि हमारा ज़ोर टीचर्स ट्रेनिंग पर होना चाहिए, लेकिन National Sample Survey Office का आंकड़ा कहता है कि इस देश में सिर्फ 13 परसेंट टीचर्स ट्रेन्ड हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 87 परसेंट टीचर्स हैं, जिनको अभी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्या उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास कोई रोडमैप है? हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर कॉलेजेज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं, जिनसे उन्हें ट्रेन किया जा सके। हमारी New Education Policy कहती है कि technology पर ज़ोर दिया जाए। हमने कोविड के दौरान भी देखा है कि किस तरह से बच्चों को technology के सहारे पढ़ाया गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में 80 करोड़ लोग पांच किलो राशन पर गुजारा कर रहे हों, तो क्या उन परिवारों तक इंटरनेट, कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोई रोडमैप है, ताकि उनके बच्चों को शिक्षित किया जा सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। Minority community से जुड़ा हुआ जो मदरसा एजुकेशन का पैटर्न है, तो मैं माननीय मंत्री जी से उस पर बहुत गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि New Education Policy है, उसमें कुछ मदरसे ऐसे हैं, जिनको सरकार recognize करती है, लेकिन कुछ बड़े शिक्षण संस्थान जैसे नदवा और देवबंद हैं, तो क्या New Education Policy के कॉन्टेक्स्ट में आपने इन बड़े संस्थानों से डॉयलॉग करने का कोई मानक या बातचीत शुरू करने का प्लान बनाया है? मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे minority institute थे, जहां पर स्कॉलरशिप का प्रावधान था, लेकिन आपने Maulana Azad National Fellowship को एक झटके

में बंद कर दिया। जिसमें हजारों-लाखों छात्र, जो उस स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक तरफ प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, लेकिन जब आप स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं, तो गरीब तबके से आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा- व्यवस्था को लेकर, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर आपके पास क्या प्लान है? माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रधान मंत्री जी जाकर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, लेकिन आप ही की सरकार एनआईआईटी, कालीकट में प्रोफेसर डॉ. शाइजा ए. को योजना और विकास विभाग का डीन बना देती है, जो खुलकर कहती हैं कि मेरी नज़र में नाथूराम गोडसे बहुत महान था। आपकी New Education Policy यह है और इस दिशा में जा रही है।

सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किस तरह से एनसीईआरटी की किताबों में साम्प्रदायिकता को परोसा जा रहा है! माननीय मंत्री जी, क्या आपके संज्ञान में है कि केन्द्रीय हिंदी संस्थान और NIEPA जैसे जो संस्थान हैं, उनमें अघोषित तौर पर यह कह दिया गया है कि देवनागरी में लिखते हुए जो नुक्ते लगाए जाते थे, जिनको कहा जाता है कि वे उर्दू से आते हैं, उनको अघोषित तौर पर रोक दिया गया है कि नई छपने वाली किसी भी किताब में नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। एनसीईआरटी की किताबें छापने वाले कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी, तो उनका यह कहना था कि हमें ऊपर से आदेश है, हालांकि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह नुक्ता हटा कर आप देवनागरी भाषा को मजबूत कर रहे हैं या उसे कर्कश और कमजोर बना रहे हैं? यह मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है और मैं उनसे इसके बारे में जानना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पीएमश्री विद्यालय को लेकर बहुत बातें हुईं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एक जिला है। वहां धामूपुर गांव में वीर अब्दुल हमीद विद्यालय है। पिछले दिनों पीएमश्री कंपोजिट स्कूल का नाम लेकर उस स्कूल का नाम बदल दिया गया। महोदय, उसके सहारे भी सांप्रदायिकता परोसने की कोशिश की गई। जब सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा खड़ा हुआ, हम सभी लोगों ने आवाज़ उठाई, तब बेसिक शिक्षा ने अधिकारी ने फिर से नाम बदल कर पुनः उसका नाम वीर अब्दुल हमीद - जो परम चक्र विजेता हैं, उनके नाम पर करने का काम किया। महोदय, इस योजना के थ्रू भी सांप्रदायिकता को परोसने का जो काम किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। मंत्री जी के संज्ञान में है यह बात है या नहीं, लेकिन उसको रोकने के लिए आप क्या काम करेंगे?

महोदय, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उनमें से हिंदू-मुस्लिम एकता के चैप्टर हटाए जा रहे हैं। महोदय, एनसीईआरटी की किताबें बच्चों का ज़ेहन तैयार करती हैं। आप बेसिक तौर पर एक नया इतिहास पढ़ाने के चक्कर में बच्चों को, छोटे बच्चों को गुमराह करके, उनको एक असत्य इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, आगे चलकर वे बच्चे दुनिया में कहां सस्टेन करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा और धर्म को एक-दूसरे से अलग रहना चाहिए। मैं आज इस विषय पर बात करते हुए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से भीमराव राम जी अम्बेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद इकबाल और भारत

के संविधान पर आधारित शोध पत्रों को हटाया गया है, दलित लेखक बामा और सुकीरथ राणा को अंग्रेज़ी पाठ्यक्रम से हटाया गया है, क्या ये चीज़ें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हैं?

महोदय, समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी पर आदरणीय मंत्री जी से और सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि आप बदलाव के नाम पर ये जो नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

महोदय, कैंपस में जिस तरह की £ है - अभी एक माननीय सदस्य ने अपनी स्पीच में बोलते हुए जेएनयू का जिस तरह से जिक्र किया कि जेएनयू में किस तरह के नारे लगे। कुछ नकाबपोश लोग आते हैं, नारे लगाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पुलिस सालों साल गुज़रने के बाद भी उन नकाबपोश लोगों को ढूंढ़ नहीं पाती है। इतने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने के लिए सरकार जो तरीका इस्तेमाल कर रही है, वह बहुत शर्मनाक है।

महोदय, पिछले दिनों एक महिला नकाबपोश, जिसने छात्रावास में लाठी बरसाई थी, डंडे चलाए थे, उसकी पहचान आज तक नहीं की जा सकी, दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ़ नहीं सकी। जामिया की लाइब्रेरी में जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गई थीं, उनके जख्मों के निशान आज तक नहीं सूखे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ...(**व्यवधान**)... अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर वहां के सांसद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह बहुत शर्मनाक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से पूछना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप बदलाव के नाम पर जो नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप बैठिए, विराजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: महोदय, नदियों को साफ मत कीजिए, उन्हें गंदा मत होने दीजिए, नदियाँ अपने आप साफ हो जाएंगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप जंगल मत उगाइए, बस पेड़ों को काटना बंद कर दीजिए, जंगल अपने-आप उग जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि शांति स्थापित करने के लिए भाषण मत दीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति अपने-आप स्थापित हो जाएगी, मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम फैलाने पर लंबे-लंबे लेख मत लिखिए, बस नफरत करना बंद कर दीजिए, प्रेम अपने आप फैल जाएगा। यह जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जिस तरह से गरीब तबके के लोगों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, वह बहुत शर्मनाक है, जिस तरह से शिक्षा को निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, वह बहुत शर्मनाक है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर सोचें और इसमें सुधार करने का प्रयास करें। इस सदन की तरफ से शायद हम इससे बेहतर बात, इससे बेहतर सुझाव नहीं दे सकते हैं। महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): इमरान प्रतापगढ़ी जी, आपका भी धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

श्री जयराम रमेशः उपसभाध्यक्ष जी, अभी-अभी इमरान प्रतापगढ़ी जी ने एक सांसद का जिक्र किया है। महोदय, जिस सांसद ने कहा था, उस सांसद को ऑथेंटिकेट करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): उन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया है।

श्री जयराम रमेशः उन्होंने सांसद का जिक्र किया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): इमरान साहब ने उन्हें ऑथेंटिकेट कर दिया है। श्रीमती मौसम बी. नूर, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

SHRIMATI MAUSAM B NOOR (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress, I thank you for allowing this discussion on the Education Ministry. Yesterday, the Education Minister called the people of a State 'uncivilised'. He should tender an apology on the floor of the House. Also, Sir, I appeal to you to allow discussion on the important issue of duplicate collector's photo identity cards, a serious matter, to enable free and fair election. ..*(Interruptions)*..

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): डा. जॉन ब्रिटास, आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मौसम नूर जी बोल रही हैं और आप आसन और उनके बीच में आ रहे हैं। यह उचित नहीं है।

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: Sir, the BJP talks about co-operative federalism. Let me give you one example on education itself to show you that it is an empty slogan, a *jumla, a*nother hollow promise by the BJP, which is running a shaky coalition since the BJP is 32 seats short of the majority. The Samagra Shiksha Scheme follows a 60-40 fund-sharing ratio between the Union and the State. Despite West Bengal being one of the best-performing States in implementing this programme, the Union Government has failed to release the fund it owes us. In the financial year 2023-2024, the Union Government was supposed to allocate Rs. 1,746 crores to West Bengal. However, only Rs. 311 crores have been released so far, less than 18 per cent of the total funds due. The Bangla-*Birodhi* mindset is deep-rooted in their minds. Even after repeated communications and letters from the State Government, the Union Government did not release a single penny owed to the State of West Bengal. In fact, what it did was stop all funding even in the financial year 2024. We, the All India Trinamool Congress, are standing strong by our ideology of *Maa Mati Manush* by not only releasing 40 per cent of the State's share regularly, but releasing an additional amount as well. This amount is paid to ensure that wages and salaries are given on time to the Samagra Shiksha employees, and composite grants to the schools and

other student-centric incentives are not stopped. The Union Government's failure to release funds approved by the Ministry of Finance for West Bengal is an act of depriving the State's people. This violates the right to education. Hence, I ask you here in this House: Why do you deprive Bengal? You can't beat us, so you deprive us. Or, is it because we don't accept the name PM SHRI for a scheme where the State is contributing 40 per cent of the funds? Sir, the Samagra Shiksha guidelines do not mention signing the MoU for PM SHRI as a prerequisite for fund release. Withholding funds on these premises is anti-federal and undemocratic. It is depriving the people of Bengal of their rightful dues. Moreover, several other demands from the Government of West Bengal have been made, but none have been addressed by the Union Government, be it regarding midday meal schemes or increasing the allocation per student or increasing financial support for midday meal cooks. However, on the other hand, we believe in development for all. As a result, about 2,30,000 cook-cum-helpers are given Rs 1,000 per month for 10 months in a year. Further, the State Government on its own is also providing additional Rs. 500 per month as an honorarium to each cook-cum-helper, whereas you don't even address the demand to construct dining halls, kitchen sheds and provide flexi-funds. In every manner, you have been anti-Bengal. A testimony to that is the fund for infrastructure and R&D of universities and colleges have been discontinued for the last few years. In fact, the new scheme of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, that has a funding pattern of 60-40 between the Union and the State, has been renamed as Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan. Why, Sir, why Pradhan Mantri everywhere? Even in this scheme, the Union owes Rs. 170 crores to the State of West Bengal. The Government speaks a lot on education. However, when the budget comes, the Union Government is spending only 0.37 per cent of the GDP on education this year. Whereas, look at West Bengal, look at our education model. We are spending more than 2 per cent of our GSDP on education. The state of education in the country is so bad that one out of two students in grade 8 cannot do basic division. The pre-metric scholarships between 2018-19 and 2022-23 were decreased by 94 per cent.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्या, समाप्त करें।

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: Under PMKVY, only 15 per cent of the trained candidates were placed. In fact, the placements were delinked from the fourth phase. Only four out of ten youth in the workforce possess formal skills and one in three youth are neither in education, nor in employment nor in training, with women making 95 per cent of this group.

Sir, I would suggest our Education Minister to come to Bengal. See and learn from Mamata di's education model. After all, the world is learning from Bengal. Kanyashree has been recognized by the United Nations. We have other schemes like *Aikyashree, Sikshashree, Medhashree* and *Sabooj Sathi* which have made the lives of students easier. Hence, I say, leave this Bengal-*birodhi* mindset and learn from Bengal. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैं माननीय सदस्या और अन्य सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वैसे यह नियम है कि हम पढ़ कर भाषण नहीं देंगे, पर सभापति महोदय सबको allow कर रहे हैं। मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि संसदीय परंपराओं के अंतर्गत हम लिखा हुआ पूरा भाषण नहीं पढ़ सकते, हम quote कर सकते हैं। माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा।

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, with your kind permission, I would like to speak while sitting as I am unable to stand.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप बैठे-बैठे आराम से बोलिए।

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, when the Business of the House started exactly after the Question Hour, I was watching it sitting in my house. Because of my health, I am unable to sit here for the whole day. Former Chief Minister Digvijaya Singh *ji* was speaking. Then your good self spoke from this side. I heard all the speeches barring one or two speeches which I missed.

Sir, I do not want to criticise on the issues raised by several hon. Members. I am only going to say a few words. Education is a Concurrent Subject. It is the responsibility of both the State and the Centre. They should see that there is no controversy on this issue. Whether it is about the appointment of Vice-Chancellors, I don't want to raise that issue. Not just in Karnataka but in several States, appointment of Governors was one of the major controversies. That is where I draw the attention of the hon. Education Minister to see that this type of controversies should not be allowed to continue. I only appeal to your good self to see that some remedy should be there to resolve this controversy.

Now, I confine myself to Karnataka. There are private institutions in Karnataka. My senior colleague Ramesh *ji* is sitting there. There are 30 universities in Karnataka. Now, the private institutions in Karnataka are playing a very major role in providing education, starting from primary education to medical education, engineering, etc. In all aspects, 30 private institutions are there. I don't want to recall what happened in respect of deemed universities. I don't want to go in-depth of how and when the

deemed universities were started in those days. It hurts the feelings of some Members if I talk in detail about deemed universities. During that period, Karnataka was able to get recognition. That is why, I said that there are 30 universities in Karnataka and they are doing their best to provide education. They are providing education to all communities and sections of the society. There is no discrimination. That is one thing which everybody has to appreciate.

Sir, coming to the point, when Karnataka was ruled by the late Maharaja Krishnaraja Wadiyar, Mysore University was started about 100 years back. Then, there is also Dharwad University. You know why I refer to this is because Mr. Ramesh should not mistake it. He is a senior colleague from Congress. He is a good friend of mine. Now, what is the position? There is no money to pay the salaries. A University which was started about 100 years back has no money from the State Government to provide salaries! That is the position. I will just give a brief note. The University was established in 1916 as the sixth oldest university in the country. The University has made a significant contribution in the field of higher education by providing quality education during the outstanding leadership and efficient regime of Prof. Rangappa between 2013 and 2017. The University not only celebrated the Centenary but it also witnessed several memorable events. For instance, the President of India inaugurated the Centenary year in July, 2015. The hon. Prime Minister was gracious enough to inaugurate the Indian Science Congress in January, 2016. Narendra Modi*ji* was the person who inaugurated where I was present. During the Science Congress session, as many as ten Nobel Laureates from across the world visited the University and delivered lectures on the subject of their expertise. Apart from other credentials, Prof. Rangappa is also a Fellow of the World Academy of Sciences. He is one of the renowned scientists in the country. In fact, he was instrumental in upgrading the physical facilities of the University of Mysore. It is very disappointing and distressing that the University of Mysore alongside the Karnataka University, Dharwad, established in 1949, have been suffering from indifference and callousness of the State Government. It is worrisome that as many as 370, meaning more than 65 per cent of the faculty's sanctioned teaching posts are vacant for quite some time. The stalemate of the University is impacting both teaching and research. The two old Universities, viz., the University of Mysore and the Karnataka University, Dharwad, need substantial grant from the Centre. The hon. Education Minister is here; please take note of that. These two Universities are your responsibility, -- I have already mentioned about the Concurrent subject -- you must see that sufficient grant is given without mixing politics. I hope and trust that my request would be considered by the Central Government because Modi*ji* has come, and the President of India has come

on two occasions, which I have already mentioned. There is one more thing which I have mentioned that our hon. Leader of the House mentioned about what the Union Government, Modi*ji*'s Government has done. He spoke about 1.1 lakh medical seats.

4.00 **P.M.**

He is the Leader of the House who is holding the portfolio of Ministry of Health and Family Welfare. He mentioned that nearly 1.1 lakh UG and PG medical seats, over the past decade, were added by the Government. And, also, 75,000 medical seats will be added in medical colleges, in the coming 5 years, with a long-term goal. Sir, this is one of the major steps taken by the Union Government and the hon. Minister, Mr. Nadda, who is also the Leader of the House. He mentioned this on the floor of the House. I congratulate the hon. Leader of the House who is holding the portfolio of Ministry of Health & Family Welfare. I do not want to take much time. My only appeal is this. I was a school teacher before joining politics. I know the problems of the rural schools. Nobody should mistake me. As Chief Minister, I appointed 1,56,000 lady teachers in one-step. I appointed 1,56,000 lady teachers for the first time. Now, we talk about Women's Reservation and *Nari Shakti*. But, at that time, there was no reservation. I appointed 1,56,000 women teachers when I was Chief Minister. I do not want to mention what all I had done. I can quote several instances about the Women's Reservation and all these things. Sir, as an elderly man--I am 92 years old--I can speak what I have done. My friend is sitting here. I only request the Union Government--I am not criticizing the position of the Karnataka Government; but such two prestigious institutions have no resources to pay salaries--to help the universities. The Union Government should see without mixing politics. Whatever the burden that may come, you must shoulder that burden and see to it that the institutions should be saved.

With these words, my respectable sincere thanks to the hon. Vice-Chairman, Sir, who has given me an opportunity to speak. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय देवगौड़ा साहब। आपकी सारी बातें उन्होंने नोट की हैं। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी।

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Thank you Mr. Vice-Chairman Sir. Today, as the discussion is going on about the Ministry of HRD and the education policy, we must all compliment our journey since Independence till today as to how education in our country has evolved. It has not only evolved, but has shaped the destiny of our

country till now and will be the most important factor as we go along in our onward march. I would also like to compliment the Government and, especially, the Prime Minister's vision for giving very special emphasis not only to education, but more importantly, to women or girls' education as well as skill development, which, eventually, will be taking this country, the next generation and generations to come forward and giving them strength to be able to stand on their own feet. Education, of course, is the most important pillar in any child's evolution and development and the Government's policy, NEP and other initiatives have actually been bearing fruit. I would like to emphasize just one thing. I come from Maharashtra which has been one of the most forward looking in terms of education. My colleague here, has been the Chief Minister also of the State. All the States, we all focus on education being affordable. Therefore, all our children in villages or even in big cities went to municipal schools, they went to Zila Parishad schools and so on. But over a period of time, whether it is Maharashtra or many other States in the country, have not been contemporary enough to change according to the needs of the time. As a consequence, most of the municipal schools and Zila Parishad schools impart education, of course, in the language of the State, which is absolutely necessary. But they have not kept pace at par with the other changes which are taking place in this field of education. Whether we like it or not, everybody is so passionate when it comes to language. In Maharashtra, obviously, we fight for Marathi. In Tamil Nadu, we always see that people fight for the Tamil language, and rightly so, there is nothing wrong with that. It is a language which is our ownership, coming from a particular State. But at the same time, the world is changing. Today, I dare say and I should say this because most of us would have experienced it. आप सभी जानते हैं कि जिला परिषद और म्युनिसिपल स्कूल्स में भर्ती नहीं हो रही है। कई कक्षाओं में सिर्फ 10-20 बच्चे ही हैं। लेकिन वहीं, अगर छोटे से गांव में, जहां मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है, साथ ही, उसी गाँव या शहर में कोई सीबीएसई स्कूल होगा, तो वहां साल की 40-50 हज़ार रुपये फीस होने के बावजूद भी वे स्कूल्स पूरी तरह से फुल रहते हैं। वहां एडमिशन के लिए लोगों को सिफारिशें लगानी पड़ती हैं। What I am trying to say is that somewhere there is a need to tweak the educational model and I would say to the Central Government, प्रधान जी, कृपया इस विषय पर ध्यान दें कि आप केंद्र सरकार के माध्यम से जितना कर सकते हैं, उतना करेंगे ही, लेकिन राज्यों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करें। पूरे देश और दुनिया के हिसाब से उसका आधुनिकीकरण करें। यदि एक बच्चा उसी गांव में जिला परिषद या म्युनिसिपल स्कूल में मुफ्त में पढ़ने के बजाय सीबीएसई स्कूल में जाने को प्राथमिकता दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि माता-पिता को लगता है कि वहां उनके बच्चे का भविष्य बेहतर होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रफुल्ल पटेलः इसलिए, जो सीबीएसई स्कूल आज लोकप्रिय हो रहे हैं, उसी तरह के बेहतर स्कूल राज्यों के माध्यम से पूरे देश में खोले जाएं। आप उन्हीं स्कूल्स की गुणवत्ता बढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करें। I can take some more time, few minutes.

श्री जयराम रमेशः सर, इनका बोलने का समय पूरा हो चुका है।

SHRI PRAFUL PATEL: My friend, you are always my dearest friend.

श्री जयराम रमेशः सर, आप निष्पक्ष रहिए।

श्री प्रफुल्ल पटेलः वे निष्पक्ष ही हैं। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि हमारे बहुत सारे बच्चे आज पूरे विश्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। आप अगर हिसाब लगाएंगे, चाहे वह regular education हो, technical education हो और medical education हो, इसके लिए हमारे कई लाख बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ऐसे-ऐसे मुल्कों में हैं, जिनके हमने नाम नहीं सुने होंगे, वहां पर भी हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। हम लोगों को हमारी सोच बदलनी होगी, क्योंकि हम लोग इस मामले में बहुत ज्यादा खींचतान कर लेते हैं और हम कई बार सही रास्ते से भटक जाते हैं। आज विश्व में हमारे बच्चे foreigh exchange खर्चा करके, मां-बाप के लाखों-करोड़ों खर्च करके वहां जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और बहुत सारे वापस आ जाते हैं और बहुत सारे वहीं पर रह जाते हैं। चाहे उच्च शिक्षा की प्रणाली के लिए विदेश की universities के साथ tie up करिए, चाहे हमारे यहां उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ तैयार कीजिए, जिससे हमारे यहां शिक्षा बाहर जाकर प्राप्त करने के बजाय भीतर ही मिल जाए, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए बहुत सारे local issues रहते हैं, इनको भी tweak करने की जरूरत है। लास्ट में, आज हमारे देश में सभी भाषाओं के प्रति हमें गर्व है और होना भी चाहिए। Classical languages में हमारी मराठी भाषा का समावेश करने के बारे में आया है। हमारी मराठी भाषा को दर्जा मिलने की वजह से महाराष्ट्र में हम सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारी भाषा के प्रति सभी लोगों का इतना सम्मान है, यह जानकर भी बहुत खुशी होती है। इसके साथ-साथ सभी languages को local level पर महत्व दे सकते हैं। इसके साथ-साथ शिक्षा के माध्यम से बच्चों को बताया जाए कि वे भारत के अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत गहन विचार करके नई नीति में और सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए।

सर, हमें skill development के बारे में भी सोचना चाहिए। आज लाखों लोग, जो Gulf में काम कर रहे हैं, वे बहुत शिक्षित नहीं हैं, लेकिन skilled हैं। वहीं आज 150 billion लोग हमारे भारत को हर साल remittance करते हैं, inward remittance करते हैं, जो इस देश की financial और foreign exchange stability के लिए बहुत जरूरी है और इतने ही लोगों को केवल अपनी स्किल के आधार पर रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट को भी ज्यादा से ज्यादा महत्व दें। मैं इसके बारे में हमारे एचआरडी मंत्री जी से निवेदन करता हूं। उनके सभी अच्छे प्रयासों में हमारा सहयोग तो है और वे अवश्य हमारे देश के भावी नागरिकों की बेहतर शिक्षा प्राप्ति के लिए काम करेंगे। मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। डा. कल्पना सैनी।

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस सम्मानित सदन के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2024-2025 के बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप शिक्षा पर बोलिए।

डा. कल्पना सैनी: मैं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक सुधारों और दूरगामी पहलों पर...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, शिक्षा पर चर्चा हो रही है।

डा. कल्पना सैनी: मैं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक सुधारों और दूरगामी पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूं।

मोदी सरकार ने हमेशा शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार माना है। यह इसी विचारधारा के साथ शिक्षा प्रणाली को सशक्त, समावेशी करेगी और वैश्विक नेतृत्व वाले भारत देश की यह शिक्षा नींव भी मज़बूत करेगी। हमारे देश की 40 प्रतिशत आबादी युवाओं और बच्चों की है, जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका सही नियोजन एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है।

राजनीति के पारंपरिक और सर्वकालिक मुद्दों में रोज़गार सबसे प्रमुख स्थान रखता है। किसी भी सुशासन की परख का आधार शिक्षा व्यवस्था होती है। यदि मोदी सरकार के 10 वर्षों का मूल्यांकन किया जाए, तो कई ऐतिहासिक उपलब्धियां सामने आती हैं। विपक्ष की पिछली सरकारों की निष्क्रियता और अदूरदर्शिता के कारण भारत की शिक्षा प्रणाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती चली गई। शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने, डिजिटल इंडिया के अनुरूप ढालने और रोजगारपरक बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रह गए और उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिला।

महोदया, विपक्ष के कार्यकाल में कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिससे विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रहे और औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल सका। इसके विपरीत, 2014 में भाजपा सरकार के आने के पश्चात शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधारों को प्राथमिकता देते हुए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। महोदया, 2014 में 68,728 करोड़ रपए के बजट के साथ शिक्षकों की ट्रेनिंग, स्किल कार्यक्रम और वर्चुअल कक्षाओं पर ध्यान दिया गया। महोदय, 2015 में बजट मामूली रूप से बढ़कर 68,968 करोड़ रुपए हुआ, जिससे उच्च शिक्षा, नए-नए आईएएम, नई नई आईआईटी और शिक्षा ऋण योजनाओं पर जोर दिया गया।

महोदया, 2016 में 72,394 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से जारी हुआ, जिसमें हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की स्थापना हुई। महोदया, 2017 में शिक्षा क्षेत्र को 9.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 79,685 करोड़ रुपए आवंटित

किए गए, जिससे कॉलेजों को स्वायत्ता देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए गए। 2018 में 83,626 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम' शुरू किया गया, जो विदेशी छात्रों को आकर्षित करने पर केंद्रित था। 2019 में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 94,853 करोड़ रुपए मिले, जिसमें खेल, शिक्षा, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता को बढ़ावा देने की पहल शमिल थी। महोदया, 2020 में शिक्षा बजट 99,300 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसका मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति को लागू करना था, 2021 में शिक्षा मंत्रालय को 93,224 करोड़ रुपए मिले, जिससे स्कूलों और उच्च शिक्षा को सशक्त करने के साथ-साथ वैश्विक साझेदारी के माध्यम से कौशल विकास पर जोर दिया गया। महोदया, देश के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए हैं। इन प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का क्रियान्वयन रहा है।

महोदया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तनकारी लहर के रूप में उभरी है। इस शिक्षा नीति ने शिक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं को समझते हुए एक समग्र समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें बहुविषयक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल में सशक्त बनाना भी है। एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं में बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों का एकीकरण किया गया है। यह नीति आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है, जिससे छात्र केवल रटकर सीखने के बजाय व्यावहारिक और नवाचार आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकें। महोदया, एनईपी 2020 का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है, बल्कि छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करना है। महोदया, 2022 में शिक्षा बजट पहली बार वन ट्रिलियन रुपए के पार पहुंचा, जिसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और संस्थानों को समर्थन देने पर विशेष ध्यान दिया गया। महोदया, 2023 में यह बजट बढ़कर 1,12,899 करोड़ रुपए हो गया, जिससे एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएँ शामिल हुईं। महोदया, 2024 में शिक्षा बजट 1,48,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें डिजिटल शिक्षा, रोजगारपरक कौशल विकास और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सुधारों को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। यह दशक शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कौशल विकास की प्राथमिकता देने का साक्षी रहा। महोदया, एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं में बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों का एकीकरण किया गया। यह नीति आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है। इससे छात्र केवल रटकर सीखने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करते हुए सरकार ने शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। स्किल इंडिया मिशन और रिसर्च फाउंडेशन जैसी पहलों ने युवाओं को हुनरमंद बनाकर उनकी क्षमताओं को नया आयाम दिया है। इन प्रयासों के चलते प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और भाजपा का यह विश्वास मजबूत हुआ कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उनके प्रयास सही

राह पर हैं। इस चुनाव में भी युवाशक्ति मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनी। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में मोदी सरकार के 10 वर्षों के युग को स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। इस दौरान नई शिक्षा नीति लागू करने से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक कई बड़े कार्य किए गए, जो युवा सोच और उनकी जरूरतों के अनुरूप थे। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसमें एक अहम पहल थी। SWAYAM प्लेटफार्म के जरिए 4 करोड़ से अधिक छात्र ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ चुके हैं, हालांकि डिजिटल शिक्षा की अवधारणा पहले से मौजूद थी, लेकिन कोविड काल में इसे जबरदस्त गति मिली। उस समय जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हो गए, तब ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प बनी। अब यह न केवल सुविधा, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है, खास तौर पर उन छात्रों के लिए, जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। देश के स्कूलों की आदर्श स्थिति को लेकर अब तक कोई मानक तय नहीं था, लेकिन एनईपी लागू होने के बाद मोदी सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में दो सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल में बदलने का निर्णय लिया, जिसे पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) का नाम दिया गया। इसके तहत 6,207 सरकारी स्कूलों को चुना गया और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए 630 करोड़ रुपए जारी किए गए। बेरोजगारी से युवाओं को बचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही उन्हें कौशल विकास से जोड़ने की रणनीति बनाई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश के 50 प्रतिशत युवाओं को किसी न किसी कौशल से जोड़ा जाए। केंद्रीय बजट 2025-26 शिक्षा प्रणाली के डिजिटलीकरण, तकनीकी सशक्तिकरण और नवाचार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल 1,28,650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक है। मोदी सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए 78,572 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 50,077 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ किया जा सके। सरकार ने स्कूली शिक्षा को अधिक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की योजना बनाई है, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रति विद्यार्थियों की रुचि को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। दशकों तक भारत में डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों की उपेक्षा एक बड़ी समस्या रही है। जब 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति अपने चरम पर थी, तब भारत की शिक्षा प्रणाली इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। भाजपा सरकार ने निर्णय लिया कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारतनेट परियोजना के माध्यम से सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे ई-लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ आईआईटीज़, आईआईएम, एनआईटीज़, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संस्थानों के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे भारतीय युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार किया जा सके। पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटीज़ में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65,000 से 100 प्रतिशत बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं,

जिससे शिक्षा तक उनकी पहुंच सुगम हो सके। नए स्कूल खोलने के साथ-साथ कक्षा आठ तक की छात्राओं को मुफ्त किताबें और ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आर्थिक बाधाएं उनकी पढ़ाई में रोड़ा न बने। आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए अध्यापकों के लिए आवासों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही महिला शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, जिससे छात्राओं को सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक माहौल मिल सके। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दयनीय बनी रही, जहाँ सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, योग्य शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था। भाषा नीति की दृष्टि से भी कांग्रेस सरकार ने शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक प्राथमिकता दी, जबकि मातृभाषा और भारतीय भाषाओं की अनदेखी की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण और वंचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुँच कठिन हो गई। इसके विपरीत मोदी सरकार ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 'भारतीय पुस्तक योजना' की शुरुआत की, जिससे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मातृभाषा में शिक्षा को बल मिलेगा। इसी क्रम में सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है, जो लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करेगा। कौशल विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

सरकार गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए पहचान पत्र जारी करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे उन्हें अधिक सुरक्षित रोजगार अवसर प्राप्त होंगे। अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे भारत वैश्विक अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर सके। सरकार ने मेडिकल और तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए नए मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों की स्थापना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, 'प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना' के तहत डिजिटल शिक्षा संसाधनों को और मजबूत किया जाएगा, जिससे स्कूली बच्चों के लिए ई-कक्षाओं और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत कौशल विकास, Inter-disciplinary learning और लचीली शिक्षा प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिससे छात्र अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा का संयोजन कर सकें। सरकार ने शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की योजना बनाई, जिससे छात्र उद्यमिता की ओर प्रेरित हो सकें। इस बजट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया है, जिससे वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा केवल एक डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न रह कर नवाचार, आत्मनिर्भरता, रोजगारपरक कौशल का स्रोत बन सके। इसके लिए मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ।

यह बजट शिक्षा के क्षेत्र में समग्र सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इन पहलों से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस बजट में प्रस्तावित सुधारों से भारत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह बजट सिर्फ आँकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि युवा भारत का भविष्य गढ़ने का संकल्प है। 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र के साथ यह बजट एक सशक्त, आत्मनिर्भर और ज्ञान आधारित भारत की दिशा में अभूतपूर्व कदम है। मैं पूर्णतया इस बजट का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय श्री अब्दुल वहाब।

SHRI ABDUL WAHAB (KERALA): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on the New Education Policy. My request to our Minister is, first of all, in our district, Malappuram, we need a Kendriya Vidyalaya. It is a long pending demand in Ponnani. The next request is, we need Central assistance to set up digital libraries in Kerala. Only 3,416 schools, out of 15,864 schools, in Kerala, have digital libraries. Then, we request for fund allocation to A.M.U. Centre, Malappuram. There is a campus of Aligarh Muslim University. We have given 300 acres. We acquired 300 acres and given to that campus. But nothing is there. Either you return the property to Kerala Government so that we can set up some universities there or you set it there. Ministerji, Aligarh Muslim University has 300 acres. This is unutilized for years, and, with much difficulty, we acquired that. If you are not in need of it for Aligarh Muslim University, please return this land to Kerala Government. We have scarcity of land in Kerala, as you all know. Timely disbursal of scholarships is not happening. Forget the name 'Maulana Azad'. You may change the name of the university to that of the Prime Minister. We have no problem with that, but we want scholarships. If the name is the problem, change the name. Even disbursal of scholarships to SC and ST students is not being done. OBC fellowships are late by six to eight months. Increase non-NET Fellowship from Rs. 8,000 to a minimum of Rs. 20,000. This is not very much higher than what they get in MNREGA. They cannot live with those eight thousand rupees. Maulana Azad National Fellowship should be reinstated. There have been a lot of suicides happening in NIT, Calicut.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): वे आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री अब्दुल वहाब: उनको सुनना चाहिए। उनको कोई दूसरे सदस्य डिस्टर्ब कर रहे हैं।

There should be an inquiry as to why it is happening. There is one more thing. A colleague here mentioned the case of a Professor who said nice things about the

person who killed the Mahatma. He is from NIT, Calicut and this is known. Now, an inquiry committee needs to be set up for the suicides. 54 dropouts happened there. For what reason, why it is happening, we don't know. The recent UGC Regulation, 2025 takes down the autonomy of the university's status to appoint their own independent committee for selection and promotion of faculty. The recent UGC Regulation of 2025 does not leave any role for the State Government in appointing Vice-Chancellors in public universities under the State Act. ...(*Time-bell rings.*)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): आपका टाइम तो कम्प्लीट हो गया है।

SHRI ABDUL WAHAB: Madam, I may be given some more time.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI SANGEETA YADAV): Please conclude within one minute.

SHRI ABDUL WAHAB: This is a violation of the fundamental rights of the State in a federal structure. In many other aspects, the UGC Regulation, 2025, is highly controversial. Hence it must be taken back. Thank you.

SHRI S. SELVAGANABATHY (Puducherry): Madam Vice-Chairperson, education is meant to promote the economic and socio-cultural development of developing countries. Education plays an important role in human capacity building and accelerates economic growth through a society's knowledge, skills and creative strength. Education's positive outcomes include poverty reduction, change in health status, socio-economic policy development and good governance.

Keeping all these things in mind, this Budget is aiming to cater to the comprehensive requirements, right from childhood to youth, who would be leading from the front in realizing the *Viksit Bharat* agenda of 2047 and beyond. The highlight of the historic Budget of 2025-26 is that the total budget allocation for the Ministry of Education has reached Rs. 1,28,650 crore, marking a 6.22 per cent increase over BE 2024-25. Fifty thousand Atal Tinkering Labs in Government schools is a landmark. In the next five years, all Government secondary schools will be provided with broadband connectivity under Bharat Net. In the next three years, *Bharatiya Bhasha Pustak* Scheme would provide digital form Indian language books. There is an allocation of Rs. 20,000 crore to implement private sector-driven research, development and innovation. IITs started after 2014 would get new infrastructure which could accommodate 6,500 more students. Provision has been made for 10,000

fellowships for technological research under the PM Research Fellowship Scheme. Five National Centres of Excellence for Skilling are to equip youth for 'Make for India - Make for the World'. There is provision for Manufacturing Centres of Excellence in Artificial Intelligence for Education with a total outlay of Rs. 500 crore. Through regulatory changes, the regulators are facilitating opportunities for stakeholders by taking measures to internationalise the education ecosystem, bringing transparency and industry-relevance and improving access to education for India's youth. Some areas, where regulatory stakeholder consultations have resulted in promulgation of regulations are:- (i) UGC guidelines to facilitate the setting up of foreign university campuses anywhere in India, which will further add to this impetus of internationalisation of education; (ii) An Institutional Development Plan (IDP) for higher education institutions, which provides a strategic roadmap for their functional and structural growth; (iii) Mandatory disclosures on institutions' websites provide much-needed transparency and allow the students and parents to make well-informed decision about admissions and other aspects; (iv) Introduction of PM Vidya Lakshmi Scheme to provide financial support to meritorious students, thereby improving access to education and targeting to increase the Gross Enrolment Ratio.

The hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, approved a new Central-sector scheme PM Vidyalaxmi on November 6, 2024. It seeks to provide financial support to meritorious students in their pursuit of higher education. PM Vidyalaxmi portal provides single window for the students to access information and make application for educational loans provided by the banks and also Government scholarships. It has the following features:- (i) Information about educational loan schemes of banks; (ii) Common educational loan application form for students; (iii) Application to multiple banks for educational loans; (iv) Facility for banks to download students' loan applications; (v) Facility for banks to upload loan processing status; (vi) Facility for students to email grievances or queries relating to educational loans to banks; (vii) Linkage to national scholarship portal for information and application for Government scholarships.

Our hon. Prime Minister made provision for setting up another 85 new Kendriya Vidyalayas (KV). As on date, there are 1,256 Kendriya Vidyalayas, out of which three are outside the country, that is, in Moscow, Kathmandu and Tehran. A total of 13,56,000 students are studying in KVs. Now, with these new 85 Kendriya Vidyalayas, an addition of 82,560 students can be accommodated in the coming years and it will create 5,388 direct permanent employment opportunities by way of appointment of teaching and non-teaching positions in the country.

A nation can flourish only with language. I will come to the three-language policy after some time.

Our hon. Prime Minister has taken initiatives to curb burden on students during exam time. The hon. Prime Minister conducts *Pariksha Pe Charcha* programme every year. Many students participate all over India and get benefited. Counseling sessions on stress management and psychology treatment for students are being organised during the exam period. It really helps to drop the number of exam-related suicides by students and failures also.

One of the best visions of our hon. Prime Minister is *Beti Bachao Beti Padhao* programme, which is scaling new heights. The daughters are God's precious gift but, earlier, their importance was undermined. The hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, on 22nd January, 2015, launched the scheme *Beti Bachao Beti Padhao.* This scheme is completing a decade now. It also ensures proper arrangements and participation in education and employment for girl children. The doors for admission of girls in Sainik schools and National Defence Academy are now open. Modi Government's initiatives have contributed to notable increase in women's participation in STEM education, the enrolment figure being around 40 per cent in the year 2021-22. Over the past decade, female enrolment in higher education has risen from 1.57 crore to 2.7 crore and the number of women securing Ph.Ds has increased by 107 per cent.

Sir, the National Education Policy 2020 aims to make high-quality education accessible to all children in India. The policy also aims to reduce the gaps between academic and vocational streams and integrate technology into the education system. Like the previous education policies introduced in the years 1968, 1986 and 1992, the National Education Policy, 2020 also received criticism from certain quarters. Are they valid and reasonable? This is my question.

Since 1965, the anti-Hindi sentiment has come to prevail in Tamil Nadu and Puducherry. In fact, opposition to the three-language formula stemmed from this sentiment. The sentiment has been established so strongly that the three-language formula of National Education Policy 2020 without compulsory Hindi is also opposed. Now, we are not giving compulsory education for Hindi but it is also being opposed. I would like to remind the House that the three-language formula was put forth first in 1968 and was followed in 1986 and 1992. The three-language formula had a compulsory component of Hindi at that time. Whose Government did this? Only the Congress Government did this. But, in National Education Policy, 2020, Hindi is not being made compulsory. I would like to remind you that all other Southern States followed the formula and learnt Hindi except in Tamil Nadu and Puducherry.

Now, in Puducherry also, the CBSE curriculum is being introduced in Government schools and three-language formula is followed in Mahe and Yanam region. I have a question to my friends in the Opposition benches. Do they share the same view on three-language formula? Even yesterday, one of the Congress colleagues vouched for the two-language policy in Tamil Nadu. That is fine, but will the Congress say it openly that the nation needs only two-language formula? Will their leader, Shri Rahul Gandhi, agree to that? It was the Congress Government, which formulated the three-language system. Even now, they are implementing three-language formula in Karnataka and Kerala in the South but in Tamil Nadu, they are supporting the two-language system. Forgetting that they are pan-India parties, they pretend to support the two-language formula in Tamil Nadu. Wherever possible the medium of instruction until, at least, Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be the mother tongue or local language or regional language. It does not neglect English medium. It is simplified that thereafter the medium will be English.

I have another question to the champions of Tamil. The new National Education Policy describes mother tongue as the medium of instruction up to 8th standard. This was not the case with the previous policies. Only the BJP Government thought of giving primacy to the mother tongue. It proposes to impart even technical and medical education in the regional languages. Is it not a welcome development? Do you want to oppose this also? There are some self-appointed champions of Tamil language, its heritage and culture. They claim that they are the only saviours of Tamil. Before 1967, most of the schools in Tamil Nadu offered only Tamil as a medium of instruction. Only after the dawn of the DMK rule, the matriculation schools and CBSE schools have mushroomed, where Tamil is not a compulsory subject at all. They are responsible for more than 30 lakh students completing the school education without learning the single alphabet in Tamil. This is very pathetic. They must repent that they have paved the way for total neglect of Tamil even for Tamil natives.

Universalization of literacy and numeracy is much needed. As a part of it, Right to Education Act will be extended to cover secondary level education. This aims to make education accessible to all the children from 3 to 18 years, regardless of their socio-economic background. It is a step towards ensuring social justice by roping in children from under-privileged sections. At the same time, quality cannot be compromised. Let us assume that 'by grade 3' functional literacy, including reading and writing, and numeracy, including doing basic operations on paper, are to be attained by the children when they complete the grade. But its veracity can be proved only by a competent screening system. This is where the question of assessment becomes relevant.

In the New Education Policy, 2020 brought out by the Central Government, a target of 6 per cent of GDP was fixed for education. For the year 2025-26, the Budget allocated for the Ministry of Education is more than one lakh crores of rupees which is 13 per cent above the Revised Estimates of 2024-25. The Department of School Education and Literacy has been allocated Rs. 78,572 crores, which is a 16 per cent increase over the Revised Estimates of 2024-25, and the Department of Higher Education has been allocated about Rs. 50,000 crores which is an 8 per cent increase over the Revised Estimates of 2024-25. (*Time-bell rings.*) Madam, I will conclude only with a small request.

Puducherry has introduced CBSE syllabus in all Government schools. Puducherry requires special assistance for upgrading the Government schools, improving infrastructure in colleges and expanding scholarships for students from economically weaker sections. I urge the Ministry to allocate specific funds for the UT of Puducherry to ensure equitable educational development. Thank you, very much.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Madam, education is not just a sector. It is a foundation upon which our nation's future rests. It is a bridge between poverty and prosperity, ignorance and knowledge, unemployment and opportunity. While the Government boasts of record enrolment, the harsh reality is that learning levels are declining, teachers' vacancies remain unfilled and school infrastructure in many rural areas is shockingly inadequate. The truth is that education is not a priority for this Government. Public investment on education has actually fallen during the Modi years. Why have the Union Budgets slashed education spending from 3.1 per cent in 2014 to 2.9 per cent in 2024? This figure is far below the 6 per cent recommended by the National Education Policy, and the lowest in the world. The Government talks about equal opportunity, but how can a farmer's son in Bihar or a factory worker in Uttar Pradesh compete with the elite coaching students in cities? The Kendriya Vidyalayas were once the pride of the nation. Today, if you take last ten years into account, the quality of Kendriya Vidyalayas all over India has deteriorated mainly because of lack of resources. Even the teachers are not equipped. I think we need an enquiry into this. If we look at sainik schools, what we find is that even sainik schools have been privatised. Actually, the quality has come down. We produce over eight lakh engineering graduates every year but only 20 per cent of them get jobs relevant to their degrees. Over 50 per cent of the Indian graduates remain either unemployed or stuck in low-paying unrelated jobs. The Ph.D. holders are applying for peon's job. MBA students are selling vegetables and engineering students are riding delivery bikes. The Government is not only neglecting education but also politicalising it.

Universities are being forced to follow ideological agendas instead of academic independence. Dissenting voices in campuses are being silenced. Students are being labelled anti-nationals for questioning policies. The autonomy of institutions like JNU, DU, IIMs, etc., is being compromised through politically motivated appointments. Recently, there were a lot of anti-social activities, drug abuse and even murder cases reported among minor students below the age of 18. Globally, when you see the study, we find that a child ...(*Time-bell rings.*)... One minute, Madam. The overall development takes place between the age of 3 and 7. If you give good guidance, instruction and education, the child will be successful in future. But when good guidance is not given between the age of 3 and 7, we find that most of the children get diverted to all kinds of anti-social activities. You take the case of Finland from where one of the points of the National Education Policy has been taken. In these Scandinavian countries, the teachers teaching kindergarten or LKG students are given a pay which is much more than what the Principal gets. I request the Government to go through the facts and see what is happening to the children in the country who are indulging in anti-social activities and see that a scheme is drafted for the young children so that they can become successful in future. I am concluding, Madam. I request the Government to increase the education spending to 6 per cent of the GDP as recommended by the experts. ...(*Time-bell rings.*)... Regulate private institutions to ensure that education remains affordable for all.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

SHRI JOSE K. MANI: One more point, Madam. Stop commercializing education instead of strengthening public institutions. A nation that fails its students, its students fail it. A Government that ignores education is writing a death sentence for its own future.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): श्री रामचंद्र जांगड़ा जी। आपके पास पन्द्रह मिनट का समय है।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आज भारत की नई शिक्षा नीति के ऊपर यह चर्चा हो रही है। मैं इसमें भारतीय ज्ञान परम्परा का उल्लेख करना चाहूंगा। वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूपांतरण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही आदमी तमाम बंधनों से मुक्त हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युद्ध का जन्म मन में होता है और मन को सांस्कारिक करना और शांत करने का काम शिक्षा ही

कर सकती है। भारतीय ज्ञान परम्परा में बहुत हद तक आंकड़ों के ज्ञान के बजाय संस्कारों पर ज़ोर दिया गया है। मैं उसी के ऊपर अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा समाहित करूंगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे पास जनसंख्या तो है, लेकिन इसका रूपांतरण जनशक्ति में नहीं हो पाया है। जनशक्ति में रूपांतरण तभी होगा, जब शिक्षा के अंदर नैतिकता आएगी। नैतिकता के बिना ,हम केवल मात्र एक रट्टाफिकेशन के ज़रिए ज्ञान को अर्जित करते रहें और उसमें ज़रा भी नैतिकता न हो ,तो मैं समझता हूं शिक्षा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। महोदया ,शिक्षा का उद्देश्य केवल मात्र बुद्धि का विकास नहीं है ,बल्कि भावनाओं और आध्यात्मिकता का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा वह है ,जो केवल मात्र जीविकोपार्जन नहीं ,बल्कि जीवन का भी निर्माण करे। इसलिए हमारे सामने कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जो लंबे समय से शिक्षा चलती रही ,मौजूदा इंसान के अंदर जो प्रतिभा होती है ,क्या उस प्रतिभा को बाहर लाने में उस शिक्षा ने कोई सहयोग दिया है? क्या हम शिक्षा के द्वारा एक संवेदनशील समाज का निर्माण कर सके हैं? क्या शिक्षा के माध्यम से केवल भोगवादी मनोवृत्ति का ही विकास हो रहा है? क्या शिक्षा केवल डिग्रीधारक बेरोजगार लोगों की फौज है? महोदया ,हमारे सामने बहुत से सवाल हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, एक शिक्षित इंजीनियर अच्छा वेतन लेता है, एक शिक्षित आईएएस, आईपीएस अच्छा वेतन लेता है, वह एक अच्छे और बड़े पद पर भी है, लेकिन यदि उसके मां-बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, उस शिक्षा में कोई नैतिकता नहीं है।

महोदया, यहाँ पर शिक्षा के विषय में बहुत-सी बातें हुईं, हमारे भाई संजय सिंह जी चले गए हैं, उन्होंने मौजूदा शिक्षा के वातावरण पर कई कटाक्ष किए हैं। मुझे अचंभा होता है कि एक आदमी शीर्ष पद पर रहकर यह कहे कि मैं इंजीनियर हूं, मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूं जो हिसाब-किताब के अंदर पूरी तरह से परफेक्ट होता है, लेकिन यदि वही आदमी किसी शराब घोटाले के अंदर जेल जाता है, तो उसकी शिक्षा के अंदर कोई न कोई कमी है, उसकी शिक्षा में नैतिकता नहीं है।

हमारी माननीय सदस्या, कनिमोझी जी यहाँ से चली गई हैं, उन्होंने तमिलनाडु की शिक्षा के ऊपर काफी चर्चा की थी, लेकिन हमें अचंभा होता है कि शिक्षा लेकर, उच्च शिक्षण संस्थानों से निकलकर लोग ऐसे उच्च सदन तक आ जाते हैं, ऊंचे से ऊंचा पद भी ग्रहण कर लेते हैं, परंतु यदि उसके बाद किसी स्पेक्ट्रम घोटाले के अंदर जेल की हवा खाते हैं, तो उनकी शिक्षा के अंदर कोई न कोई कमी है, वह शिक्षा नैतिकता नहीं सिखाती है।

महोदया, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार शिक्षा के अंदर नैतिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा के लिए, जैसा मैंने कहा कि यह केवल मात्र जीविकोपार्जन नहीं है, बल्कि यह जीवन का भी निर्माण करती है, इसलिए शिक्षा के अंदर बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है।

महोदया, भारत में आजादी के बाद इस ओर ज़ोर दिया जा सकता था, क्योंकि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज पर विजय प्राप्ति के बाद 1947 तक, 755 वर्ष तक इस देश ने गुलामी का दंश झेला है। उसके अंदर हमारी ज्ञान परंपरा के ऊपर बहुत कुठाराघात किया गया है। महोदया, भारत वह देश है, जहाँ पर ईसा से 700 साल तक्षशिला

विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया गया था, उसकी स्थापना हो गई थी। महोदया, यहाँ पर ईसा से 400 वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। हमारे देश के अंदर पूरी दुनिया से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर बख्तियार ख़िलज़ी जैसे लोग आए और उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। महोदया, कोई भी वह कोशिश, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को नष्ट कर सकती थी, उन्होंने वह हर संभव कोशिश की।

महोदया, भारत के विश्वविद्यालयों का इतिहास गवाह है कि छह-छह महीनों तक नालंदा की लाइब्रेरी की आग नहीं बुझी थी। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितनी ज्ञान परंपरा थी, वहाँ पर कितना समृद्ध ज्ञान संचित किया गया था, लेकिन लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि आज उसी भारतीय ज्ञान परंपरा के भंडार, नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किया गया है।

5.00 P.M.

अगर शिक्षा को केवल मात्र जीविकोपार्जन का साधन बनाएंगे और कोई नैतिकता नहीं आएगी, तो फिर उस शिक्षा का अर्थ क्या रहेगा? उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ उल्लेख करना चाहूंगा कि विश्व के अंदर किस-किस देश के अंदर जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा के ऊपर खर्च होता रहा है। हमारी पहली शिक्षा नीति 1968 में आई। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। तीसरी शिक्षा नीति में 1986 की शिक्षा नीति को ही दोहराया गया और उसके अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन 1992 में जो शिक्षा नीति आई, उसमें संकल्प लिया गया था कि हम जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा के विकास के ऊपर खर्च करेंगे। हमारे देश के अंदर शिक्षा के ऊपर जो खर्च हुआ है, उसके संबंध में मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। 1951-52 में मात्र 0.64 प्रतिशत खर्च शिक्षा के ऊपर होता था। 1991-92 में यह आंकड़ा 3.4 प्रतिशत था और 2020 से पहले कभी भी 4.3 प्रतिशत से ऊपर यह आंकड़ा नहीं गया। 2020 में 34 वर्षों के बाद जो नई शिक्षा नीति आई उसमें संकल्प लिया गया कि हम कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। उसके अंदर शिक्षा के उद्देश्यों को बदला गया है। मैंने कहा है कि शिक्षा केवल मात्र जीविकोपार्जन नहीं है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 2014 में एक सर्वेक्षण हुआ। सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा के 75 प्रतिशत बच्चे, पांचवीं कक्षा के 50 प्रतिशत बच्चे और आठवीं कक्षा के 25 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि 40 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे, जो 100 के अंकों को नहीं पहचान सकते थे। यह अंग्रेजियत की शिक्षा का परिणाम रहा।

माननीय महोदया, पश्चिमी बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल चन्द्र घोष बने। उन्होंने पूछा कि जो अंग्रेजों के स्वामित्व के कारखाने थे - अंग्रेज तो छोड़कर चले गए - क्या वे कारखाने बंद हैं या चल रहे हैं? उनके सेक्रेटरी ने जब पता किया, तो उनको इन्फॉर्मेशन दी और उनको बताया कि सारे कारखाने चल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि उनको कौन चला रहा है? उन्होंने कहा कहा कि राजस्थान और पंजाब के मारवाड़ी बनियों ने सारे कारखाने खरीद लिए हैं और वे उनको चला रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि उनकी शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर था कि उनमें से कोई भी

मिडिल पास नहीं था, लेकिन वे कारखाने चला रहे थे, क्योंकि हमारी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उसमें उन्होंने गणित की शिक्षा चौथी क्लास तक ले ली थी। हमने भी जब चौथी क्लास पास की तो हमें भी 20 तक के कटवा पहाड़े याद थे। पौना, सवाया, डेढ़, ढाई ये भी याद थे। पांचवी क्लास पास करके कोई भी बच्चा 6 महीने मुनीमी की ट्रेनिंग लेकर किसी भी दुकान पर, किसी भी संस्थान में जाकर मुनीमी करता था, अकाउंटेंसी करता था। आज अगर कोई बी.कॉम, एम.कॉम बच्चा हो, उससे पूछे 19 निम्मा कितने होते हैं, तो वह 171 नहीं बता सकता है, 16 निम्मा कितने होते हैं, तो वह 144 नहीं बता सकता है, 17 निम्मा 153 नहीं बता सकता है। वह कैलकुलेटर उठाएगा और अगर कैलकुलेटर में वायरस होगा, तो वह संख्या भी गलत बताएगा। उसका दिमाग तो काम ही नहीं करता है। हमारी शिक्षा पद्धति, जो प्राचीन पद्धति थी, जो गुरु प्रणाली थी, उसके ऊपर बड़े-बड़े आघात हुए, क्योंकि लंबे समय तक मुगलई काल रहा। हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, जो गुरुकुल की शिक्षा थी, वह मदरसों में चली गई और जब देश आजाद हुआ, 1947 के बाद मदरसा शिक्षा सीधी मिशनरी शिक्षा हो गई और अंग्रेजियत का प्रभाव इस देश के ऊपर हो गया। मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह बात कही थी कि अगर हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखना है तो शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा और इनको यह प्रभाव देना पड़ेगा कि अंग्रेजी जानने वाला आदमी शायद कोई बहुत बड़ा आदमी होता होगा और अंग्रेजी एक स्टैंडर्ड का विषय मान लिया गया। इसलिए सब लोगों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में डालना शुरू कर दिया। अब किसी बच्चे से पूछें कि दो का पहाड़ा क्या होता है, तो उसको याद नहीं है। किसी बच्चे को पूछें कि मामी क्या होती है, यह भी याद नहीं है। किसी बच्चे को पूछे कि बुआ क्या होती है, उसको याद नहीं है। सारे अंकल-आंटी हैं और यह अंग्रेजियत का प्रभाव है। हमारे संबंध खत्म हो गए, हमारी गणित खत्म हो गई। यह अंग्रेजियत का प्रभाव था। इसलिए जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, इसका उद्देश्य केवल जीविका उपार्जन नहीं है। माननीय महोदया, जैसा मैंने कहा है, नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें बच्चों की लिखने-पढ़ने की योग्यता, आधारभूत गणितीय शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना अनिवार्य राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में तीसरी कक्षा तक सभी बच्चे यह शिक्षा हासिल कर सकें, यह लक्ष्य रखा गया है।

माननीय महोदया, जैसा हम कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल वह ज्ञान नहीं है, बल्कि शिक्षा में नैतिकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर कोई एक इंजीनियर बन जाता है और उसकी नजर सरिया और सीमेंट बेचने के ऊपर लगी रहती है, तो फिर उसकी शिक्षा का अर्थ क्या है! कोई एक एडवोकेट बन जाता है और उसकी नजर अपने client को न्याय दिलवाने के बजाय अगर उसकी जेब के ऊपर रहती है, तो उसकी शिक्षा का क्या अर्थ है! एक आदमी डॉक्टर बन जाता है और अगर उस डॉक्टर का नजरिया मरीज का इलाज करने के बजाय मरीज की जेब खसोटने के ऊपर लगी रहती है, तो उसकी शिक्षा का अर्थ क्या है! इसलिए नई शिक्षा नीति में भारत के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लक्ष्य जीविका उपार्जन का नहीं, बल्कि लक्ष्य जीवन निर्माण का लिया है, जिससे व्यक्ति का निर्माण किया जा सके। इसलिए इसके ऊपर बहुत कुछ किया गया है।

माननीय महोदया, मैं इसमें आपको एक सर्वेक्षण की बात कहना चाहता हूँ। 2017 और 2018 में एक सर्वेक्षण किया गया है। अभी संजय जी एक सवाल कर रहे थे, मैं उसका जवाब देता हूँ। 6 से 17 साल तक की उम्र के बच्चे, जो स्कूल से बाहर हैं, उनकी संख्या 3.22 करोड़ थी। यह

लक्ष्य लिया गया है कि 2030 तक शत-प्रतिशत बच्चे स्कूल के अंदर रह कर शिक्षा प्राप्त करें, सरकारी स्कूलों का वह स्तर बढ़े और सरकारी स्कूलों की वह गुणवत्ता रहे कि कोई भी drop-out न हो। नई शिक्षा नीति के अंदर यह लक्ष्य लिया गया है।

मैं अभी बीच में बात कर रहा था कि आज की जो शिक्षा है, rote learning की जो शिक्षा है, मैं उसके बारे में कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले दिनों कोटा से खबर आई कि कितने छात्रों ने आत्महत्या की। शिक्षा प्रणाली के अंदर जो त्रुटियाँ रहीं, मैं इस विषय के ऊपर थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। 10 अप्रैल, 2019 को तेलंगाना बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया था। वहाँ 10 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 3 लाख विद्यार्थी फेल हो गए और 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। हमारे देश में परीक्षा में असफलता का सामना करने के फलस्वरूप आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ी है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में संसद में जानकारी दी थी कि विभिन्न परीक्षाओं में असफल होने के फलस्वरूप देश भर में 2014 से 2016 तक 20,476 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। यह देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है! केवल परीक्षा के अंदर कुछ कम अंक आ गए और बच्चों ने आत्महत्याएँ कर लीं! उनकी शिक्षा का स्तर क्या रहा, उनका मानसिक स्तर क्या रहा? हमारे देश में अग्निवीर योजना चालू की गई। हमारे छात्रों ने करोड़ों-अरबों की संपत्ति आग की भेंट चढ़ा दी। उनकी शिक्षा का स्तर क्या था? उनकी शिक्षा में राष्ट्रीयता थी ही नहीं। अगर शिक्षा में राष्ट्रीयता होती, तो वे स्टूडेंट्स अपने देश की संपत्ति को कैसे स्वाहा करते! मैं मानता हूँ कि उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, बच्चों को बहकाया जा सकता है, बच्चों को इस बात के लिए उकसाया जा सकता है, लेकिन वे उकसे क्यों? उनकी शिक्षा के अंदर राष्ट्रीयता का अभाव था, तभी उन्होंने देश की संपत्ति को अग्नि की भेंट चढ़ा दी। शिक्षा के अंदर राष्ट्रीयता जगे, शिक्षा के अंदर वह गुणवत्ता हो, जिसमें नैतिकता जगे। किसी भी शिक्षित व्यक्ति के माँ-बाप किसी वृद्ध आश्रम में न रहें। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, सड़क के ऊपर कोई घायल आदमी पड़ा हुआ है और हम उसे छोड़ कर चल देते हैं कि मुझे क्या लेना-देना है, क्यों खामखाँ बीमारी मोल लें, कभी मेरे सिर न पड़ जाए, तो मेरी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। उस शिक्षा का कोई मायने नहीं है, क्योंकि शिक्षा में नैतिकता और भावुकता है ही नहीं। शिक्षा तो भावनाओं को जगाने का, आध्यात्मिकता को जगाने का एक साधन होना चाहिए। माननीया, मैं थोड़ा सा वक्त चाहूँगा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, आप एक मिनट में कन्क्लूड कीजिए। अभी और भी लोग बोलने वाले हैं।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: महोदया, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे निराश होकर कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाएँ। मैं आपको इस नयी शिक्षा नीति का उद्देश्य बता रहा हूँ। बच्चे निराश होकर कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाएँ। उनको भविष्य में अपने आपको साबित करने के और भी अनेक मौके मिलेंगे। दुनिया में ऐसे महान लोगों की भरमार है, जो अपने आरंभिक जीवन में फेल होते रहे, किन्तु बाद में उन्होंने इतिहास रच दिया। रात के बाद दिन भी आता है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। वे हार नहीं मानें, अपनी क्षमता को पहचानें और चुनौती को स्वीकार करें, तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी से अपनी तुलना नहीं करें, अपनी गलतियों से सीखें

और उसमें सुधार लाएँ। यह समझना जरूरी है कि जो बच्चे 95 प्रतिशत तक अंक ले आते हैं, तो क्या वे न्यूटन बन जाते हैं, एडीसन बन जाते हैं या आईंस्टीन बन जाते हैं? इसीलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि परीक्षाओं में प्राप्त अंकों से सफलता का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता है। ...(**समय की घंटी**)... सफलता के लिए सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास जरूरी है, शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए, धन्यवाद।

SHRIMATI SUDHA MURTY (Nominated): I thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on this subject.

"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।"

This is the age-old saying. In education system, an excellent education policy, excellent school premises, all those things you can do, but if you do not have a good teacher, it is of no use. Teachers play an important role in education system not only by their qualification, but by their methodology of teaching, convincing, becoming friendly, at times strict and many times very soft. It is an art. Teaching is not by degree, it is an art. And we have forgotten that if you do not have good teachers with all these policies, it is of no use. The system will not improve. I want to request our Education Department people, our Minister that we should care for teachers' training. Many training sessions are there. Once they pass the exam, B.A., B.Ed. or MA, M.Ed. or even PhD at college level, they enter into the system, and afterwards, there are no exams until they retire. This should not happen. Every three years, they should have a new technique or new knowledge and examination should be there. Otherwise, they will not improve. It is not like that one time you pass and you retire with that knowledge. It is of no use. Many teaching programmes are there. People do go there. They get a certificate, but there are no examinations for them. I checked, tried and saw many such schools abroad and other places also. Every three years, a teacher has to appear for an examination with different learning technology because technology changes. Nothing is free in life except mother's love. Everything has a price. So if you want to be a good teacher, there is a price for that. The price is not money; it is good training and examination for the teachers. This method should be more in the primary section because between three to seven or three to nine—one of our esteemed colleagues said—are the formative years. In the formative years, you should have an excellent teacher's training program and teachers should appear and pass. They can make or mar the children and, particularly, build the education system in a good direction. That is the reason our ancestors always felt that a good teacher is the backbone of education and a student, who loves education is *vidyarthi*, who

considers *vidya* as his money or her money, one who is keen to learn and there is a teacher who is keen to teach. That combination only can be successful. If you have students who are not keen to learn, whatever may be the teacher's effort, the result will be nil and void. If you have a great student and you do not have a good teacher, the child will learn, but in a very difficult way. He cannot succeed as much as he or she would have, if you do not have great teachers. As I come from a teacher's family, and I, myself, am a teacher, I am aware of the role of a teacher in education system. A bad teacher can spoil entire batch. A doctor makes a mistake; a patient goes three feet below the earth or six feet below the earth. If a magistrate makes an error, a person will hang six feet above the ground; whereas, if a teacher makes a mistake, the entire batch is spoiled. Teacher is most responsible person in the education system. We should see that the teacher will prosper, with money. Today, I have seen, in primary school section, you get good salary of Rs.60,000 to Rs.70,000. Thank you, Sir. Thank you to our Government which has given excellent service, excellent monetary facilities to teachers. But, I request you to have that training in every three years and examine them. That is the reason our ancestors have told, in the hierarchy in our society, "मातृ देवो भव", mother of the supreme, "पितृ देवो भव", then we say, "आचार्य देवो भव", teacher, I salute them. Thank you very much, Madam, for giving me this opportunity to express my concern about teachers, their benefits and their contribution to the society. We should not forget it. I am the product of what my teachers have taught. I remember them, 'गुरुभ्यो नमः'।

THE VICE - CHAIRPERSON (SHRIMATI SANGEETA YADAV): Thank you. Now, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairman, Madam, on behalf of my AIADMK party leader, Thiru Edapadi Palaniswami, I rise to participate in the discussion on the functioning of the Ministry of Education. With the farsightedness of the AIADMK leaders, like Puratchi Thalaivar MGR, Amma, and Edapadi Palaniswami, in Tamil Nadu, the State has come to the forefront of education and greater enrolment ratio. The founder leader of AIADMK, Dr. MGR, has brought the Mid-Day Meal Scheme and gave free uniform and books to attract students and to retain them and also many engineering colleges have been started during his period.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.*]

Following his footsteps, Amma Dr. Jayalalithaa has given free laptops to students. She has given gold for *Mangalsutra* to ensure that girls have the opportunity

to pursue higher education and lead a better life. And, she also introduced many schemes. Sir, during the period of Thiru Edapadi Palaniswami, understanding the predicament of students of the rural areas, he reserved 7.5 per cent MBBS seats to students who studied in Government school, particularly, in rural areas.

Sir, Tamil Nadu has been following the two-language formula, which is well established. Tamil Nadu is convenient with the two-language formula and, AIADMK Party is also supporting well-defined two-language formula. But, the crisis which is happening in Tamil Nadu -- DMK Government raising this -- is because of the Congress Party. During the Emergency period, Shrimati Indira Gandhi took the education out from the State List and brought under the Concurrent List. But, the DMK never opposed then and afterwards never tried to bring that under the State List. And, Sir, in April, I am telling, there are seven posts of Vice-Chancellors which are going to become vacant in Tamil Nadu. The Vice-Chancellors are not appointed. This is creating problem in higher education. What caused this problem? The problem caused in 2010. During the UPA and the Congress period, the rules were issued which are regulated by the UGC. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please.

DR. M. THAMBIDURAI: During the Congress-DMK period, they brought out that the UGC nominee must be appointed through Selection Committee. It happened in 2010. Who brought that? That is why the DMK is making excuse that the UGC nominee is yet to be appointed, the Governor is not appointing the Vice-Chancellor. They are accusing. Who is responsible? This is Congress and DMK people. They have brought this rule in 2010. How can they blame this Government? And also, Sir, regarding the NEET examination, who brought the NEET examination? In 2010, when Shri Ghulam Nabi Azad was the Health Minister, at that time, Shri Gandhiselvan, the MoS in the Ministry of Health from DMK, introduced NEET. That is the thing. But, the DMK Government made the promise to Tamil Nadu people of opposing the NEET examination. Have they done anything? They are telling that. Don't blame the Central Government. But, they could not do that. But, they are asking amount of Rs. 2,000 crores. Who is responsible for Three-Language Formula? It is the Congress Government. Who introduced Hindi? It is the Congress Government. Why are they continuing with the Congress in I.N.D.I.A.? ...*(Interruptions)*... Who brought all these policies? ...(*Interruptions*)... The Congress Government — now I.N.D.I.A. alliance -- is responsible for all this. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. *...(Interruptions)...*

DR. M. THAMBIDURAI: During their period in power, they laid the groundwork for the current issues — UGC nominees' issue, the Three-Language Formula, imposition of Hindi. Now, they are joining hands with them and playing a blame game against this Government. I am pointing out that this is the real issue.

There are numerous CBSE schools that have come up. Is the DMK Government concerned about this? I want to know from the hon. Education Minister how many CBSE schools were recommended by the DMK Government during their period and given clearance, thereby leading to language problems. Who is responsible for all this? They are shouting against the hon. Education Minister. If the hon. Minister is responsible, I will join them in criticizing. However, the real issue is that the Tamil Nadu Government is facing a crisis. Even when the AIADMK Government was in power, they were also facing crisis. But, they managed everything. Shri Palanisamy managed everything. But, these people are blaming the Central Government. They are providing free liquor, increasing taxes, and people are suffering. There is also a law and order problem, with ladies facing many issues.

The DMK has failed in every field, but the AIADMK party is still advocating for the two-language formula. We do not object to this, but the DMK Government is misleading people. They are just creating drama by putting on black shirts. You want more funds for school education. We have no objection to that.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें।

DR. M. THAMBIDURAI: They are creating all this drama because the 2026 elections are approaching. However, people will not vote for the DMK party. This time, the AIADMK party will win in 2026 due to the DMK's misdeeds. People are well aware of this. They can't brush aside the real issues by raising other concerns to gain votes.

Who imposed Hindi? Who introduced the Three-Language Formula? Who implemented the NEET examination? The Congress and the UPA are responsible for all these decisions. They were partners in the Government. Why are they blaming the current Government? Why could not they resolve these issues during their 18-year tenure as allies of the Central Government? Now, you are protesting here!

The people of Tamil Nadu are clever and know the difference between the DMK and AIADMK Governments. We implemented various programs for higher education without any issues. However, the DMK has failed in the education sector.

Education became a Concurrent Subject due to the DMK Government's inaction in bringing it back under the State List. This crisis is a result of their failure.

We support cooperative federalism and demand sufficient funds. However, the DMK must not mislead the people of Tamil Nadu for political gains in the 2026 elections. People will not fall for this, and they will vote for the AIADMK party. The DMK will be defeated. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद। अब सभी माननीय सदस्य समय का ध्यान रखेंगे और अपने निर्धारित समय में ही बोलेंगे। डा. फौजिया खान, आपके तीन मिनट्स हैं।

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र): सर, *"नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति सत्य समं तपः।"* अर्थात्, विद्या के समान आंख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है। इस विचार को यदि देश ने दिल से अपनाया, तभी भारत विकसित बन सकता है।

Sir, education is the only light. The Budget Speech of the hon. Finance Minister mentioned 'education' nine times saying that good quality school education is the second most important component of *Viksit Bharat*. Here are nine instances that depict the difference between the *kathni* and the *karni* of the Government -- Vision and Action. NEP की कथनी क्या है, विज़न क्या है? Vision है six per cent of GDP expenditure on education. करनी क्या है, एक्शन क्या है, बजट के प्रावधान में लगातार कटौती। Between 2015-16 and 2025-26, expenditure towards Ministry has come down from about 3.8 per cent to 2.5 per cent this year. दूसरा, NEP की कथनी क्या है – it is due importance to foundational learning. एक्शन क्या है -- No clear funds have been allocated for early childhood education. There are no standard curricula or teaching methodologies. Three lakh schools are ungoverned nation-wide. Most schools adopt formal techniques unsuitable for young children's cognitive and social development. This is the age when 80 per cent intellectual development takes place. Is just a short-term training course for *anganwadi sevikas* enough? Where is the dedicated board for pre-primary education, where curricula are framed and methodologies are defined? Nothing is there.

Number three, Sir, *kathni* -- world-class institutions; *karni* -- budget has been reduced by 73 per cent. Number four *kathni* is that there is improved teacher quality. There are many teacher training institutions which fail to meet even minimum infrastructure requirements. There are proxy teachers or government-appointed educators who illegally delegate their responsibilities to others. I agree with Dr. Sudha Murty that teachers should have an examination every three years. पांचवां, कथनी क्या है? That there is balanced pupil to teacher ratio; absolutely not there, Sir. There is a high imbalance of student-teacher ratio in the nation in all Government schools.

कथनी क्या है- employability; करनी क्या है- employment crisis. There is grave skill mismatch. कथनी क्या है - good infrastructure; करनी क्या है -- schools lack toilets for girls, libraries, computers, etc. No Indian institution is there in the QS world rankings. There is significant brain drain. Concurrently, the perilous donkey routes are being used. There is unauthorized migration. Why? That is because of our education system. My only request is increase the budget allocation as recommended in the NEP to make solutions to all these problems. Schools are not just walls and gates, they are stepping stones to brighten our fates. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Thank you. Shri Niranjan Bishi. You have five minutes.

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for having given me the opportunity to speak on the working of the Ministry of Education. The Article 21 of the Constitution of India guarantees free and compulsory education to children. The Right to Education Act describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children. Sir, education is necessary, whether it is quality education, higher education, vocational education or professional education, for the development of our nation. But as a public representative, हम जहां भी जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, कॉलेज में Lecturer नहीं है, यूनिवर्सिटी में Reader नहीं है, Assistant Professor नहीं है, Associate Professor नहीं है और Professor नहीं है, तो बच्चों को कैसे higher education, quality education और professional education मिलेगी? सर, कोरापुट में एक Central University of Odisha है, कोरापुट एक ट्राइबल एरिया है। सर, वहां 137 posts of Lecturer, Reader, Professor, Assistant Professor and Associate Professor are vacant. 89 परसेंट टीचिंग स्टाफ की posts वैकेंट है और 80 परसेंट posts non-teaching staff की vacant हैं। Everybody wants that education should be imparted in mother tongue. Sir, education should be imparted in mother tongue, particularly, to tribal students. So, the Ministry of Education should appoint such teachers who can teach the Scheduled Tribe students in their mother tongue-- Mundari language, bhumij language, kui language, sora language, kosali language and ho language -- so that the tribal students could learn reading and writing and join the mainstream.

Sir, the Government should establish more Eklavya Model Residential schools, more PM SHRI schools, more JNV, Jawahar Navodaya Vidyalaya, schools, and more Central schools like our ex-Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, had opened OAVs in each and every block; 314 OAVs in 314 blocks. So, the Government of India, Ministry of Education, should also establish JNVs, Eklavya Model Residential schools and PM

SHRI schools in each and every block because the population of the students is increasing day by day.

Sir, more than 7 lakh posts of Lecturer, Reader, Professor, Assistant Professor, etc., are lying vacant. If it will be recruited and if the posts are filled up, then 1,57,500 SC/ST candidates will be engaged. In our State of Odisha, 9,000 posts of Lecturer, Reader, Associate Professor, Assistant Professor and Professor are laying vacant. If these posts are recruited, then 3,487 candidates belonging to SC/ST will get job benefit of Lecturers in the colleges and universities.

There is lack of adequate funding for Odisha and also, there is dropout. ओडिशा में ड्रापआउट बहुत ज्यादा होता है। यह राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें एज ग्रुप 6 से 14 है, तो 14 साल तक के बच्चे आठवीं क्लास तक पढ़ते हैं। उसके बाद, particularly, SC/ST students dropout होते हैं, क्योंकि वे दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो ड्रापआउट रेट बढ़ता है, उसके बाद वे माइग्रेंट लेबर होते हैं, चाइल्ड लेबर होते हैं। इसलिए एससी, एसटी स्टूडेंट्स को और देश के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट करना है और एज ग्रुप को 14 की जगह 20 करना है। कम से कम अंडर ग्रेजुएट तक उनको एजुकेशन देनी है। फ्री एजुकेशन, compulsory education up to under-graduate or graduate level, quality education, vocational education, professional education देनी चाहिए।

मैंने टीचर शॉर्टेज के बारे में बोला था। उसके बाद ट्रैवल एरिया में जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, ट्रैवल एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे मिलेगी? अगर वहां नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, उसके पास डिवाइस नहीं है, मोबाइल नहीं है, ई-रीडर नहीं है, तो वह एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना है। जो गरीब बच्चों को फ्री में मोबाइल या अदर डिवासिज़ दे, ताकि वे ऑनलाइन पढ़ सकें।

जो scholarship disbursement होता है, SC/ST को particularly और SEBC students को, उसको भी ठीक टाइम पर स्कॉलरशिप देंगे, stipend देंगे, तो SC/ST बच्चे और SEBC कम्युनिटी के जो बच्चे ड्रापआउट होते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।

उसके बाद वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट में मिनिस्ट्री के efforts in promoting vocational education and skill development in Odisha have been insufficient. There is a lack of coordination between educational institutions and industries. उसको भी देखना है। उसके बाद हमारा ...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री निरंजन बिशि: ओडिशा में 35 Universities हैं ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, किसी भी माननीय सदस्य को उस समय सदन में उपस्थित रहना चाहिए, जिस समय उसका नंबर आए। आप नहीं थे, फिर भी आसन ने आपको समय दिया है। आप कृपा करके समाप्त कीजिए।

श्री निरंजन बिशि: जी, So I request our hon. Minister who is sitting here, hon. Dharmendra Pradhanji, to resolve various demands because the Government of Odisha has given various demands to the Ministry. But the Ministry has not taken concrete steps to resolve the State's long-standing educational issues. Hence, I request the Minister to resolve all issues relating to the State of Odisha.

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the Discussion on the 'Working of the Ministry of Education'. To ensure 100 per cent good and quality education, our Government, led by Shri Narendra Modi, has allocated a total outlay of Rs. 1,28,650 crore and taken up the following steps to improve our educational sector: (1) Fifty thousand Atal Tinkering Labs are going to be set up in Government schools in the next five years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among our young students. (2) Broadband connectivity will be provided to all Government secondary schools in the rural areas of the country under the Bharat Net project. (3)The *Bharatiya Bhasha Pustak* Scheme would be introduced to provide digital form Indian language books for schools and higher education institutions, aiming to help students understand their subjects better. (4) An additional infrastructure will be created in five IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. The total number of students in 23 IITs has increased 100 per cent, from 65,000 to 1.35 lakh, in the past ten years. (5) A Centre of Excellence in Artificial Intelligence for Education will be set up with a total outlay of Rs. 500 crore. Three Centres of AI for Agriculture, Health and Sustainable Cities had been announced in 2023. (6) Rs. 20,000 crore has been allocated to implement private sector-driven research, development and innovation initiatives, announced in the July Budget, 2024. (7) In the next five years, under the Prime Minister Research Fellowship Scheme, our Government will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. (8) A 'Gyan Bharatam Mission' for survey, documentation and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries and private collectors will be undertaken to cover more than one crore manuscripts. (9) National Centres of Excellence for Skilling — Building on the initiative announced in the July, 2024 Budget, five National Centres of Excellence for Skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for 'Make for India, Make for the World' manufacturing. The partnerships will cover curriculum design, training of trainers, a skills certification framework and periodic reviews. (10) Educational reforms and steps towards innovation — Our Government has established a modern educational

system for our students through the 'National Education Policy, 2020'. Opportunities for learning in mother toungues are being provided so that no child is deprived of education. Various recruitment exams are being conducted in 13 Indian languages, eliminating language barriers. To enhance 'ease of doing research' and 'one nation one subscription' scheme, etc. offering free access to international research materials has been introduced recently. *Drone Didi Yojana* has been instrumental in empowering our women, both economically and technically. Our daughters are flying fighter jets. They are joining the Armed Forces and leading corporate companies. Owing to the bold decision and promise to empower *nari shakti* by our hon. PM, our daughters are being admitted to National Military Schools and National Defence Academy. This is a matter of pride for this House and the entire country. We all feel proud of our daughters for bringing laurels and medals in Olympics. In the QS World University Asia rankings, 163 Indian Universities have been included. Inauguration of New Nalanda Univeristy campus has revived India's ancient glory in the field of education. Our Rashtrapatiji has proudly mentioned that 'the day is not far when an Indian citizen would travel to space abroad with an indigenously-developed Gaganyaan spacecraft.' The recent success in space docking has further paved the way for Bharat to establish its own space station and for this our hon. President has also congratulated ISRO and all the citizens on this achievement. (11) The Saksham Anganwadi and Poshan-2.0 programmes provide nutritional support to more than 8 crore children in the Aspirational Districts and the North-Eastern Region. (12) Now, I would like to talk about Viksit Bharat by 2047. Lastly, I would like to express my thankfulness to our hon. Prime Minister and the hon. Education Minister for their meaningful and holistic approach for the development of our nation in the field of education. We all know that 'Viksit Bharat' is a campaign for the welfare and inclusive development of our Bharat by 2047. To achieve this goal, our Government has to be more and more considerate towards the less developed States of the North-Eastern Region. For example, the two-year disturbance in an underdeveloped State like Manipur is a real hindrance to the development. My State, Manipur, is already backward in comparison with other States, but the disturbance has dragged down the State further. It will take a lot more time to bring the development of Manipur at par with that of other States of India. To fulfil the vision of Viksit Bharat by 2047, for educational infrastructure, economic growth, social progress and environmental sustainability etc., we have to bring peace and normalcy first in Manipur. We need a long-lasting and amicable solution for the present crisis in Manipur so that the Viksit Bharat Vision is achieved by 2047. Otherwise, the State of Manipur shall be left behind.

With these few points, I conclude my speech on the Discussion of the Working of the Ministry of Education. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Shri Sandosh Kumar P. You have three minutes.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, it is very difficult even to mention the issues related to the education system within such a short span of time. So, I shall try to highlight one or two points. The problem with this Government is that it always forgets that there is an Article 246 in the Indian Constitution. Article 246 speaks about education, which is in the Concurrent List. With the NEP, the Government is trying to destabilise the federal structure through this new education system. I can show a number of examples, but due to paucity of time, I do not want to elaborate the points. There are N-number of issues. I demand that this NEP should be rolled back.

The second point is related to the imposition of Hindi. Hindi is a very beautiful language and we all love it. There is no doubt at all, but the point is that we have many languages in our country and no language can be termed as the 'regional language'. All languages are the 'national languages'. You cannot find out a term as 'regional language' in the Constitution. Malayalam is a national language. Telugu, Odia, Tamil are all national languages. I stand for all the languages. A large number of people speak Hindi, whereas Malayalam-speaking people may not be that big in numbers, but the point is that all these languages are equally important and it should be the duty of the Government to protect all the languages. We cannot accept any move to impose Hindi.

Now, I come to another point relating to PM SHRI scheme. There N-number of schemes in the name of Prime Minister - PM SHRI, PM Poshan, etc. The point is that Kerala, as a State, is one of the worst sufferers. Rs.530 crores are pending to the State of Kerala during these years because we are not a signatory to the so-called MoU. What does MoU mean? The MoU means that we have to implement this New Education Policy. We already have a well-established education system in Kerala. We have a very good infrastructure. We have spent crores of rupees on this. Now, the Central Government will give us 60 per cent of the same and we have to spend 40 per cent, but what will we have to do for that? We have to put a photo of the Prime Minister and a board also. So, how can we suffer this insult? Our demand is that PM SHRI and related projects must not put a burden on the States and we should get our due share. It is not a question of getting some financial assistance. It is a question of our prestige, and as a State, we deserve our due share. I take this opportunity to

demand the same. Finally, Sir, I would like to make two specific demands. During her Budget speech on 1st February, 2023, the hon. Finance Minister announced 30 Skill India International Centres to be set up across different States. I demand that one such centre should be set up in Kerala.

My second demand is regarding opening of a new Kendriya Vidyalaya in Mattanur where we have a huge airport and infrastructure. Although the quality of teachers in the Kendriya Vidyalayas is horrible and South India has become a dumping ground for this, I still demand for opening of a new Kendriya Vidyalaya in Mattanur.

There are many more issues like Draft UGC Guidelines are there but due to paucity of time, I am not able to cover those issues. I was a student leader and I was part of AISF. Our Education Minister has also been a student leader. I think, we have to protect the interests of the students and upcoming generation and our politics and ideology should not become a burden for the upcoming generation. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद, संदोष कुमार पी जी। श्री रामजी। You have three minutes.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही, मैं अपनी पार्टी की मुखिया, आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने चार बार के शासन काल में उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। साथ ही, मैं सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के महानायक, महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत रत्न बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को नमन करूँगा।

मान्यवर, शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शिक्षा ही देश का भी निर्माण करती है। बहुजन महापुरुषों में महात्मा फुले का शिक्षा के लिए बड़ा योगदान है। उन्होंने देश में लड़कियों और दलितों के लिए 1848 और 1852 में स्कूल खोले और 1882 में हंटर कमीशन के सामने free education for all in India की माँग की। वहीं बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने भी 20 जून, 1946 को सोसाइटी बना कर Siddharth College of Arts, Science and Commerce मुम्बई में खोलने का काम किया।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात नहीं करें। कृपया आप सुनें।

श्री रामजी: उन्होंने अपने उपदेशों में कहा भी कि educate yourself. बाबा साहेब और महात्मा फुले की विचारधारा पर चल कर उत्तर प्रदेश में आदरणीया बहन जी ने कई विश्वविद्यालय खोले। उन्होंने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के

साथ लगभग 5,000 प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी खोलने का काम किया। इसके साथ ही, गरीब बच्चों का ज़ीरो फीस पर एडमिशन लेने का आदेश दिया और इसको सुनिश्चित भी किया। आज तक देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना, जहाँ पर ज़ीरो फीस पर गरीब बच्चों को एडमिशन दिया गया। मान्यवर, इसके साथ ही, स्कॉलरशिप और फेलोशिप, जो आज नई शिक्षा नीति में कई-कई महीनों तक नहीं मिल रही है, उन्होंने उसको टाइम पर दिलाने का काम किया। यहाँ तक कि बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना शुरू की और लाखों बच्चियों को साइकिल और 25,000 रुपए का चेक दिया, ताकि बच्चियाँ 10वीं और 12वीं की शिक्षा को ग्रहण कर सकें।

मान्यवर, आज सरकार की शिक्षा नीति में देश का गरीब बच्चा शिक्षा से महरूम हो रहा है। सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है। शिक्षक स्कूल जाते ही नहीं हैं। वे सिर्फ सेलरी लेने जाते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज आई कि मध्य प्रदेश की शिक्षिका विदेश में रह रही थी, लेकिन वह अपने सरकारी डिपार्टमेंट से सेलरी ले रही थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में शिक्षकों के लिए performance based promotion तय करनी चाहिए। अगर आपका स्कूल का performance अच्छा नहीं है, तो आपकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। आप दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल भी देखिए। प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी बढ़ी हुई है कि गरीब आदमी, मिडल फेमिली प्राइवेट स्कूलों की फीस afford नहीं कर सकती। अगर उसने afford कर भी लिया, तो उनके कोर्सेज़ इतने ज्यादा costly होते हैं, महँगे होते हैं कि वे अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने की बात सोच भी नहीं सकते हैं।

मान्यवर, आज हम देश के अंदर बात कर रहे हैं कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' होना चाहिए। हमने यह भी बात कर ली और 'वन नेशन, वन टैक्स' भी हो गया। यह अच्छी बात है, लेकिन इसी देश के अंदर 'वन नेशन, वन एजुकेशन सिस्टम' क्यों नहीं हो सकता है? अमीरों के बच्चों की एजुकेशन अलग होगी और गरीबों के बच्चों की एजुकेशन अलग होगी, यह नहीं हो सकता। यह देश संविधान से चलता है, इसलिए इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ। मौखिक परीक्षा और viva को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम द्रोणाचार्य पद्धति के टीचर लोग दलितों, पिछड़ों और आदिवासी बच्चों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें।

श्री रामजी: आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों तथा ऐसे संस्थानों के अंदर गरीब बच्चों की शिक्षा free कर देनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई पूरी कर सकें, क्योंकि तमाम एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को शिक्षा से महरूम होना पड़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें, आप ज्यादा समय ले रहे हैं।

श्री रामजीः मान्यवर, मैं 30 सेकंड में समाप्त कर रहा हूँ। सरकार को Right to Education का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ताकि देश में गरीबों के बच्चे भी वहाँ पढ़ सकें। देश में population के हिसाब से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी खोलने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं लास्ट में एक बात और कहूंगा। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का चलन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन भी बच्चों के लिए बहुत खतरा है। वे बच्चे ऑनलाइन बहुत सारी वैसी चीजें देख लेते हैं, जो उनको उस उम्र में नहीं देखनी चाहिए। इसको भी देखते हुए सरकार को कोई न कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... इसके साथ ही, मैं लास्ट में एक बात करना चाहूंगा और लास्ट में यही बात कह कर खत्म करना चाहूंगा कि सरकार को शिक्षा मेला या शिक्षा के महाकुंभ की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि इस देश के नौजवान शिक्षित हो कर उस महाकुंभ में जाएँ और अपने ...(**व्यवधान**)... ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री रामजीः उस हिसाब से शिक्षा को ग्रहण करें, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्री संजय कुमार झा। आज आपके लिए तीन मिनट का ही समय है ।

श्री संजय कुमार झा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर पॉसिबल हो, तो एकाध मिनट बढ़ा दीजिएगा।

महोदय, हमारे इतिहास में भाषा को कभी भी डिवाइज़िव फैक्टर नहीं माना गया है। उदाहरण के तौर पर, जबलपुर में 1,500 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला, काशी में चोल कालीन तमिल शिलालेख मिला, काशी में तमिल संगमम् है, उज्जैन में पांड्य वंश का कॉपर प्लेट मिला, महात्मा बुद्ध के समय के, सातवाहन काल के प्राकृतिक शिलालेख मथुरा में लिखे गये, जो महाराष्ट्र में मिले। बहुत सारे शिलालेख श्रीलंका में मिले। क्या कारण है कि चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य-6 ने कश्मीर के विद्वान विल्हण को उनके काम में मदद की; क्या प्रेरणा थी कि कृष्ण देव राय, जो दक्षिण भारत के सबसे महान राजा थे, उन्होंने बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कवियों एवं साहित्यकारों को सपोर्ट किया? इस प्रकार इस देश में एक-दूसरे को सपोर्ट करने का यह कल्चर रहा है। इसी तरह मैसूर विश्वविद्यालय में अनंत कृष्ण शर्मा हुए, जो प्रसिद्ध तेलुगू पंडित के रूप में जाने गए। वे कन्नड़ शास्त्र और साहित्य में विशेषज्ञ थे। उनके लिए संस्कृत पर मजबूत पकड़ होना आवश्यक था। कम से कम तीन पीढ़ियों के कन्नड़ भाषा के शिक्षक, प्रोफेसर और साहित्यकार बंगला साहित्य के बड़े नाम बंकिम चंद्र और रवींद्र नाथ ठाकुर के काम को पढ़ने और सीखने के लिए, बंगला सीखते थे। वही स्थिति आंध्र प्रदेश में भी रही। एक दशक से अधिक समय तक प्रोफेसर टी.वी. वेंकटलाचल शास्त्री ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध कन्नड़ प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। आज भी लोग तेलुगू भाषा बोलने वाले ऐसे व्यक्ति को बहुत सम्मान देते हैं, जो संस्कृत और तेलुगू दोनों में निपुण हो। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मिथिला क्षेत्र से, वहां हमारे कवि कोकिल विद्यापति हुए, जो हमेशा राधा-कृष्ण पर लिखते थे।

उनका बड़ा प्रभाव बंगाल में रहा और उनका बड़ा प्रभाव ओडिशा के लोगों में रहा। मैं मानता हूं कि जिन महान व्यक्तियों ने एक भाषा से दूसरी भाषा सीखने की स्वस्थ परंपरा बनाए रखी, उसे बढ़ावा दिया, वे स्वाभाविक रूप से ओपन माइंड के थे। उन्होंने लिबरल ट्रेडिशन को फॉलो किया। उनकी जाति और मातृभाषा केवल संयोग हो सकती है। इसलिए कन्नड़ साहित्य में बहुत प्रतिष्ठित नामों की उत्पत्ति गैर-कन्नड़ जाति से होती थी। डी.वी. गुंडप्पा, मस्ती वेंकटसा, टी.वी. कैलाशम, ये सब तमिल थे। वहां डी.आर. बेंद्रे मराठी थे, जो कन्नड़ भाषा में पढ़ाते थे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां के नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा हमेशा होती है। अभी एक हिस्टोरियन, विलियम डेलरिंपल ने अपनी एक बुक लॉंच की है और उसमें उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है। उनकी जो किताब आयी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस समय में नालंदा विश्वविद्यालय ही पूरी दुनिया का ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड था और वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते थे। बहुत से चाइनीज ट्रैवलर्स नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़ाई करते थे। अब हमारे मुख्य मंत्री, नीतीश कुमार जी ने उसका काम शुरू किया और हाल ही में आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वहाँ जाकर नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। वहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र रहा है।

मैं एक बात और कहूँगा। चूंकि माननीय मंत्री जी यहां पर हैं, मेरा यह मानना है और मुझे लगता है कि यह जो language है, भाषा है, कल्चर है, यह बड़ी यूनिफाइंग रही है और वह कभी डिवाइज़िव रही ही नहीं। मेरा मानना है कि यह शिक्षा का विषय मैटर ऑफ कंटेस्ट नहीं होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... यह किसी के लिए नहीं होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... फ्रैंक स्मिथ, जो एक British psycholinguist हैं, उन्होंने कहा कि 'One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way." इसलिए मुझे लगता है कि इसको ...**(व्यवधान)**... Three languages also. इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए मुझे लगता है कि इसमें contest नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री जी के द्वारा नई शिक्षा नीति में जो काम हो रहा है, वह प्रोग्रेसिव है और हम लोग इनका बिल्कुल समर्थन करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद, संजय कुमार झा जी। डा. जॉन ब्रिटास। आप हमेशा इतना लेट आते हैं, फिर भी आपका समय रहता ही है।

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I am from Kerala and Kerala has shown the way to this country how we have to conduct ourselves in the field of education.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): हम तो केरल के शंकराचार्य जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर ही चल रहे हैं।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I seek your indulgence and request for three-four minutes extra. I fully appreciate my dear friend Sanjay Kumar Jha *ji* because he talked about the diversity of this country. Actually, he was trying to convey a message to the BJP. I am sure about it. He also said that they should not be fussy about the language.

Yes, they should not be fussy about the language. You should be liberal. This country has rich diversity. The moment you dictate terms from Delhi to a State, there ends the diversity. Sir, you know that anyone who speaks from the Treasury Benches harks on emergency. During the emergency, there was 42nd Amendment to the Constitution through which education was taken out of the State List. If they are genuine and honest, I would request them to revert that. Give back education to States, if you are genuine. Sir, please appreciate the fact that the very party which ridicules Congress on emergency, actually benefits out of the emergency now. They actually feast on emergency. I respect my friend, the hon. Minister. He is a thorough gentleman. But I do not support his policies. He is intending for a complete takeover of higher education. The UGC guidelines came. He knows what the implications of the guidelines are. There are 1,074 universities in this country. Hardly, 54 are Central Universities. There are a few private universities also. You know what he wants to do. He wants to take over all the universities built by the sweat and blood of the States. This is what he has done. If he speaks about federalism, he should immediately withdraw the guidelines which the UGC has issued. I appreciate that every language is our language. Hindi is our language. But the moment you start a pattern of uniformity like one leader, one political party, one religion, one language, etc., there ends this country. This country belongs to all. Hon. Minister was kind enough. He withdrew a reference which was made in the Lok Sabha. But, even then, I would urge upon him, please don't make Kerala to learn from another State. We have gone ahead.

Sir, the scheme of this Government is very interesting. They start a Centrally Sponsored Project. They will contribute some amount. They want States also to contribute. Do you know what they do? They want to brand the entire scheme. They contribute something for the housing scheme where three-fourths would be spent by the States. But they want to brand it as their scheme. Just look at the *Samagra Shiksha Abhiyan*.

6.00 P.M.

An amount of Rs. 849 crore due to Kerala has been withheld. Do you know why? It is because we are not implementing PM SHRI scheme. PM SHRI was never part of Samagra Shiksha Abhiyan. Even for PM SHRI, State has to fund 40 per cent. You are such a seasoned politician; you understand the implications. Kerala has crossed the threshold. Some bureaucrats here prepare a scheme. They want the States to follow. We have already crossed that stage; we have gone ahead. So, what is suitable to

Bihar or Odisha may not be suitable to Kerala. Am I correct, Dr. Thambidurai? Yes! Sir, please allow me. I am from Kerala. I told you that we are showing light to this country in the field of education. Please give me three more minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका समय समाप्त हो रहा है, अब आप समाप्त करें।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am concluding. My point is very simple. The hon. Minister has to stop this business of centralization of everything in Delhi. Stop it; respect the State Governments. Please understand that there are talents. There is a vision from every State Government. Mr. Sanjay Jha supports BJP but he spoke about the rich diversity of this country like in Tamil Nadu, Kerala, Odisha, etc. He is from Odisha. The Member from Odisha, who spoke, said that Odisha is starved in the entire higher education; there is no staff and nothing. My only submission to the hon. Minister is, please uphold the spirit of the Indian Constitution.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया समाप्त करें।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, one last comment! If they are honest and sincere with regard to their stand on Emergency, please make sure 'Education' is given back to the States. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद। हमें सात बजे तक बैठना है। कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में यह तय हो गया था कि 6 घंटे हर विभाग पर चर्चा के लिए दिए जाएंगे, इसलिए सदन का टाइम 7 बजे तक का है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपके तीन मिनट्स हैं।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): सर, जब हम छोटे थे, तो उस समय मोहम्मद रफी जी का एक गाना होता था- *"नन्हे-मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी।"* उस तकदीर को बनाने में एक बड़ी अहम भूमिका हमारी शिक्षा निभाती है, तो हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ियों की एजुकेशन को लेकर और आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर हम अपनी राजनीति को अलग रखकर इस पर चर्चा करें।

सर, जब हम शिक्षा की बात करते हैं और तकदीर की बात करते हैं, तो हाल ही में एक ASER रिपोर्ट आई थी। ASER रिपोर्ट में करीब 6.5 लाख बच्चों की रीडिंग स्किल्स और मैथमेटिकल स्किल्स का टेस्ट लिया गया था। मुझे दुर्भाग्य से यह बोलना पड़ रहा है कि जब क्लास तीन और पांच के बच्चों का लैंग्वेज टेस्ट लिया गया, रीडिंग टेस्ट लिया गया, तो majority of the children क्लास 2 लेवल की टेक्स्टबुक भी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ पा रहे थे। इसी तरह, जो मैथ का सिंपल डिविजन टेस्ट था, उसमें क्लास 8 और 5 के majority of the children could not do it. यह हमारे लिए एक चिंताजनक बात है कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वह

बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं? ...(**व्यवधान**)... चलिए, यह 2024 का है,सर। आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। Mr. Jayant, I am sure, you will correct me. सर, मैं 2024 की बात कर रही हूँ।

सर, मैं तीसरी बात यह बोलना चाहती हूँ कि ये लोग आगे आकर पढ़-लिख भी लें, हायर एजुकेशन की तरफ भी जाएं, तो पिछले 10 साल में ऐसे करीब 89 separate cases हुए हैं, जहां पर पेपर लीक हुआ है। उसकी वजह से इस देश के 6.5 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं। सर, महाराष्ट्र में हाल ही में चुनाव हुए, वहां डबल इंजन सरकार बनी। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार स्टेट बोर्ड के 10^{th} और 12^{th} के पेपर भी लीक हो गए। यह पहली बार हुआ है। यह शर्मनाक बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

सर, आरबीआई की एक रिपोर्ट है, जो बताती है कि ऐसे करीब 25 लाख युवा हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और उनको स्टूडेंट लोन की जरूरत पड़ती है, जिनमें से करीब 70% विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। हमारे सामने वह भी एक चैलेंज है कि वे विदेश क्यों जाते हैं, क्यों हम अपने देश में ही ऐसे इंस्टिट्यूशंस नहीं बना पा रहे हैं, जहां पर वे पढ़ाई कर सकें? ऐसे 25 लाख युवा हैं, जो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से सिर्फ 7 लाख को यह मिलता है, बाकी बच्चों को पर्सनल लोन लेना पड़ता है, जिसका rate of interest 12 से 14 परसेंट है और कहीं-कहीं तो यह 14 से 18 परसेंट है। मैं मानती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं - खासकर वे महिलाएं, जो पढ़ाई करना चाहती हैं, कैसे उनको लोन अच्छे से मिल सके, इस पर ध्यान देना है।

सर, बजट में IIT की बात हुई थी। निर्मला जी ने कहा कि IIT के students को लेने के लिए सीट्स और बढ़ाने वाले हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, मैं एक ही मिनट लूंगी। I will wrap up.

सर, IIT के जो students होते हैं, वे इस उम्मीद से इस कॉलेज में जाते हैं कि अच्छी शिक्षा तो मिलेगी ही, साथ ही, अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा। आईआईटी मुम्बई हो, आईआईटी गुवाहाटी हो, वहां job placement में गिरावट देखने को मिली है। आईआईटी दिल्ली में भी गिरावट देखने को मिली है।

सर, मैं जिस ASER रिपोर्ट की बात कर रही थी, उस रिपोर्ट में एक और चीज़ सामने आई है – access to smart phones. जैसे-जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए access to smart phones बहुत ज़रूरी है। उसमें भी जेंडर का जो divide है, वह बहुत obvious है। अगर 70 परसेंट पुरुषों के पास स्मार्ट फोन का access है, तो सिर्फ करीब 60 परसेंट महिलाओं के पास smart phone का access है। इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (बिहार)**:** महोदय, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से भारत सरकार और विशेषकर शिक्षा विभाग का धन्यवाद करता हूं। साथ ही, आदरणीय प्रधान मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। इनकी ओर से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी पहल की जा रही है। महोदय, समय तो बहुत ही कम है, लेकिन मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं:

"विद्या बिना मति गयी,
मति बिना नीति गयी।
नीति बिना गति गयी,
गति बिना वित्त गया।
वित्त बिना शूद्र गए,
इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए।।"

महोदय, यह पंक्ति आज की नहीं है। अब से लगभग पौने 200 साल पहले, एक महान महापुरुष ने इसे कहा था, जिनका नाम हम सभी बहुत सम्मान के साथ लेते हैं-महात्मा ज्योतिबा राव फुले। उस समय के समाज में, जो व्यक्ति समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा था, उसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा और विद्या का क्या महत्व हो सकता है, इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह पंक्ति कही थी।

हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, और यदि हम महात्मा फुले का नाम न लें, तो यह चर्चा अधूरी रह जाएगी। हम महात्मा फुले साहब के चरणों में नमन करते हैं। साथ ही, हम सरकार का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बहुत जोर-शोर से की है और इसे ईमानदारी से लागू भी कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में शिक्षा की नितांत आवश्यकता है।

पहले, शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से कम थी, लेकिन सरकार की पहल के कारण अब स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक परिवर्तन है। परंतु जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी लगभग पौने 200 साल पहले, तब भारत में किसी भी जाति या धर्म की महिलाओं के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे, उन्हें शिक्षा की अनुमति नहीं थी।

ऐसे समय में, महात्मा फुले साहब ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, उन्हें खुद शिक्षक बनाया। हमारे देश में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में हम सावित्रीबाई फुले का नाम सम्मानपूर्वक याद करते हैं। महोदय, जब वे अपने पति से शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षिका बनीं, तब उन्होंने इस देश में महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय स्थापित किया। उसी समय से महिलाओं को शिक्षा का अवसर मिल रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय कुशवाहा साहब, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, वैसे

ही 3 जनवरी - जो माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है - को "महिला शिक्षक दिवस" के रूप में पूरे देश में मनाने का निर्णय भारत सरकार को लेना चाहिए।

अब भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन समयाभाव के कारण, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Shri Masthan Rao Yadav Beedha. आपके पास तीन मिनट का समय है।

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the Discussion on the Working of Ministry of Education. On behalf of TDP leader, Nara Chandrababu Naidu Garu, I participate in this discussion. Over the last three decades, we all witnessed the rise of Andhra Pradesh and its proud Telugu community not just in India, but all across the world. I am proud to state that the Telugu Desam Party, under our founder Shri NTR Garu and the present leader hon. Nara Chandrababu Naidu Garu, has been at the forefront of educational development of Andhra Pradesh and our country.

Our leader has often said that the foundation of a prosperous and progressive society is 'Education'. Under NTR Garu, we set up Andhra Pradesh's first all women institution- Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam. It is thriving to this very day. He championed an early form of the Mid-Day Meal Scheme for children in schools so as to provide them all possible nutritional support and help them focus on their education and revamped the A.P. Residential Programme to provide quality education to rural and socially disadvantaged youth. Under Nara Chandrababu Naidu Garu, world class institutions, such as the Indian School of Business, were established to give all Indians an opportunity to world class education and help grow India.

In the recent Budget, our State Government has re-affirmed its commitment to education with its programmes such as Thalliki Vandanam under which Rs. 15,000 to mothers for sending children to school would be given, Sarvepalli Radhakrishnan Vidyarthi Mitra, under which free books, uniforms and supplies for 35.69 lakh students and free electricity for all Government schools would be given. This underscores the importance of education given by our Government and its commitment to the development of education in A.P.

Respected Vice-Chairman, Sir, our party leader, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, has often said that we must not restrict our thoughts to Indian languages and international languages. Why stop at three when we can offer ten? This will not only open opportunities for students to travel the world, but it would also help the

Indian community integrate with other countries seamlessly becoming leaders of the next generation.

As I conclude, I would like to end with a quote for all our students across India from our former President and visionary Dr. A.P.J. Abdul Kalam: "When knowledge is lit, economy flourishes". Jai *Bharat*, Jai Andhra Pradesh. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, I call upon the hon. Minister of Education to reply to the discussion.

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज आपने इस पवित्र गृह में शिक्षा के ऊपर Vote on Account के माध्यम से पिछले छह घंटे से एक सार्थक चर्चा करने की अनुमति दी।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

इस सदन के अत्यंत सम्माननीय 29 माननीय सदस्यों ने अपने सुविचारित अभिमत को रखा। मैं सबसे पहले आपका तथा सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज इस चर्चा को बहुत समृद्ध किया, उसकी बहुत गरिमा बढ़ाई। मैं सभी का व्यक्तिगत रूप में आभारी हूं।

उपसभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए, सभी ने अपना अभिमत रखा। एक डेमोक्रेसी में शिक्षा जैसे विषयों में यह अपेक्षा करना उचित भी नहीं है कि सभी का मत एकरूप हो जाएगा। यदि विद्वानों की एकरूपता हो जाती, तो मानव सभ्यता का रूप और कुछ होता। इसको आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इस विषय में सब सहमत थे कि कोई भी सभ्यता की मूल रीढ़ होगी, तो इस देश की शिक्षा-व्यवस्था होगी, उस देश की नई पीढ़ी होगी। आज सबने उस विषय को दोहराया है, सब ने इस अच्छी बात को प्रकाशित किया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि जब से माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश की सेवा करना शुरू किया है, तब से वे वर्षवार वित्तीय प्रबंधन, financial allocation शिक्षा के ऊपर बढ़ा ही रहे हैं।

महोदय, तथ्य यही कहता है। 1,28,650 करोड़ रुपये, पिछले वित्तीय अनुदान से जितना हुआ था, उससे लगभग 6.22 प्रतिशत की वृद्धि इस बार के बजट में भी हुई है। 2013-14 में स्कूली शिक्षा में वित्तीय प्रबंधन 52,701 करोड़ रुपये था और 2025-26 के वित्तीय वर्ष में यह अनुदान बढ़कर 78,572 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। वित्तीय अनुदान की यह वृद्धि सरकार की प्रतिबद्धता प्रमाणित करती है। अगर आज हम अपने देश में एज ग्रुप वाइज पॉप्युलेशन की विशेषकर कैल्कुलेशन करते हैं, तो अमूमन थोड़ा इधर-उधर हो सकती है, क्योंकि कुछ राज्यों की पॉप्युलेशन स्टेबलाइज हुई है और कुछ राज्यों की पॉप्युलेशन ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया स्टेटेस्टिक्स देखते हैं, तो the population of an age-group is around two crores. आज शिक्षा व्यवस्था में एज थ्री, प्री स्कूल एजुकेशन का एनईपी ने परामर्श भी दिया है। हमारे देश में बाल आंगनवाड़ी एक पुरानी व्यवस्था है। अभी हमने उसमें बाल वाटिका के एक नए

पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। इस तरह से उसमें भारत सरकार का महिला बाल विकास विभाग और भारत सरकार का शिक्षा विभाग दोनों मिलकर काम करें। इन दोनों में पूरा सामंजस्य है, दोनों मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत काम करेंगे। क्योंकि न केवल देश के, बल्कि विश्व के विशेषज्ञ यह मानते हैं कि बालक और बालिका का छोटी उम्र में ही मानसिक विकास हो जाता है, इसलिए पहली बार एनईपी में भारत सरकार ने एक नीतिगत निर्णय किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी हमारे साथ है। अभी तीनों संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग बैठे थे। क्योंकि आज देश में लगभग 100 परसेंट institutional birth होता है, उसका पंजीयन होता है, इसलिए वह बच्चा सीमलेस्ली आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल तक कैसे जाए, इस पर भी काम हो रहा है। देश के पिछड़े इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, बस्तियों में बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं, संपन्न लोग प्ले स्कूल में भेजते हैं, लेकिन उसको धीरे-धीरे एक करिकुलम फ्रेमवर्क में, एक common curriculum framework में मिनिमम इकट्ठा कर पाएं, इसीलिए आज हम एज 3 से 18 तक, यानी 12वीं तक इस स्कूल एज ग्रुप को देखेंगे, तो उसमें 15 साल में लगभग 30 करोड़ बच्चे होंगे। उन 30 करोड़ बच्चों की देखभाल करने के लिए काम करना जरूरी है।

महोदय, उनकी दो प्रमुख देखभाल हैं — एक तो उनका न्यूट्रिशन और दूसरा उनकी एजुकेशन। इन दोनों के बारे में मैंने 1,28,000 करोड़ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के 78,572 करोड़ के आंकड़े को एजुकेशन के दायित्व के लिए बताया है। उनके अलावा हेल्थ और डब्ल्यूसीडी के खर्चे भी उसके ऊपर आते हैं। हम सब लोग आज इनके लिए प्रतिबद्ध हैं। महोदय, इस अर्लि एज के लिए एनईपी में कहा गया है कि बच्चा तीन साल से चार, पाँच साल तक आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में आए। हमारे देश में कई जगह पर आंगनवाड़ी और बाल वाटिका कोलोकेटेड हैं। हमारे इस बार के बजट में भी सक्षम आंगनवाड़ी की कल्पना की गई है, पोषण 2.0 की कल्पना गई है। उसके लिए भी अलग वित्तीय प्रबंधन किया गया है।

महोदय, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। दोनों की कैलोरी वैल्यूज़ सब लोगों को मिले, कोई भी किसी स्कीम से कवर हो, इसका प्रयास हो रहा है। आज डिजिटल की दुनिया में हमारे पास पिन पॉइंटेड अकाउंटिंग की व्यवस्था है, सब लोग आभा की आईडी से रजिस्टर होते हैं, बाद में वह स्टूडेंट आईडी अपार में कन्वर्ट होती है। आभा, अपार मिलाकर - जो कि आधार एनेबल है, आज इन सभी का पंजीयन किया जाता है। उन सभी की देखभाल हो, सभी लोग इंस्टिट्यूशन में आएं - डिलीवरी से लेकर प्रि स्कूल एजुकेशन तक, इंस्टिट्यूशन में डेली आएं और एज सिक्स से आगे फॉर्मल स्कूल में आएं, क्लास वन में आएं — इसके लिए सरकार की आज यह व्यवस्था है। हमने उनके लिए नई शिक्षा नीति में जोर दिया है। प्ले बेस्ड एजुकेशन हो, सॉन्ग बेस्ड एजुकेशन हो, लोकल स्टोरी, लोकल डांस, लोकल ड्रामा आधारित एजुकेशन हो, भाषा में और कथा कहानी में जितनी स्थानीयता आ पाए- ये सभी बातें सरकार की रणनीति का हिस्सा है। इस पर डब्ल्यूसीडी और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।

उपसभापति जी, मैं कई सारे विषयों को छुऊंगा। उपसभापति महोदय, शिक्षा पर एक intensity के साथ और इमोशनल अटैचमेंट के साथ सभी ने अपनी बातें कहीं। कुछ-कुछ विषयों पर उनके मन में जो जिज्ञासा है, जो कुछ शंका है, मैं उनका उत्तर देने की विनम्रता से कोशिश करूंगा। महोदय, मैं प्रारंभ में आपके माध्यम से सरकार की नीति के बारे में इस सदन में कुछ बातें रखना चाहूंगा। मैं शिक्षा विभाग के इस बार के वित्तीय एलोकेशन के तीन उपक्रमों के बारे में आपके

सामने एक फेज में उल्लेख करना चाहूंगा कि वे क्या हैं। अभी बहुत सदस्यों ने कहा कि सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया जाता है? क्या प्राइवेट स्कूल ज्यादा बढ़ेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम मोदी जी की सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। इसीलिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक ही स्ट्रोक में इस बार के बजट में निर्णय हुआ है कि देश में जितने सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सभी सेकेंडरी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड की इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाई जाएगी और इसके लिए भारतनेट को काम दे दिया गया है। भारतनेट ने वह काम शुरू कर दिया है।

उपसभापति महोदय, पहले हमारे देश में शिक्षा की प्रायोरिटी एक डिग्री लेना और एक नौकरी की तलाश में मिनिमम ज्ञान को इकट्ठा करना था, लेकिन आज जिस स्टेज में हमारा देश पहुंचा है और हमारे देश के नौजवानों की जो मेधा है, वह पहले भी थी, लेकिन पहले हमारे देश में प्रायोरिटी ब्रेड-बटर और मिनिमम एमेनिटीज़ थी, लेकिन आज aspiration नई ऊंचाई तक पहुंच रही है। देश एक बड़े गांव का हिस्सा हो चुका है। हम आज एक बड़े गांव में, एक यूनिवर्स में रहते हैं। एक छोटे गांव में भारत एक इलाका है। उसमें हमारे नॉलेज लेवल को न केवल भारत के लिए बनाना, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए बनाना है। हमें विश्व गुरु नहीं बनना है, हमें विश्व बंधु बनना है। यह आज हमारी सरकार की philosophy है। माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम विश्व बंधु का दायित्व लेने वाले हैं। इसलिए जब जी-20 के प्लेटफार्म पर विश्व के सम्पूर्ण देश एकजुट हुए, उस समय हम लोग यह नहीं भूले कि हमारा दायित्व ग्लोबल साउथ के नाम पर विश्व के गरीब देशों की प्रति भी है। जब जी-20 के अवसर पर ग्लोबल साउथ का कॉन्क्लेव हुआ, तो उस समय एजेंडा क्या था? उस समय एजेंडा था कि उन देशों में शिक्षा कैसे होगी? उन देशों की best practices क्या हैं? भारत उनमें क्या मदद कर सकता है? हेल्थ में क्या हो सकता है? रिसोर्स जनरेशन में क्या हो सकता है? भारत पिछले 10 साल में 30 करोड़ लोगों को गरीबी से उठाकर ऊपर लेकर आया है। यह अनुभव आज भारत एक बंधु के नाते, एक गुरु के नाते नहीं - कभी जमाने में यह शब्दावली इस्तेमाल की गई होगी - आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि हम विश्व बंधु बनना चाहते हैं। इसलिए अपने देश के बच्चों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना है। हमने पिछले सात साल में अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से 10 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की हैं। सभी स्कूल में टिंकरिंग लेबोरेटरी होती है, लेकिन हमने उनका स्तर बढ़ाया है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please Dr. John Brittas, no interruption.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: I need your protection, Sir. John Brittas*ji*, you are a good friend of mine. At least, I listened to you very aptly. Please bear the democracy at least. You are a knowledgeable person. And you are a person from Shankaracharya's place. Please bear that.

आज इस सरकार ने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में एक ही स्ट्रोक में निर्णय किया कि यह कार्य हम आने वाले पांच साल में करने वाले हैं। हर एक टिंकरिंग लैब की स्पेंडिंग शायद आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में एक टिंकरिंग लैब पर 20 लाख रुपये की स्पेंडिंग होगी। अभी 10 हज़ार हैं और 50 हज़ार नई अटल टिंकरिंग लैब्स pro rata में आबादी

के हिसाब से दिया जाएगा और उनको चैलेंज रूट पर दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक प्रमुख स्थान पर हब एंड स्पोक मॉडल पर एक साइंस लैब, एक इनोवेशन सेंटर, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का कल्चर बन पाए। यह अटल टिंकरिंग लैब का प्रमुख उद्देश्य है। यह इस बजट की एक प्रमुख योजना है। यह fews के लिए नहीं है, बल्कि यह योजना सभी के लिए है। एनईपी की एक प्रमुख रिकमंडेशन है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा कि इसमें कुछ वैचारिक दृष्टिकोण है, एक पटुता है। Yes, I don't hide that also. हमारा एक दृष्टिकोण है कि भारत की सभ्यता को कैसे देखना है?

इस देश की जनता ने हमें स्वीकृति दी है। हम इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के पास गए थे। एक बार नहीं, हम तीन-तीन बार गए हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम किसी भी विषय को किसी के ऊपर लादना नहीं चाहेंगे, लेकिन भारतीयता के ऊपर हमें नाज है, भारतीय भाषाओं के ऊपर हमें नाज है। इसलिए इस बार के बजट में 'भारतीय भाषा पुस्तक योजना' शुरू की गई है। भारत में 22 scheduled languages हैं और उनके साथ ही English भी है, इस तरह से 23 languages हैं। भारत की 22 scheduled languages में कम से कम एक हजार पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँगी। एक हजार पाठ्य पुस्तकें 22 भाषाओ में! शायद तमिलनाडु की mathematics की पुस्तक असम के विद्यार्थियों को काम आएगी। शायद पंजाब के literature का कोई विषय ओडिशा में inspire करेगा। शायद ओडिशा की कोई पाठ्य पुस्तक गुजरात को inspire करेगी। इसलिए आज भारत का जो रत्न भंडार अनेक भाषाओं में छुपा हुआ है, इन सबको उजागर करना इस सरकार की priority है। आज हमने 'भारतीय भाषा पुस्तक योजना' लागू करने का दायित्व लिया है। इस बजट में उसके बारे में उल्लेख किया गया है।

उपसभापति जी, उच्च शिक्षा में 2013-14 में कितनी spending होती थी? उच्च शिक्षा में 2013-14 में 26,750 करोड़ रुपए की spending होती थी। इस बार बजट में हमने वित्तीय प्रबंधन किया है - 50,077.95 करोड़ रुपए। मैं विनम्रता के साथ यह सूचित करना चाहूँगा। आज हमें उच्च शिक्षा को वैश्विक करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, माननीय प्रधान मंत्री जी मानते हैं कि सर्टिफिकेट, डिग्री, इसका अपना एक महत्व है, लेकिन competency, हुनर, कौशल, skill, उसका अपने आप में बहुत महत्व है। आज हमारे देश में नौजवानों को, अभी की existing workforce को global standard तक ले जाने के लिए हमें heavily invest करना पड़ेगा। हमें अपनी emerging technology को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ job का जो नया landscape बन रहा है, हमें new landscape of job के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए पिछले बजट में माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें जो दायित्व दिया था, अगर मैं उसको याद करूँ, तो AI in Healthcare, AI in Agriculture, AI in Sustainable City, इन पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले बजट में तीन Centre of Excellence बनाने का दायित्व दिया गया था। इस बार सरकार ने AI for Education के दायित्व के लिए 500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। IITs की सीटें बढ़ाई गईं। Prime Minister Research Fellowship (PMRF) में 5 साल में 10,000 बच्चों को उच्चतर गवेषणा के लिए NET UGC के द्वारा चलने वाले NET JRF के beyond science students के लिए 10,000 नई scholarships की योजना बनाई गई। उसका परिणाम यह है कि आज हम सरकार का जो डाटा देखते हैं, उसमें drop out rate काफी मात्रा में घट रही है। यह primary level पर घट रही है, secondary level पर घट रही है। शिक्षा में महिलाओं की participation बढ़

रही है, primary में बढ़ रही है, secondary में बढ़ रही है। एससी, एसटी, ओबीसी, तीनों वर्गों में आज entry level पर participation बढ़ रही है।

अभी PM POSHAN, PM SHRI, ऐसे flagship programmes, जो NEP को complement करते हैं, ऐसे सारे प्रोग्राम्स के बारे में कई विषयों के ऊपर चर्चा हुई। मैं थोड़ा एक-दो विषय के ऊपर clarification भी देना चाहूँगा। शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में चर्चा हुई, शिक्षकों की capacity बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। मैं आगे थोड़ा और specifically कहूँगा, लेकिन अभी इस स्टेज पर मैं कहूँगा कि शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर जो DIET है, इन सारे DIETs को धीरे-धीरे Centre of Excellence बनाया जाएगा। जो नए टीचर्स हैं, उनके ऊपर सबने चिंता की। हमारी आदरणीया सुधा मूर्ती जी ने सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की कि हमारे शिक्षकों की दक्षता बढ़नी चाहिए। उपसभापति जी, हमारे देश में आज 25 करोड़ स्कूली विद्यार्थी हैं, जिनमें 4 करोड़ उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं। जब मैं 25 करोड़ कहता हूँ, तो उसमें entry level पर GER लगभग 100 परसेंट है; secondary level पर यह 80 परसेंट है; higher secondary level, यानी 11वीं, 12वीं में यह संख्या घट कर 75 परसेंट है। यानी ऊपर की कक्षाओं में वह drop out भी थोड़ा 20 परसेंट, 25 परसेंट है। In higher education, it is around 27 to 28 per cent. इसको और भी आगे बढ़ाना है। यह सब करने के लिए शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

महोदय, सभी सदस्यों ने बहुत महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। हम लोग उनको निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। मैं एक ही प्रमाण देना चाहूंगा कि DIET को मजबूत करने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत - सबने कहा कि समग्र शिक्षा में यह नहीं था, वह नहीं था, यह क्यों आया? वह पहले नहीं था, लेकिन जब सबने ध्यान दिया कि शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, तो हमने एक mid-course step लिया कि हमें priority देखनी पड़ेगी। NEP ने ही teachers' capacity building के लिए कहा है। इसलिए हमने हरेक DIET को मजबूत करने के लिए tailor-made DIET की बात की है। जिस DIET की जो आवश्यकता है, इसके बारे में यह कोई informed scheme नहीं है। सबने कहा कि आप इसे मत थोपिए। हमने राज्यों के साथ परामर्श किया। राज्य के उस particular DIET को कहा कि आप एक स्केल बनाइए कि आपको क्या चाहिए। भारत सरकार उस हिसाब से tailor-made DIET बनाने के लिए अपनी मदद बढ़ा रही है।

उपसभापति जी, NEP में एक विषय भाषा के बारे में कहा गया है। आज मैं कहूं, तो भारत एक बहुभाषी देश है। इसके राज्य और इसकी यूनियन टेरिटरीज़ में उसका जो cultural group/area है, cluster है, उसमें अनेकों भाषाएँ बोली जाती हैं। हमारे ओडिशा के सांसद, बिशी साहब ने आदिवासी भाषाओं के बारे में कहा। मैं इसको स्वीकार करता हूं। NCERT ने 104 भाषाओं में, सभी राज्यों की 104 भाषाओं में, primer बनाया है, उसे द्विभाषी बनाया है, इसीलिए ताकि बच्चों को पढ़ने में और समझने में सुविधा हो। आज literacy में संख्या बढ़ रही है।

महोदय, कई विषयों पर एक सैद्धांतिक बात कही जाती है कि भाई, हम बहुत सी भाषाएं क्यों पढ़ेंगे? यह सबका मत हो सकता है। पिछले दिनों संविधान सभा में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। कभी-कभी देश की प्रमुख पार्टी, कांग्रेस पार्टी को समय के हिसाब से स्टेंड बदलना चाहिए, लेकिन वह progressive होना चाहिए, regressive हो - एक स्टूडेंट के नाते मैं कभी-कभी पब्लिक पॉलिसी में घबराता हूं। संविधान सभा में आप ही का बोलबाला ज्यादा था। नेशनल लीडरशिप ने

किस आधार पर चर्चा की थी, उसमें भाषा को लेकर क्या चर्चा हुई थी, उसमें क्या consensus बना था कि हम कैसे आगे बढ़ें? मैं इसीलिए बड़ा emotional होकर कहता हूं।

महोदय, मुझे पिछले 24 घंटे में बहुत सी बातें सुननी पड़ीं। मैं इस देश की पहली भाषा-आधारित प्रशासनिक इकाई का सुपुत्र हूं, ओड़िया आदमी हूं। उपसभापति जी, हम आप ही से बन कर आए हैं। 1911 में Bengal Presidency से पहले आप और हम अलग हुए थे, फिर 1936 में आपने हमें छोटे भाई के रूप में मान्यता दी। इस तरह, मैं पहले भाषा-आधारित राज्य का व्यक्ति हूं। भाषा का अपने आप में महत्व है। इस देश में पिछले 78 सालों में भाषा को लेकर बहुत सी बातें कही गई हैं। NEP ने भाषा के बारे में क्या कहा है, उसको मैं आज आपकी अनुमति से इस पवित्र सभागृह में उद्धृत करना चाहूंगा।

उपसभापति जी, आज भारत के बारे में विश्व क्या मानता है? भारत छोड़िए, विश्व इसके बारे में क्या मानता है? जब कोई सदस्य वरिष्ठ सदस्य कहेंगे - मैं खरगे जी की अनुमति लेकर उनका नाम लेना चाहूंगा। जब यहां चर्चा में दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, तो खरगे जी जैसे सीनियर व्यक्ति थोड़ा उठ कर बोले कि आप भारत के कुछ इलाकों को भाषा के नाते अलग करना चाहते हैं। माननीय खरगे जी, ऐसा नहीं है। आप जिस इलाके से आते हैं, वह बहुभाषी है। वहां कन्नड़ भाषा है। मैं गुलबर्गा के बारे में जानता हूं। मैं वहां गया हूं। वह हैदराबाद-कर्नाटक का पुराना हिस्सा है। वहाँ हिंदी भी, चालू हिंदी भी और उर्दू आधारित हिंदी भी समझी जाती है। वहां इंग्लिश तो है ही, लेकिन वहां एक-दो स्थानीय लैंग्वेजेज़ भी हैं, तेलुगू भी है। क्या हम इस विविधता को अस्वीकार कर दें? आज विश्व क्या कह रहा है? इस बार 2024 में "the impact of multi-lingualism on global education" के बारे में चर्चा हो रही है। 2023 में "Multi-lingualism and job market in the EU" पर चर्चा हो रही है और हम कहां फंसे हैं? क्या किसी का अधिकार हरने के लिए, किसी को आहत करने के लिए, भाषा का उपयोग करेंगे? कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह पाप न तो कभी किया है और न ही आने वाले दिनों में करेगी। हमारा दृष्टिकोण अलग है। हाँ, यह विचारधारा का विषय है। हम 'वसुधैव कुटुंबकम्' में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम दुनिया के मानवों को एक परिवार की दायित्वदारी मानने वाले लोग हैं। हमको यह बात मत पढ़ाइए। हम विभेद करने वाले लोग नहीं हैं। आज शिक्षा हमें यह उपलब्ध कराती है। आज शिक्षा में enrolment बढ़ा है। आज Gross Enrolment Ratio में पिछले दशकों की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज देश के अंदर कुछ चुनौतियाँ हैं। देश के नौजवानों की aspiration आसमान छू रही है। इस समय में उनकी डिग्री का महत्व, उनकी क्षमता और competency की उपयोगिता का समायोजन - ये सरकार के सामने चुनौतियाँ हैं, इसलिए education और skill development पर ध्यान देने की जरूरत है। इसको कोई अलग दुनिया और सरकार ने नहीं माना है। हम लोगों ने आज इनको एकरूप करके इसके लिए एक roadmap बना कर 21वीं सदी के मानव को सबल बनाने के लिए यह चिंता की है।

उपसभापति जी, कई माननीय सदस्यों ने research के बारे में तरह-तरह की बातें की हैं। यह कहा गया कि रिसर्च का पैसा घटाया गया है तथा रिसर्च के बारे में कई प्रकार के तथ्य यहाँ पर बताए गए हैं। मैं दो-तीन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2015 में क्या स्थिति थी और 2022 में क्या स्थिति है? 2015 में इस देश में 1,45,000 research publications होते थे और आज 2022 में research publications की संख्या 2,73,000 है। यह हमारी उपलब्धि है। Engineering

specific research में 165 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसलिए आज देश में ज्यादा patents मिल रहे हैं और हम startup ecosystem में दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। यह ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि उसके लिए कुछ योजनाएँ बनाई गईं और उनकी उपलब्धि आज सामने आ रही है। Patent file में 93 परसेंट की ग्रोथ हुई है। 2014 में 42,763 पेटेंट्स हुए थे और आज 2023 में 82,881 पेटेंट्स हुए हैं। Global Innovation Index ranking में हम 2014 में 76वें रैंक पर थे और आज हम बढ़ कर 39वें रैंक पर पहुँचे हैं। यह ऐसे ही नहीं हुआ है। आज लगभग 2,500 उच्च शिक्षण संस्थान और 300 यूनिवर्सिटीज़ में R&D cell खुल गया है। आज Smart India Hackathon देश की उच्च शिक्षा की बहुआकांक्षित योजना बन चुकी है।

उपसभापति जी, महाराष्ट्र के पुणे में महाराष्ट्र सरकार का एक मर्यादा संपन्न इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं उस कॉलेज में एक बार समावर्तन उत्सव में गया था। मैंने इसी Smart India Hackathon में participate किए हुए एक लड़के के इनोवेशन को देखा। उस लड़के को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता है, वह मराठी बोलता है। उन्होंने क्या इनोवेशन किया है? उन्होंने यह इनोवेशन किया है कि मनुष्य के शरीर में laser-welding कैसे होगा, मनुष्य के शरीर के अंदर लेज़र से कैसे जुड़ाव होगा, उन्होंने उसकी एक टेक्नोलॉजी निकाली। उसको स्वास्थ्य विभाग ने मान्यता दी है। उस लड़के से पूछा गया कि इसमें तुम्हारा कितने का व्यवसाय हुआ है? उसका डेढ़ करोड़ रुपए का बिजनेस दो साल पहले हो चुका था। आज और भी बढ़ चुका होगा। आज हम यह नया भारत बना रहे हैं। यह भाषा की monopoly के कारण नहीं हो रहा है। इनोवेशन तब हो पाएगा, जब एक व्यक्ति जिस भाषा में बचपन से सीखा है, समझा है, उसी भाषा को लेकर आगे बढ़ेगा, तब जाकर वह इनोवेशन कर पाएगा। यह एनईपी की उपलब्धि है।

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनईपी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन थी। उसकी कमेटी बन गई है। उसके वित्तीय प्रबंधन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई है। आज 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' है। पहले एक लाइब्रेरी के लिए एक महंगा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। भारत सरकार ने अपना पैसा खर्च करके सारी लाइब्रेरीज़ को इकट्ठा करके एक सब्सक्रिप्शन लेने का प्रावधान किया। इसके लिए लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप एक करना चाहते हो! अगर एक करने में देश के सामान्य गरीब विद्यार्थियों को अच्छा material उपलब्ध होगा, तो इसमें आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? आपको उसका स्वागत करना चाहिए। मैंने रिसर्च इकोसिस्टम और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में उल्लेख किया। आज हमारे देश में इसका नया परचम लहरा रहा है।

उपसभापति जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इन दिनों में स्पेस की नीति में परिवर्तन किया है। पहले स्पेस में सरकार की monopoly होती थी। सरकार ने तय किया कि उसको हमारे नौजवानों के लिए समर्पित किया जाए। हमारा नौजवान low orbit satellite बना सकता है। सर, मैं खुद चेन्नई के रिसर्च पार्क, मद्रास आईआईटी में देखकर आया हूँ कि वहां तमिलनाडु के ग्रामीण युवक, जो किसी आईआईटी में नहीं पढ़े हैं, उन्होंने अपनी ही टेक्नोलॉजी से स्पेस में जाने वाला low orbit satellite बनाकर उड़ा भी दिया है। यह आज उच्च शिक्षण संस्था की योजना के कारण संभव हो रहा है।

उपसभापति महोदय, मेरी बहन, आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा कि ऐसे 25 लाख युवा हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और उनमें से 70% बाहर जाते हैं। प्रियंका जी, वे ऐसे नहीं जाते हैं। हमारे पास जो इमीग्रेशन डिपार्टमेंट और एमईए से प्राप्त तथ्य हैं, उनके अनुसार यह आंकड़ा vary करता है और इधर-उधर मिलाकर यह लगभग 15 लाख के अंदर है। इसमें दो-तीन देशों के डेस्टिनेशंस शामिल हैं, जो 15 लाख के अंदर हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे देश में ही उनको पढ़ने का अवसर मिले। हम PMRF 10,000 क्यों देते हैं? हमारे देश के विद्यार्थियों में ताकत है। उनको यहीं पढ़ाने के लिए, यहीं के इंस्टिट्यूशंस को और मजबूत करने के लिए हमने आईआईटी को महत्व दिया, एनआईटी को महत्व दिया। Anusandhan National Research Foundation में हमारी संस्थाओं की कैपेसिटी बढ़े, इसके बारे में हमने दायित्व लिया है।

सर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज Skill development एक priority का विषय है। मैं आपको इसका एक मानक बताता हूँ। QS Rankings, जो विश्व की one of the quality measuring agencies है, उन्होंने कहा कि 2014 में ऐसे 10 इंस्टीट्यूशंस थे और 2024 में ये 46 हुए हैं। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। Ph.D. enrolment में वर्ष 2014-15 में 1,70,000 विद्यार्थी होते थे, जो आज बढ़कर 2,33,000 हो गए हैं। सर, जैसा कि मैंने पेटेंट के बारे में कहा, पेटेंट में भारत पहले, 2013 में 8^{th} पोजिशन पर था, लेकिन आज 6^{th} स्थान पर पहुंच गया है। मैं यह World Intellectual Property Organization के तथ्य बता रहा हूँ। हम start-up ecosystem में तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं।

उपसभापति महोदय, अब मैं इससे भी महत्वपूर्ण एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। एक International Science Innovation Tracking Agency, ASPI - Australian Strategic Policy Institute है। वे लंबे समय की ट्रैकिंग करते हैं और उन्होंने 2003 से 2007 तक भारत का एक assessment किया था। उसमें विश्व की जो पहली 5 टेक्नोलॉजीज़ थीं, उनमें से केवल चार टेक्नोलॉजीज़ में भारत किसी एक पोजीशन पर था। आज उन्होंने पूरी दुनिया में 46 critical areas की टेक्नोलॉजीज़ के काम की ट्रैकिंग की। उन्होंने दुनिया के किसी भी देश में यह ट्रैक किया कि वहां उन 46 critical areas में टेक्नोलॉजी के क्या-क्या काम हो रहे हैं। आज उनमें से 45 में भारत या तो पहले 5 में है या 2 में है। ये क्षेत्र क्या हैं, मैं इनके बारे में बताता हूँ। ये क्षेत्र हैं - advanced materials manufacturing, advanced information and communication technology, biotechnology, gene technology and vaccines and energy environment. आज हमारी जो साइंटिफिक उपलब्धि है, उसकी स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने यह उल्लेख किया।

उपसभापति महोदय, यहां कई विषय उठाए गए, यहां कई तथ्यों के बारे में चर्चा की गई। माननीय सदस्यों ने यहां कई विषय उठाए और उनमें से सबसे पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कुछ तथ्यों को रखा। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूछा कि इसकी accessibility क्या है? अभी मैंने इसकी accessibility के बारे में भी कुछ विषयों का उल्लेख किया। आदरणीय प्रियंका जी ने ASER के बारे में उल्लेख किया। मैं इन दोनों को जोड़कर एक उत्तर देना चाहूंगा। ASER हर 2 साल में एक सर्वे करती है। यह एक न्यूट्रल बॉडी है और कभी-कभी यह हमको भी थोड़ा निष्पक्ष दृष्टि से देखती है। इस बार की जो ASER की रिपोर्ट आई, उसके बारे में मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। Reading And Arithmetic में - क्लास 2 के standard के question को ऊपर की क्लास के बच्चों से पूछते हैं और learning outcome का हिसाब करते हैं। पहले देश में बहुत ही

चिंताजनक अव्यवस्था थी। वर्ष 2018 में standard three में उसका आउटकम 20.9 परसेंट था, इतने बच्चे पढ़ पाते थे। वर्ष 2022 में कोरोना के कारण यह घट गया। अभी क्लास 3 के standard के बच्चे क्लास दो की परीक्षा में कैसे करते हैं, अभी यह बढ़कर 23.4 परसेंट हो गया। यह घटा नहीं है, यह बढ़ा है। पहले 2018 में क्लास 5 में यह 44.2 परसेंट था, वर्ष 2022 में कारोना के कारण घटकर यह 38.5 परसेंट हो गया। इस बार यह बढ़कर 44.8 परसेंट - लगभग 45 परसेंट हो गया। ऐसे ही, गणित की बात करूं, तो गणित में भी performance बढ़ कर ऊपर आयी है। क्लास 3 में पिछली बार 26 परसेंट था, जो इस बार बढ़कर लगभग 34 परसेंट तक आ गया है। क्लास 4 में पिछली बार के 25.6 परसेंट से बढ़कर 30.7 परसेंट तक आया है।

पिछले दिनों में प्राइवेट स्कूल्स की तुलना में गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रति रुझान बढ़ा है। सरकारी स्कूल्स में learning outcome ज्यादा है। लोग पूछते हैं कि NEP का क्या अर्थ है, तो मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में दक्षता धीरे-धीरे आगे बढ़े। इसीलिए इस बार ASER रिपोर्ट के बाद जो लेख आया है, उस लेख में यह आया कि NEP energy देखने को मिली है, FLN का सफल रूपायन हो रहा है, जिसके बारे में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी स्वीकार किया है कि FLN के बारे में हम सबको मिल कर उसे आगे बढ़ाना चाहिए।

आपने एक विषय कहा कि अभी के NCERT की नई approach में सांप्रदायिकता की झलक दिखती है। मैं ज़िम्मेवारी के साथ कहूं - उन्होंने एक घटना बताई कि गांधी जी की हत्या के बारे में कुछ विषय को delete किया है। NCERT एक स्वतंत्र संस्था है, उन्होंने कुछ संशोधन किया है। मैंने भी अखबार में पढ़कर इसकी जानकारी हासिल की। वर्ष 2005 में जिस टोली ने उसको लिखा था, उसका उद्देश्य क्या था। गांधी हत्या में जो हत्यारा था, उसके बारे में एक सर्वमान्य समीक्षा है, लेकिन क्या उसको दर्शाते हुए यह बताना कि भारत की कोई एक जाति या वर्ग ही उसके लिए ज़िम्मेवार है, क्या हमें बच्चों को यह पढ़ाना चाहिए? क्या यह पढ़ाना चाहिए कि ब्राह्मण वर्ग के लोग ज़िम्मेवार हैं? क्या हमें इसकी अनुमति देनी चाहिए? क्या यह मूल विषय था? इसमें सांप्रदायिकता ...(**व्यवधान**)... नाम लिखो, क्या आपत्ति थी? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: John Britasji, no comments please. ...*(Interruptions)*...

श्री धर्मेंद्र प्रधान: जॉन ब्रिटास जी, अपनी बात ज़ोर से कहने से सत्य कभी असत्य नहीं हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं yield नहीं कर रहा हूं। मैं फ्लो में बोल दूं, फिर मैं दिग्विजय सिंह जी के एक-दो प्रश्न ले सकता हूं।

मेरे मित्र रीताब्रता जी...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: उपसभापति महोदय, वह निकाल दें। यह गलत चीज़ है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will see. ...*(Interruptions)*... खरगे जी, मैं कह रहा हूं कि examine करेंगे। आप बैठ जाएं। मैंने कहा कि हम examine करेंगे। आप सुनते नहीं है, खड़े हो जाते हैं।

श्री धर्मेंद्र प्रधानः आप ही ने किया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Khargeji, please sit down. ...*(Interruptions)*... प्लीज़, आप बोलें।

श्री धर्मेंद्र प्रधानः उपसभापति महोदय, मैं अपने मित्र रीताब्रता जी की dilemma को समझ सकता हूं। वे लेफ्ट से एकदम राइट आये हैं, लेकिन पहले उधर जो दिख रहे थे, उसकी तुलना में अब वे और भी अच्छे लग रहे हैं। इसलिए मैंने उन्हें कॉम्प्लिमेंट दिया, "Looking more handsome. Keep it up." लेकिन उन्होंने कहा कि कभी-कभी पुराना hallucination रहता है, तो क्या किया जाए?

My dear friend, Ritabrata, आपने कहा कि NCERT ने भारत के कुछ जन आंदोलनों को हटा दिया। हाँ, हमने हटाया है, लेकिन क्यों? क्या हम इस देश में बंदूक उठाने वाले, लोकतंत्र को नहीं मानने वाले नक्सलवाद को जन आंदोलन कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसी कारण इसे हटाया गया। कृष्ण जी कौन थे? जिस पार्टी में आप पहुंचे हैं, उस पार्टी ने कृष्ण जी को क्या किया? यह नहीं चलेगा। आप चीज़ों को सिलेक्टिवली कह देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यदि तर्क होना है, तो पूरा तर्क होगा। इस देश को सारे विषयों को समझने का अधिकार है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RITABRATA BANERJEE: I spoke about... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ritabrata ji, please listen to the hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: I would like to answer that also. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Nothing has been omitted. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the hon. Minister speak. आप बोलिए।

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, nothing has been deleted from anywhere.

During the Covid period, some rationalization has been done by the NCERT. What they had to do, they have done and they have corrected their mistake. जो गलती हुई है, उसको सुधारने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत बातों को जस्टिफाई करने में डेमोक्रेसी में चिंता बढ़ती है। यह उचित नहीं है। अभी मेरे मित्र इमरान जी बोल रहे थे। अभी शायद वे यहां उपस्थित नहीं हैं। वे कहां से तथ्य लेकर आए हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं है। मुझे पता नहीं है

कि प्रतापगढ़ी जी ने कौन-सी कविता पढ़ ली है, उन्होंने किसकी कविता पढ़ ली, उसके बारे में वे ही जानें, लेकिन जो authentic data UDISE है, राज्य सरकारें जो तथ्य एक प्लेटफार्म पर डालती हैं, That is known as UDISE. UDISE में primary school teachers की training capacity 88.2 परसेंट मेरे सामने है। Pre-primary की 89 परसेंट training capacity है, secondary की 90.7 परसेंट है और higher-secondary की 89 परसेंट है। यह ट्रेन्ड टीचर्स की अभी की स्थिति है। मैं सुधा मूर्ती जी की बात को स्वीकार करता हूं कि उन्होंने जो कहा ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak. ...*(Interruptions)*...पहले सुन लीजिए। Please have patience to listen. ...*(Interruptions)*...

श्री धर्मेंद्र प्रधानः उन्होंने कहा कि तीन साल के अंदर continuous training होनी चाहिए, मैं उनकी इस बात को स्वीकार करता हूं। इसलिए हमने DIET को मजबूत किया। DIET में continuous upgradation, training, skilling, upskilling होती रहेगी, यह हमारा अभिमत है।

उपसभापति महोदय, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति Concurrent List में है। अनेक राज्यों में अनेक सरकारें हैं। अनेक राज्य सरकारें इस समय नियुक्तियां भी कर रही हैं, लेकिन मैं केवी और जेएनवी, दो शिक्षण संस्थानों के बारे में थोड़ा तथ्य रखना चाहूंगा। केवी में 2004 से 2014, दस साल में 19,059 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थीं। 2014 से 2024 के अंदर 33,952 टीचर्स नियुक्त हुए थे। यह रिकॉर्ड है और यह बात ठीक है। टीचर्स भी अलग-अलग एज के होते हैं। वैकेन्सी होती है। हमारी सरकार घर नहीं बैठी है। नियुक्ति मेले के माध्यम से हरेक महीने में हमने नियुक्ति देना जारी रखा है। It is a continuous process. हम दस साल का आंकड़ा आपको दिखाएं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपने 19 हजार किया और हमने 33 हजार किया। आपको स्वाभाविक अच्छा नहीं लगेगा। हमने इन दिनों में नवोदय विद्यालय में 7,000 fresh appointments की हैं। यह भी एक continuous process है।

उपसभापति महोदय, अभी higher education की टीचर्स के बारे में चर्चा हुई। मैं एक ही तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। Higher education में in 2014, in the higher education sector, in total, 37 per cent posts were vacant when there were 16,217 sanctioned posts in Central Universities. At that time, 57 per cent Scheduled Castes, 63 per cent Scheduled Tribes and 60 per cent of OBC posts were vacant. यह उनकी performance की guarantee थी। अभी हमारे मित्र मनोज झा जी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मनोज जी अनुमति लेकर गए हैं।

श्री धर्मेंद्र प्रधानः मनोज झा जी ने एक विषय 'Not Found Suitable' के बारे में कहा। यह मेरे लिए ताज्जुब की बात है। उनकी जो शंका है, वह सही है। यह होता था कि पहले उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में देश की संवैधानिक व्यवस्था को मान्यता नाम के लिए दी जाती थी। इंटरव्यूज़ होते थे, लेकिन 'Not found suitable' category दिखाई जाती थी और फिर उन सांविधानिक सुरक्षित

वर्गों के अधिकार का हनन करते हुए उसे general category में परिवर्तित किया जाता था। महोदय, यह practice कब से हो रही थी? आज़ादी के उपरांत SC/ST reservation चला, मंडल कमीशन के बाद 90s में OBC reservation हुआ और यह भी तभी से चला। मान्यवर, 'not found suitable' का मंत्र तो आप ही जानते हैं, आप ही ने उसको चलाया है। देश में पहली बार माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी एक क्रांति लेकर आए और मैं आपके सामने वे तथ्य दिखा रहा हूं।

महोदय, 2019 में Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act लाया गया। पहली बार, आज़ादी के इतने सालों के बाद, 2019 में मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद कई एमपीज़ ने उन्हें एप्रोच किया कि सर, हमारा यह अधिकार छीना जाता है। SC/ST MPs, OBC MPs उनसे मिले और पहली बार भारत की संसद, लोक सभा और राज्य सभा में कानून बनाया गया कि 'not found suitable' is abolished. यह नहीं चलेगा। खाली है, खाली रहे, लेकिन उन्हें भरना पड़ेगा। किसी ने कहा कि पहले Assistant Professor में Ph.D. रखते थे, आपने उसको उठा दिया है। हाँ, हमने उठाया है, यह हमारे समय में लिया गया निर्णय है कि अच्छा बच्चा घर के प्रेशर में नौकरी में जाएगा या पीएचडी के नाम पर चार-पाँच साल बिताकर नौकरी मिलेगी, इसकी अपेक्षा करेगा? इसीलिए हमने विश्वास करके 'not found suitable' का जो षड्यंत्र है, उसको ढूंढ़ा। एक्ट बन गया है, फिर भी टीचर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि उनकी योग्यता की capacity में इतने विषय क्लिष्ट किए गए हैं कि वे नहीं मिलते हैं। यह तथ्य है और इसको सभी को सपोर्ट करना है। महोदय, 2019 में इस हाउस में हुआ था। आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय तक राज्यों में, देश में शासन के दायित्व में रहे, आपके पास तो आज भी घड़ियाली आँसू बहाने की दक्षता है, फिर आपने क्यों नहीं किया? हम करें, तो आप कहते हैं कि आपकी विचारधारा अलग है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी विचारधारा गरीब कल्याण है, हमारा विचार एससी/एसटी वर्ग का उत्थान है।

उपसभापति महोदय, मेरे मित्र रीताब्रता और मेरी बहिन नूर जी ने बंगाल का उल्लेख किया। महोदय, मैं बंगाल के बारे में कितना कहूँ, कितना मर्यादित रहूँ, कितना अमर्यादित रहूँ, क्यों कहूँ - वह बात एक तथ्य है। महोदय, अभी सीएजी की रिपोर्ट में कुछ तथ्य आए। बहुत पुराने नहीं, तीन साल पहले के तथ्य आए। कुछ कंप्लेंट्स आईं, बंगाल से कोई पब्लिक पेटिशन आई कि वहाँ का PM POSHAN का पैसा, भारत सरकार का जो पैसा जाता है, जो किसी निर्दिष्ट बैंक एकाउंट में रहता है, वह उस बैंक से बाहर आ गया। महोदय, उस पैसे से वहाँ के सत्ताधारी दल के कुछ अंदरूनी झगड़े के कारण जो हानि हुई, उस हानि में किसी को compensation दिया गया, PM POSHAN के पैसे से उसका मुआवजा भरा गया है। यह जो तथ्य आया है, यह तथ्य कोई आपत्ति नहीं थी, हमने इसे नहीं माना, क्योंकि ऐसा होता रहता है, पब्लिक पेटिशन्स डलती रहती हैं। हमने उसे उठाकर CAG से special audit करवाया। उसमें वही तथ्य निकलकर सामने आया। अभी CBI की inquiry चल रही है, इसमें हम क्या करेंगे? भारत सरकार के, बंगाल के हिस्से के, गरीबों के पैसों को अगर कोई पार्टीबाजी में खर्च करे, तो क्या यह देना चाहिए? यह कैसे दे सकते हैं? क्या नियम यह कहता है? सर, यही विषय है। हम क्या कर पाएंगे? आपको भारत के नियम, कानून मालूम हैं। आप सत्ता में आए हैं, अच्छा है, लोगों ने आपको चुना है, आप सेवा कीजिए, लेकिन मैं इस पर आपके बारे में क्या कहें? अभी आपके शिक्षा मंत्री कहाँ हैं? किसी शिक्षा मंत्री के घर में किस प्रकार का पहाड़ मिला है, यह कहते हुए हमें भी शर्म आती है। सर, हम पुरानी

Bengal Presidency का हिस्सा हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। जो बंगाल एक समय में शिक्षा की सरस्वती की भूमि होता था, रबीन्द्रनाथ टैगोर जी की भूमि होता था, विवेकानन्द जी की भूमि होता था, अरबिंदो की भूमि होता था, उस राज्य के शिक्षा मंत्री ऐसा करें! हे प्रभु! सर, इसके लिए क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? सर, सच बहुत कड़वा होता है। इसके लिए क्या करें, किंतु सत्य का सामना करना चाहिए। प्रजातंत्र में आप कुछ कहेंगे, तो आपको थोड़ा सुनना भी चाहिए और सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। यह बंगाल की स्थिति है।

7.00 **P.M.**

जॉन ब्रिटास मेरे बहुत परम मित्र हैं। वे सदन के आदरणीय सदस्य हैं। वे केरल के ऊपर बहुत प्राइड करते हैं। मेरा भी केरल पर बहुत अभिमान है। हमारा कोई भेदभाव नहीं है। यूनिवर्सिटी के बारे में - वे मेरी मर्यादा जानते हैं और मैं भी उनकी मर्यादा जानता हूं – लेकिन साहब, क्या यूनिवर्सिटी है! अभी आदरणीय तंबी दुरै जी भी उल्लेख कर रहे थे। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के बारे में और टीचर्स स्टैंडड्र्स के बारे में जो विवाद उठा है, क्या वह 2025 में उठा है? हम जो विधि-व्यवस्था लाए हैं, यूजीसी ने जो रेगुलेशन्स, रिफॉर्म्स का एक मसौदा पब्लिक डोमेन में रखा, क्या यह सिर्फ अभी आया है? यह सब आजादी के पहले भी था और आजादी के बाद भी चला है। 2010 में आपके ही समय में, जिसको आदरणीय तंबी दुरै जी क्वोट कर रहे थे और उन्होंने राइटली याद दिलाया कि तब किसकी सरकार थी? उस समय किसने भूमिका बनाई? उसका इस बार थोड़ा इन्क्रीमेंटल सुधार किया गया है। उस प्रस्ताव को रखा गया है और आप उस पर सुझाव देंगे, तो मिल बैठकर उसे आगे कर लेंगे। जॉन ब्रिटास साहब, क्या हम यूनिवर्सिटीज़ में राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित लोगों का अप्वाइंटमेंट कर दें? यह मूल विषय है। ...**(व्यवधान)**... आप बड़े आदमी हो। मैं तो ओड़िया आदमी हूं। हमारे यहां एक कहावत है। मैं ओड़िया में कह देता हूं – बिशी बाबू आपको हिंदी में समझा देंगे – 'बड़े आदमी को उत्तर नहीं, आसमान को कोई सीढ़ी नहीं'। दिग्विजय सिंह जी मेरे लिए अत्यंत श्रद्धेय हैं। हम बचपन से उनका नाम सुनते आ रहे हैं। वे देश के बड़े नेता हैं। मैं उनको क्या कहूं? ...**(व्यवधान)**... साहब, ऐसा मत कहो। अगर कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा - मैंने इसलिए कहा और मैंने जॉन ब्रिटास से पहले अनुमति ले ली थी। ...**(व्यवधान)**... 'Should I?' मैंने कहा कि नाम कहूं, उन्होंने कहा, 'Don't do that.' इसलिए मैं उसे नहीं कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं नहीं कह रहा हूं। वे अपनी मर्यादा रखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। What about my understanding of Kerala? What is the commitment of this Government towards Kerala? There is an institution called National Book Trust. It is a very prestigious Publication House of the Government of India's Education Ministry. Recently, the NBT has published a book written by Captain Litty Chacko. She is a Professor from St. Josheph's College, Irinjalakuda. Is my pronunciation right? In one of the programmes, I met a few sisters from a church. They came to see me. They said, 'Sir, we have a Centre for Ancient Civilisation Studies. We have some ancient documents. Can you help us in publishing it as a book?' I asked the NBT if it can do something to help them. In February, I got an opportunity to dedicate the book. This

book is published by a Christian organisation of Kerala and written by Captain Litty Chacko. She might be a Christian lady. I don't know. I don't mind that. What was the topic? They have selected the topic. I have not selected the topic. I have not suggested that. The topic was: Life and Contribution of Sangamagrama Madhava. Who is Madhava? Madhava is a mathematician of 14th century from Kerala. The research Pandulipi was developed and scientifically preserved by a Christian body. This is my understanding of a minority institution. This is not an issue of appeasement. This is my understanding of Kerala. We never discriminate against anybody. We are open to anybody. *...(Interruptions)...* Sir, I need your protection. I want to submit a few things. For the last two days in the Lok Sabha and also today, here, certain things are going on. It is about Tamil Nadu. Let me first clarify it. In our society, that means in my Odia society, Lord Jagannath is above everybody. The King of Puri, who really is not a king, is a very philosopher kind of person. He is the living deity to all Odias and all Sanatanis. My King is married to the Queen of Kanchi. So, my mother is from Tamil Nadu. Sir, I am a son of Tamil Nadu's lady. It is a coincidence that here the issue has been raised by none other than one of the very respectable Members of this House, Dr. Kanimozhi. In the other House yesterday, there was an issue. *...(Interruptions)...* Yes, another Kanimozhi; she is a very respectable Member. Personally, both of them are my sisters. I am Odia; I am a believer of Lord Jagannath. In my civilisation and my society, mother and sisters are above everything. If I hurt anybody in any of my words, again I beg for apology. I will beg for an apology a hundred times. There is no prestige issue from my side. But you have to face the truth. इसीलिए मैं कभी-कभी घबराता हूँ, मैंने जो पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। 1968 में हम कहाँ थे? Where were we? Who appointed the Kothari Commission? What was the recommendation of the Kothari Commission? Dr. Kanimozhi was quoting it. Yes, we have accepted certain things. Let me read out a letter by Chief Secretary of Tamil Nadu. Let me read it out. The date is 15th March, 2024. We have never stopped anybody's funds. I can show you the allocation and what we have given to Tamil Nadu. I can show you later on. It was on 15th March, exactly a year ago. There are 15 days left for the closure of the financial year. For negotiations, I have written five letters from my side to hon. Chief Minister of Tamil Nadu. There are, I was counting, 13 communications by the Government of India to their counterparts at my level -- to hon. Chief Minister, to hon. Education Minister, to the respective Department Heads and to the Chief Secretary. The Chief Secretary of Tamil Nadu, on 15th March, 2024, just a year ago, wrote a letter. Subject is: Establishing PM SHRI schools in Tamil Nadu. The State of Tamil Nadu has always been committed to provide enhanced quality education to its students by

implementing many impactful initiatives in school education sector. I also appreciate that. It is in one of my latest letters to show how I see Tamil Nadu. I agree with some of the arguments put forward by Tamil Nadu. What is Tamil Nadu? I don't have any confusion. At least, this Government has never had confusion to portray what Tamil Nadu is. सर, तमिलनाडु में काशी-तमिल संगमम का आयोजन करने वाले visionary leader श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं। इसके साथ ही, तमिल-सौराष्ट्र संगमम का आयोजन करने वाले visionary leader श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं। सर, नरेन्द्र मोदी जी ने इतना ही नहीं किया। I am very happy and delighted to listen Dr. Kanimozhi when she quoted Tirukkural on education. I am grateful to you, Dr. Kanimozhi. You have rightly enlightened this House by mentioning Tirukkural. What is our commitment to Tirukkural? Prime Minister Modi has given instructions to all of us to translate Tirukkural to different Indian languages and different foreign languages. Inside the country and outside the country, many times, Prime Minister Modi has mentioned that Tamil language is an ancient language of human civilization. We believe that. I am personally committed to my Prime Minister's vision. This is our commitment to Tamil language. Tamil language is nobody's monopoly. Nobody can teach us lesson how to behave with women. What they, who are saying this, had done to the great leader Jayalalithaa on the floor of the House of Tamil Nadu? ...*(Interruptions)*... History will never forget that. They cannot teach us lesson. ...*(Interruptions)*... They cannot teach us lesson. They should have patience to listen that. What had they done to the great leader Jayalalithaa on the floor of the House of Tamil Nadu? ...*(Interruptions)*... All people are witness to that. ...*(Interruptions)*.... Mr. Deputy Chairman, Sir, we don't need anybody's certificate on whether we are committed to Tamil language or not. We are committed to Tamil language. My Prime Minister is committed to Tamil language. ...*(Interruptions)*... Let me cite another example. ...*(Interruptions)*... Prime Minister, Shri Narendra Modi is the only leader in this country who has envisioned an International Centre. ...*(Interruptions)*... It is an International Centre on Thiruvalluvar at Singapore, the first of its kind in this country. ...*(Interruptions)*... Mr. Deputy Chairman, Sir, truth always enlightens many people and pinches few people. ...*(Interruptions)*... How can we help it? ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सच तो कड़वा होता है। ...(**व्यवधान**)... सच तो कड़वा होता है। ...(**व्यवधान**)... यह कैसे भुलाया जा सकता है? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order? *...(Interruptions)...* Under which Rule?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it is Rule 240. It says: "The Chairman, after having called the attention of the..."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I got it.

SHRI TIRUCHI SIVA: Whichever is irrelevant, I leave it to you. Kindly expunge it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. *...(Interruptions)...*

SHRI TIRUCHI SIVA: The subject on which he is speaking about is totally irrelevant.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister would continue. *...(Interruptions)...*

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, I leave it to your wisdom. *...(Interruptions)...* I leave it to your wisdom. I do not have any prestige issue on anything. I leave it to your wisdom but truth is always painful. *...(Interruptions)...* Those who are staying in a glass house, they should not...*...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. *...(Interruptions)...* Please continue. *...(Interruptions)...*

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, I am in social life since my school days. *...(Interruptions)...* I am a student of public policy. I track politics, I read newspaper. *...(Interruptions)...* I read newspaper. Nobody had the right to outrage the modesty of a senior leader like Jayalalithaa*ji*. *...(Interruptions)...* Truth is truth, you have to accept that. *...(Interruptions)...* Dr. John Brittas, you are from Kerala. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, please take your seat. *...(Interruptions)...* You have already spoken. Please take your seat.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, in one of my letters to hon. Chief Minister of Tamil Nadu, where I had appealed again and again that he should join NEP, he should join PM SHRI -- a letter was written on the 25th February of this year -- how do I portray Tamil Nadu, what my feeling is, what my understanding of Tamil Nadu is! In

para 8 of my letter, I have written: "Tamil Nadu has always been torchbearer of social and educational progress pioneering some of the most transformative reforms in India." That I believe, that my Government believes. "It has been at the forefront of movement that have shaped modern education, uplifted marginalized communities and fostered an inclusive learning environment." This is our understanding of Tamil Nadu. This is my commitment. Coming to the point, the Chief Secretary of Tamil Nadu has written, "With reference to your letter dated..., I would like to inform that the State of Tamil Nadu is very keen to sign the MoU for establishing the PM SHRI school in the State." Sir, these are very clear terms. Very clear! I am reading it out. ...*(Interruptions)*... I am reading it out again further. Do not disturb me. My dear Dr. Brittas, you are creating problem, keep quiet. ...*(Interruptions)*... "In this regard, a State level committee headed by School Education Secretary has been constituted. Based on the recommendation of the committee, the MoU for establishing PM SHRI school will be signed by the State before the beginning of the next academic year 2024-25." In a way, the Ministry of Education -- elections were there in those days — has well publicized this information in the public domain. I say, what your problem is, what your agitation is! 1963 and three-language formula are something different. I quote, what is there in NEP, 2020, what is the interpretation of mother tongue? Everybody appreciated it. Somebody said: "You have not consulted us, it was never discussed in the Parliament." In those days, Corona was there. Mr. Deputy Chairman, Sir, I think, Dr. Kasturirangan is above everybody, above all political colours. He is an integrated person. He is a *Gangotri*. When I saw him, I said: "Sir, you are the *Gangotri* of civilization. You are the epicentre of the knowledge of this country. What had he done? उन्होंने शायद संविधान सभा के उपरांत सभी वर्गों के साथ, सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ, सभी समाजिक वर्गों के साथ और सभी राज्यों के साथ चर्चा करके एक व्यापक परामर्श के आधार पर, एक consultative mechanism के आधार पर NEP, 2020 बनाया। What was their recommendation? यह कहा गया कि बालक-बालिका जिस भाषा को सुनता है और पहले बोलता है, अगर वह उसी भाषा में पढ़ता है और लिखता है, तब उसकी critical thinking बढ़ेगी, उसकी innovation capacity बढ़ेगी, उसकी routineness बढ़ेगी। इसीलिए it should be Reading Level-1, R1. इसको पहला language कहा गया।

सर, दूसरे language को परिभाषित करते हुए कहा, "Language used as medium of instruction, and in which literacy is first attained. Preferably, the familiar language of the students, it should be the language most familiar to the students, often mother tongue or home language." यह R1 है, यह पहला language है। Then, R2, "Any other language including English." Now, R3, "Any other language that is not R1 or R2." Nowhere, it is Hindi or Sanskrit. With utmost responsibility on the floor of the House, I can inform this country that in NEP, no other language has been imposed on

anybody. This is an open thing. Those who are saying this, I respect that sentiment. Personally, I respect the cultural sensitivity of every part of the country. It has to be respected. But, things have been changed. When Shrimati Sudha Murty was speaking, after her speech, she came to bless me. I asked her, "*Amma*, how many languages do you know?" She said that by birth, she is a Kannada, by profession, she learns English and by practice, she learns Sanskrit, Hindi and also Odiya, also Marathi, and also Telugu. What is wrong in that? Who is imposing on Shrimati Sudha Murty that she must learn these languages. Nobody is imposing anything on anyone. It is a democratic society and the order of the time is that there has to be multilingualism.

DR. M. THAMBIDURAI: It is the Congress who imposed it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Let him speak. ...*(Interruptions)*... The hon. Minister will speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, let me now come to one of the senior leaders of our country, the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu. What are his views on this language? Why to restrict to just three languages? We are talking about two languages, three languages. What is he saying? Shri Naidu is a very futuristic and progressive person. His statement is, "Why restrict to just three languages? We will promote as many languages as possible. In Andhra Pradesh, we have a plan to promote our ten languages, including global language, as part of the academic programmes." सर, आने वाले दिनों में दुनिया की संभावनाओं को देखते हुए चंद्र बाबू जी कहते हैं कि मैं पांच विदेशी भाषा पढ़ाऊंगा। किसी राज्य को मनाही नहीं है। आज हमारा व्यवसाय वैश्विक स्तर पर हो गया है।

सर, टेक्नोलॉजी में पारंगत जर्मनी को इंग्लिश नहीं आती है, जापान को इंग्लिश नहीं आती है, चीन को मंदारिन आती है, इज़राइल को हिब्रू आती है। अगर हमारे देश के नौजवान विश्व की पांच भाषा सीखें, देश की पांच भाषा सीखें, उसके लिए मैं किसी को बाध्य क्यों करूंगा? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी मैं किसी की कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं डीएमके के मित्रों की वेदना को समझ सकता हूँ। उनको उन दिनों में जिन्होंने ठगा, अभी भी उनको वही पीड़ा ध्यान में आ रहा है। उनको लग रहा है कि अभी भी यह थ्री लैंग्वेज़ फॉर्मूला है। विश्व की आवश्यकता को देखते हुए हम लोगों ने यह थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बनाया है। यह जो कंसल्टेंसी हुआ है, वह आने वाले दिनों में भी चर्चा के आधार पर ही होगा। कोई किसी के ऊपर थोप नहीं सकता है।

उपसभापति जी, मैं आपके सामने कुछ और भी तथ्य रखना चाहूँगा। Those who are putting this argument, "We will have only two language", what is happening in that

State? I will give three examples. In Tamil Nadu, if you go by the last six years' statistics--let me put a few bare facts--in 2018-19, the total number of Tamil medium students in Government schools of Tamil Nadu and aided schools of Tamil Nadu was 65.87 lakh, and English medium students were 55.18 lakhs. That means 54 per cent of Tamil language and 45 per cent of English language. There were two languages. Okay, accepted! In 2023-24, what is the scenario? It is 46.82 lakhs in Tamil language. From 65 lakhs, it is now 46 lakhs. In English language, it is 55 lakhs to 82 lakhs. That means 63.4 per cent is English and 36.3 per cent is Tamil. I am proud of Tamil language. Tamil language is an ancient language of civilization as it is put forth by my Prime Minister. Tamil language is being strengthened; that is what is there in NEP. What is your understanding of NEP? What is your opposition to NEP? NEP is advocating that in Tamil Nadu, up to class 5, the medium of instruction should be Tamil. This is in NEP. Sir, I was a witness to the historic function when the foundation stone of this new building was laid. You were there and were part of that programme. The Prime Minister quoted, "India is the mother of Democracy". भारत प्रजातंत्र की जननी है। ...(**व्यवधान**)... अच्छा! जिसको भारत के गौरव के बारे में गर्व ही नहीं है, उससे मैं क्षमा मांगूंगा और क्या कर पाऊंगा? इस विद्वान से मैं क्षमा ही मांगूंगा, यह देश उनसे मिलकर क्षमा मांगे। हे प्रभु, हे महाप्रभु जगन्नाथ, इनको सद्बुद्धि दो। यह प्रधान मंत्री जी ने क्वोट किया। यह क्वोट कहाँ का था? यह तमिलनाडु का क्वोट था। Today, Brihadeeswara is here because of the fundamental understanding of the Tamil language as it is an ancient language of civilisation. We are promoting Sengol; it is the understanding of the Tamil language. It is our civilisation. We are committed to do that. Today, what is the scenario? Even I am not against English. Those students, who have to go to the international market, must learn and understand English. We have to compete globally. But, for research, for critical understanding, mother tongue is primary. That is the primary precondition of National Education Policy. Up to 5th class, mother-tongue oriented education is a must. In Tamil Nadu, it is Tamil. In Andhra, it is Telugu. In Odisha, it is Odia. In Madhya Pradesh, it is Hindi. And up to eighth, it is 'preferably'. Then after eighth, it is up to the choice of the student. Sir, I simply fail to understand--I have not yet authenticated, I am not so sure about the fact, but it is tentatively a right fact--in Tamil Nadu, those who are advocating only two-language formula, in their own Government schools, Tamil language is declining. The colonial language is increasing. This is an alarming thing. No more Brihadeeswara *...(Interruptions)...* Nobody is thrusting upon you. Don't create fear psychosis. *...(Interruptions)...* Don't create fear psychosis. *...(Interruptions)...* Sir, they have their reservation. Okay! But what is the fact? In Tamil Nadu, there are 1,500 minority schools run by Government, Government-aided and private. Out of those 1,500 schools, in 900 schools, Telugu is

a language under Three-Language Formula. Urdu is in 350 schools under Three-Language Formula. And, in rest of the schools, Kannada, Malayalam, all languages are there. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. let him speak. ...(*Interruptions*)... Tiruchi*ji*, it will not go on record.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, in Tamil Nadu, there is much appreciation. Sir, I met a girl at Kharagpur Research Park. She is a young girl from Transport Nagar of Tamil Nadu. That lorry point! Namakkal. I met a young promising girl, young scientist from Namakkal. She is a daughter of a small shopkeeper. She is doing research in Biotechnology Department in Kharagpur, IIT. What is she researching? She is researching about vegan meat. She wants to be an entrepreneur. She was good at Hindi. Out of my curiosity, I asked her, '*Beta*, you are a girl from Tamil Nadu. How are you so good at Hindi? She told me, "By design, by conscious approach, I took Hindi because I want to be an entrepreneur. I want to create a business model for Pan-India level." This is the new Tamil Nadu. This is the aspiration. There are 1,460 CBSE affiliated schools in Tamil Nadu. Out of that, Tamil is taught in 1,411 schools, English is taught in all 1,460 schools, and Hindi is taught in 774 schools, given permission by the Tamil Nadu Government. This is the fact. You may live in your own cell. ...(*Interruptions*)... You may live in your own cell, but this is the reality in Tamil Nadu today. This is the new aspiration. You can't stop any aspirational thing for the youngsters of the country. I don't have any intention to offend any individual. As I said, all the colleagues are my respected colleagues. But it is a fact. What do you mean by NEP? NEP is meant for mother-tongue based education. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली शर्त मातृभाषा आधारित शिक्षा है। स्किल के बारे में चर्चा की गई है। लोगों ने सुझाव दिया है कि 9^{th}, 10^{th}, 11^{th} and 12^{th} में स्किल करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई text book में 6^{th} standard से skill orientation बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। Innovation, entrepreneurship, critical thinking, rootedness, these are the features of New Education Policy. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I request the hon. Minister to...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... You have already raised the point of order.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: I appeal to my colleague from Tamil Nadu. Let them abuse me personally. वे मेरा साथ कितना भी गाली-गलौज करें। आज तमिलनाडु के आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री NEP का अर्थ - पीएम श्री स्कूल में संस्कृत और हिन्दी पढ़ाने की शर्त रख रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Tiruchi Siva*ji*, please do not go by rules. I will also quote. ...(*Interruptions*)... Please, I have already given you the opportunity. Let him speak.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, किसी विषय पर हमारी कोई शर्त नहीं है। भारत को विकसित करना है, भारत को नई ऊंचाई तक ले जाना है। तमिलनाडु हमारे देश के ...(**व्यवधान**)... growth है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already allowed that.

श्री धर्मेंद्र प्रधानः हमारा दायित्व है कि तमिलनाडु के नेतृत्व में हमें देश को आगे ले जाना है। You can call me a fool, but you cannot make a fool of all the Tamil Nadu people all the time. You can abuse me. You can scold me. You can name me in any derogatory word. I am ready to accept it. But, for heaven's sake, for God's sake, don't devour the opportunity for the youngsters of Tamil Nadu. Don't be so semitic. Don't be so small. ...*(Interruptions)*... Please come out of the old ideas. ...*(Interruptions)*... Please come out of old ideas. We all have to come together and build a new country. Thank you, Mr. Chairman, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Siva, please quote me the rule. However, it is already over. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: It is Rule 241 — Personal Explanation. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please read this rule. It says ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Let me read it out, Sir. It says: A Member or a Minister may, with the permission of the Chair, make a personal explanation, although there is no question before the Council. So, I want to make a personal explanation...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please wait. ...*(Interruptions)*... But, in this case, no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise. You please read

it fully. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*... The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Wednesday, the 12th March, 2025.

The House then adjourned at thirty-one minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 12th March 2025